

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 101 ] No. 101] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2000/माघ 27, 1921 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2000/MAGHA 27, 1921

#### महानिदेशक ( रक्षोपाय ) का कार्यालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2000

विषय: -- भारत में सफेद/पीले फास्फोरस के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच-अन्तिम निष्कर्ष।

सा.का.नि. 126( अ ). — सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान तथा निर्धारण) नियमावली 1997 के संदर्भ में।

#### क. प्रक्रिया

1. भारत में सफेद/पीले फास्फोरस के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच आरम्भ करने का नोटिस 15-9-99 को जारी किया गया था तथा 15-9-99 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था। नोटिस की एक प्रति निम्निलिखित सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को प्रेपित की गई थी:—

#### घरेलू उत्पादक

- (1) यूनाइटेड फासफोरस लिमिटेड, मुम्बई, (यू पी एल)
- (II) सर्च केम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (एस सी आई एल), मुम्बई
- (iii) फास्फोरस एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (पी ए सी टी), कोचीन
- (IV) स्टार केमिकल्स (बम्बई) लिमिटेड, मुम्बई, (स्टार)
- (v) एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई, (एक्सेल)

#### आयातक तथा प्रयोगकर्ता उद्योग

- (1) श्री मजेन्था केमिकल (पी) लिमिटेड, तलिमनाड
- (n) क्लाइन केमिकल्स प्राइवेट लि., मुम्बई
- (in) नेकां केमिकल्स प्राईवेट लि., मुम्बई
- (IV) वाटसल आर्गेनिक्स लि., हैदराबाद

450 GI/2000

(V)	आनन ड्रांस एण्ड केमिकल्स लि., भावनगर
(vi)	सबीरो आर्गैनिक्स गुजरात लि., मुम्बई
(Vii)	एस टी एस केमिकल्स लि., मुम्बई
(Viii)	केमिनोवा. मुम्बई
(ix)	एक्वाफार्म केमिकल्स कम्पनी लि., पुणे
(X)	कल्पतरू केमिकल्स, तमिलनाडु
(Xi)	मेटल पाउडर कम्पनी लि. मदुरई
(Xii)	प्राची पोली प्रोडक्ट्स लि., मुम्ब <b>ई</b>

#### निर्यातक

(1)	चाइना नेशनल एण्ड कैमिकल्स आई/ई कीपरिशन, चीन
ZΩ	

- शी हिंग (चीन) डेवलपमेट लि , हॉंग कॉंग (11)
- (iii) वृहन केमिकल्स आई/ई कार्पोरेशन, चीन
- (iV)डाल्टसंस लि., हॉंग-कॉंग
- युत्रन प्राविन्शियल केमिकल्स आई/ई कार्पोरेशन, चीन  $\langle V \rangle$
- जिआगमेन केमिकल्स आई/ई कम्पनी आफ गुआग डॉंग चीन, चीन (N)
- कुनमिंग इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन, चीन (Vii)
- चाइना हूनान केमिकल्स इस्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन, चीन (Viii)
- एफ एम सी कार्पोरेशन, यू. एस. ए. (ix)
- मोनसेटो कम्पनी, यू. एस ए. (x)
- निप्पो केमिकल इंडस्ट्रियल कम्पनी लि . जापान (Xi)
- रासा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान (Xii)
- कज-एनएलएल खिमप्रोयोक्त, कजाकस्तान (Xiii)
- एल्फ एटोकेम एस ए. फ्रांस (XIV)
- होएक्ट एक्टिंग से लशाक्ट जर्मनी (XX)
- ई मके, जर्मनी (XX)
- एल्ब्राइट एण्ड विल्सन लि., युके (XVii)
- होएचर होलैंड एच वी., नींदरलैंड (XVIII)

( डाल्ट्सस लिमिटेड हाँग काँग तथा निप्पन केमिकल इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड, जापान को मेजे गए नोटिस डाक प्राधिकारियो द्वारा अवितरित वापस लौटाये गए ।)

#### संगठन

- 2. नोटिस की एक प्रति प्रार्थना-पत्र तथा प्रश्नावली सिंहत निर्यातक देशों की सरकारों को भी उनके नई दिल्ली में स्थित उच्चायोगों/ राजदूतावासों यथा बल्गेरिया, चीन, चीनी ताइपेई, हॉंगकॉंग, जर्मनी, जापान, कोरिया डी पी.आर, नीटरलँड्स , यू.के. तथा यू.एस.ए. के माध्यम से मिजवा दी गई थी ।
- 3. सभी झात घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों तथा आयातकों को प्रश्नावलियाँ भी उसी दिन भिजवा दी गईं थी जिनसे कहा गया था कि वे अपना प्रत्युत्तर 25-10-99 तक प्रस्तुत कर दें ।
- 4. मेसर्स गुइयाँग फास्फोरस केमिकल्स जनरल फैक्ट्री ने अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पीपुल रिपब्लिक आफ चाइना, नई दिल्ली के आर्थिक तथा वाणिज्य काउन्सेलर के कार्यालय के माध्यम से 30 नवम्बर. 1999 तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया था । उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए तथा निर्धारित समय में जाँच पूरा करने की आवश्यकता को देखते हुए 9 नवम्बर, 1999 तक के समय विस्तार की अनुमति दे दी गई थी तथा उनको तदनुसार सूचित कर दिया गया था । उन्हें यह मी सूचित कर दिया गया था कि उनको इच्छुक पक्ष के रूप में रिकार्ड में ले लिया गया है तथा वे सार्वजनिक सुनवाई में सम्मिलित हो सकते हैं ।
- 5 दिनांक 15-9-99 के नोटिस तथा प्रश्नावली के उत्तर निम्नलिखित पक्षों द्वारा प्राप्त हुए थे 🕒

#### घरेलू उत्पादक

- (i) यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, मुम्बई
- (ii) सर्च केंम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई
- (iii) फास्फोरस एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि , कोचीन
- (iv) स्टार केमिकल्स (बम्बई) लिमिटेड, मुम्बई
- (V) एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई

यू. पी. एल. तथा एस. सी आई. एल ने एक साझा उत्तर प्रेषित किया । स्टार केमिकल्स (बम्बई) लिमिटेड, मुम्बई ने एक आयातक के रूप में उत्तर प्रस्तुत किया। एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई ने जवाब प्रेषित किया है लेकिन उन्हों मिजवाई गई प्रश्नावली से संबंधित उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया ।

## आयातक तथा प्रयोगकर्ता उद्योग

- (i) श्री मजेन्था केमिकल (प्रा.) लि , तमिलनाडु
- (ii) क्लाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई
- (iii) नेकां केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई
- (iV) वाटसल आर्गेनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
- (V) सबीरो आर्गैनिक्स गुजरात लिमिटेड, मुम्बई
- (vi) एस टी एस केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई
- (Vii) केंमिनोवा, मु**म्बई**
- (Viii) एक्वा फार्म कॅमिकल कम्पनी लिमिटेड, पुणे

- (ix) कल्पतरू केमिकल्स, तमिलनाडु
- (X) मेटल पाउडर कम्पनी लिमिटेड, मदुरई
- (Xi) प्राची पोली प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मुम्बई

#### संगठन

- इंडियन केमिकल्स मैन्यूफैक्वरर्स एसोसिएशन, मुम्बई
- ं नोटिस का प्रत्युत्तर निम्नलिखित पक्षों ने भी प्रस्तुत किया है जिनमें आयातक/प्रयोगकर्ता उद्योग, संगठन तथा निर्यातक सम्मिलित हैं -
- (i) शा वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई- 600 001.
- (ii) रालकेम लिमिटेड, सिकन्दराबाद- 500 003.
- (iii) नागार्जुन एग्रीकेम लि०. **हैदराबा**द-500 082
- (iv) भागीरथ केमिकल्स एण्ड एण्डस्ट्रीज लि०, हैदराबाद- 500 034.
- (V) नावार्टिस इंडिया लि०, मुम्बई- 400 020
- (vi) भाष्कर एग्रो केमिकल्स लिं हैदराबाद- 500 004.
- (Vii) इंडिया पेस्टीसाइड्स लि०, बरेली- 243001
- (Viii) वेंकटेश्वर पंस्टीसाइड्स एण्ड एलाइड केमिकल्स प्रा.लि., हैदराबाद
- (ix) राइम आर्गेनिक्स एण्ड केमिकल्स लि०, हैदराबाद- 500 020.
- (x) मित्सु लिं०, मुम्बई- 400 059
- (xi) डी-नासिल काप प्रोटेक्शन लि॰, मुम्बई- 400 079
- (xii) पायनियर प्रोडक्ट्स लि०, नई दिल्ली- 110 041
- (Xiii) वेन्टेक इण्डस्ट्री लिंo, हैदराबाद- 500 016
- (XIV) मेघमणि आर्गैनिक्स लि॰, अहमदाबाद- 382 445
- (xv) कृष्णा ऐण्टी आक्सीडेन्ट्स प्रा.लि., मुम्बई- 400 103
- (xvi) लुबिजोल इंडिया लि॰. मुम्बई- 400 025
- (XVII) अनिल पेस्टिसाइड्स लि॰, पचकुला- 134 113
- (XVIII) एम.आर.फार्मा प्रा.लि , मुस्बई- 400 004
- (xix) रेन्कल केमिकल्स (इंडिया) लि०. न्यू बाम्बे- 400 705
- (xx) एच.पी.एम. इंडस्ट्रीज लि॰, नई दिल्ली- 110 005
- (XXI) ई.आई डी <sup>°</sup>पैरी (इंडिया) लि०, चैन्नई- 600 001
- (XXII) ट्राइ-केम इण्टरप्राइसोज (बाम्बे) प्रा.लि , बाम्बे- 400 016
- (XXIII) वैमन इण्डस्ट्रियल केमिकल्स लिंा, बाम्बे- 400 062
- (xxiv) सुदर्शन केमिकल इण्डसट्रीज लिं० पुणे- 410001
- (xxv) बेयर इंडिया लिंः, मुन्बई- 400 076
- (XXVI) घरदा केमिकल्स लि॰, मुम्बई- 400 050

	2(3)
(XXViii)	रवी आर्गैनिक्स लि॰, नई दिल्ली- 110 005
(XXiX)	फीकाम आर्गेनिक, मुम्बई- 400 021
(xxx)	सूमेक्स केमिकल्स लि॰, मुम्बई- 400 018
(XXXi)	अलकेमी आर्गैनिक्स लि॰, मुम्बई- 400 080
(xxxii)	स्पेक्ट्रम ईथर्स लि॰, मुम्बई- 400 055
(XXXiii)	नार्दर्न मिनरल्स लि॰, नई दिल्ली- 110005
(xxxiv)	राजस्थान इन्सेक्टी साइड्स एण्ड फर्टीलाइजर क.प्रा.लि., नई दिल्ली
(XXXV)	धनुका पेस्टीसाइड्स लि॰. नई दिल्ली- 110 005
(XXXVI)	रैलीज इंडिया लि॰. मुम्बई- 400 001
(XXXVii)	एग्रेवो इंडिया लि॰, मुम्बई- 400 093
(XXXViii)	सन्ध्या आर्गैनिक्स केमिकल्स प्रा.लि., मुम्बई- 400057
(XXXIX)	सायनामिड एग्रो लि॰, मुम्बई- 400 020
(XI)	गुजरात सुपरफास्फेट इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लि , अहमदाबाद- 380 002
(Xlı)	पेस्टीसाइंड्स इंडिया लि., उदयपुर- 313 001
(xlii)	दि आल इंडिया चैम्बर्स आफ मैच इण्डस्ट्रीज, सिवाकाशी- 626123
(xlii)	जयश्री व्यापार निमिटेड, राजकोट, गुजरात
(Xliii)	दि इंडियन स्मेल्टिंग एण्ड रिफाइनिंग कं लि., मुम्बई -400 078
(xliv)	दि इंडियन स्मेल्टिंग एण्ड रिफाइनिंग कं.लि , मुम्बई- 400 078
(xiv)	तिरूपति कोल एण्ड कोक सप्लायर्स, धनबाद (बिहार)
(xlvi)	कुंवर जी रामजी एण्ड कं , बाम्बे- 400 086
(xlvii)	शिवालिक रसायन लि., नई दिल्ली- 110019
(xlviii)	गिझो जिन्शा येलो फास्फोरस आई/ई कार्प. चीन
(XhX)	वाक हार्ड्ट लि . मुम्बई - 400018
(1)	निसर्ग फार्माकेम, भावनगर- 364 002
(h)	हिन्दुस्तान कोल मूवर्स प्रा लि., जामनगर- 361 001
(lii)	एम्को पेस्टीसाइड्स लि . मुम्बई- 400 055
(liir)	फेंडरेशन आफ कामराजार डिस्ट्रिक्ट वैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सत्तूर
(liv)	इप्का लेबोरेट्रीज लि॰, कान्डीवली (वेस्ट), मुम्बई- 400 067
(IV)	मंगलम ड्रास एण्ड आगैंनिक्स लि., मुम्बई- 400 002
lvı)	ग्रेफाइट इंडिया लि., कलकत्ता- 700 016
(ivi)	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन, मोपाल- 462 011
lViii)	अरलैक्स लि . मुम्बई- 400 001
lix)	रैनबैक्सी फाइन केमिकल्स लि . मुम्बई- 400 001
ix)	गिझोउ प्राविसियल केमिकल्स आई/ई कार्प०.चीन- 550001
ixi)	आल इण्डिया वैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, दूटीकोरिन-628 001
(XII)	युत्रम मिनमेटल्स एण्ड केमिकल्स आई/ई ग्रुप कार्प., चीन
lxin)	तमिलनाडु चैम्बर आफ् कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज , मदुरई- 625 009
lxiv)	कान्फीडरेशन आफं इंडिया इण्डस्ट्री (सी.आई.आई.) अहमदाबाद- 380 006

(lxv)	बिमोल इण्टरनेशनल लि., बगबान, बैंकाक
(IXVI)	साबर मिनरल, हिमतनगर डिस्ट्रिक्ट , एस.के. 383 001
(IXVII)	इंडियन काप प्रोटेक्शन एसोसियेशन, मुम्बई- 400 098
(Ixvai)	अंकलेश्वर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, अंकलेश्वर- 393 002
(lxix)	दि सत्तूर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज,सत्तूर- 626 203
(lxx)	सत्तूर मर्चेन्ट्स एण्ड इण्डस्ट्रियलिस्ट्स एसोसियेशन, सत्तूर- 626 203
(lxxi)	नादर्न इंडिया पेस्टीसाइड्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन,दिल्ली- 110 033
(lxxii)	पेस्टीसाइड्स एसोसियेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली- 110 001
(lXXiii)	हरियाणा पेस्टीसाइड्स मैन्यूफेक्चरर्स एसोसियेशन, नई दिल्ली-110 005
(IXXIV)	पेस्टीसाइड्स मैन्यूफैक्वरर्स एण्ड फार्मुलेटर्स एसोसियेशन आफ इंडिया. मुम्बई
(VXXI)	साउथ इंग्डिया मैच मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, कोविलपट्टी- 628 501
(IXXVI)	दि साउथ इंडिया स्वदेशी मैच मैन्यूफैक्वरर्स एसोसियेशन, सत्तूर
(livxxl)	गुजरात पेस्टीसाइड्स फार्मुलेटर्स ऐसोसिऐशन, अहमदाबाद- 389 009
(lxxVni)	रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट कार्टज मैच मैन्यूफैक्वरर्स ऐसोसियेशन, सतूर- 626 203
(lxxix)	एसोसियेशन आफ स्माल एण्ड मीडियम केमिकल मैन्यूफैक्वरर्स, मुम्बई
(IXXX)	आल इंडिया काटेज मैच इण्डस्ट्री फेंडरेशन, सतूर- 626 203
(IXXXI)	गियाग फास्फोरस केमिकल्स जनरल फैक्ट्री, चीन

7 जांच के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए अधिकारियों के एक दल ने घरेलू उत्पादकों, आयातकों और प्रयोगकर्ता उद्योगों के परिसरों का दौरा किया । जाँच के परिणामों को उन संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया गया था जिनके परिसरों का दौरा किया गया था और जाँच रिपोर्ट की एक प्रति को सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया था ।

8 सभी इच्छुक पक्षों की एक सार्वजनिक सुनवाई 23-12-99 को आयोजित की गयी थी जिसके लिए नोटिस 22-11-99 को प्रेषित किया गया था । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान इच्छुक पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने द्वारा दिए गए मौखिक दलीलों की लिखित प्रस्तुति 31-12-1999 तक दर्ज करायें तथा दूसरों द्वारा दर्ज कराए गए उत्तरों की प्रतियों को 3-1-2000 को प्राप्त करें और अपना खड़न. यदि कोई हो, तो 10-1-2000 तक प्रस्तुत कर दे । निम्नलिखित पक्षों ने सार्वजनिक सुनवाई में माग लिया :-

```
(i) यूनाइटेड फास्फोरस लि , मुम्बई
(ii) सर्च केम इण्डस्ट्रीज लि , मुम्बई
(iii) फास्फोरस एण्ड केमिकल्स बावणकोर लि , कोचिन
(iv) स्टार केमिकल्स ( बाम्बे ) लि , मुम्बई
(v) एक्सेल इण्डस्ट्रीज लि , मुम्बई
(vi) वाटसल आर्गेनिक्स लि , हैदराबाद
```

(vi) वाट्सल आगेनिक्स लि. हेंदराबाद(vii) संबोरो आगेनिक्स गुजरात लि , मुम्बई

(Viii) एस टी एस. केमिकल्स लि., मुम्बई

(IX) केमिनोआ, मुम्बई

(x)	लुब्रीजोल इंडिया लि., मुम्बई
(XI)	संध्या <sub>/</sub> आर्गेनिक केमिकल्स प्रा. लि., मु <b>म्ब</b> ई
(xii)	फेडरेशन आफ कमराजार डिस्ट्रिक्ट वैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सतूर
(Xiii)	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन, मोपाल
(xiv)	आल इंडिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, दूटीकोरन
(XV)	पेस्टीसाइड्स एसोसियेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली
(XVi)	रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट काटेज मैच मैन्यूफैक्वरर्स एसोसिएशन, सत्तूर
(XVii)	आल इंडिया काटेज मैच इंडस्ट्री फेंडरेशन, सत्तूर - 626203

(xviii) इम्बेसी आफ दि रिपब्लिक आफ बल्गेरिया, नई दिल्ली

(xix) इम्बैसी आफ पीपुल रिपब्लिक आफ चाइना, नई दिल्ली

(xx) यूरोपियन कमीशन, नई दिल्ली

# ख घरेलू उत्पादकों के दृष्टिकोण

- ३ (क) यूनाइटेड फास्फोरस लि / सर्वकेम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
- (i) यू पी.एल ने कानूनी तौर से अपनी सम्पूर्ण पीले फास्फोरस क्षमता को प्रवालन कारणों से एस.सी.आई एल को स्थानान्तरित कर दिया है और यू पी.एल, एस सी आई.एल की नियंत्रक कम्पनी के रूप में निरंतर कार्यरत हैं। एस.सी.आई.एल में यू पी एल के 53% की हिस्सेदारी के स्वामित्व के कारण एस.सी.आई एल., यू पी एल. की नियंत्रित एक कम्पनी है । यू पी एल और एस.सी.आई एल का प्रबंध नियंत्रण मी एक ही प्रमोटर ग्रुप के पास है । इसके अलावा, यू.पी एल 1996-97 तक भारत में स्वयं पीले फास्फोरस का उत्पादन कर रहा था और आज भी कर रहा है । यू पी एल की रुचि पीले फास्फोरस के उत्पादन में है क्योंकि इसकी सहायक कम्पनी इस महत्वपूर्ण सामग्री का उत्पादन कर रही है ।
- (ii) अपने विद्यमान 50 मेगावाट विद्युत सयंत्र की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य से यू.पी.एल द्वारा एस.सी आई.एल को बढाया गया था जो एक पूजी-प्रधान प्रस्थापना थी और यू.पी.एल. के प्राथमिक व्यावसायिक हितों की तुलना मे इसमें विमिन्न प्रकार के प्रचालन संबंधी और आर्थिक जोखिम भी हैं । इस विद्युत संयंत्र का उद्देश्य यू.पी.एल. और एस.सी.आई.एल. दोनों के विभिन्न संयंत्रों के लिए विद्युत की कैप्टिव आवश्यकता को पूरा करना था, किन्तु इससे भी अधिक विशेषकर अधिक विद्युत लगने वाले पीले कास्फोरस ( वाई.पी ) संयंत्र और क्लोरोकास्टिक संयंत्र के लिए था, जहाँ उत्पादन लागत की 50% से अधिक लागत विद्युत की है । इन विद्युत प्रधान संयंत्रों को न्यूनतम लागत पर विद्युत वितरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पीले फास्फोरस सयंत्र को यू.पी.एल. से एस सी आई एल को कानूनी तौर से स्थानान्तरित करने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया था। इस समय ये दोनों संयंत्र एस झी आई एल के विद्युत सयंत्र के बगल में एक ही स्थान पर स्थित है ।
- (iii) एस सी आई.एल., विद्युत शक्ति का उत्पादन यू पी एल तथा एस सी.आई.एल द्वारा कैप्टिव उपमोग के लिए करता है और अन्य उत्पादन के अधिकाश माग का विपणन मुख्यतः स्थानीय बाजार में करता है । यह पीले फास्फोरस और क्लोरीन गैस के उत्पादन के एक माग का उपयोग फास्फोरस ट्राईक्लोराइड (पी.टी.सी ) के विनिर्माण के लिए करता है जो कृषि रसायन/ टेक्निकल के लिए एक मध्यस्थ है । पुन. पी.टी.सी. का आंशिक

उपयोग अनुवर्ती उत्पादों जैसे फास्फोरस आक्सीक्लोराइड ( पी.ओ.सी ) एच ई.डी.पी. और फास्फोरस पेन्टा क्लोराइड ( पी.पी.सी.) के विनिर्माण के लिए किया जाता है । एस.सी.आई.एल., पी.टी.सी, पी.ओ.सी, एच.ई.डी.पी. और पी.पी.सी. की बिकी स्थानीय और निर्यात बाजार दोनों में कर रहा है ।

- (iv) यू.पी.एल., कृषि रसायन उद्योग जैसे एग्रोकेमिकल फार्मुलेशन्स, एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स, एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स, एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स, एग्रोकेमिकल इण्टरमीडिएट्स तथा औद्योगिक रसायनों से संबंधित उत्पादों की विस्तृत श्रेणी के विनिर्माण में लगी हुई हैं । एस.सी.आई.एल , यू.पी.एल को एकीकृत बनाने वाली इकाई है । मूल कच्चे माल से औद्योगिक बाजार के लिए कृषि रसायन टेक्निकल और उपमोक्ता बाजार हेतु कृषि रसायन फार्मुलेशन के उत्पादन के लिए मारत में पूर्णतः एकीकृत सुविधा वाली अपने तरह की अकेली कम्पनी में यू.पी.एल और एस.सी.आई.एल. ही सम्मिलत है ।
- (v) पीले/सफेद फास्फोरस के उत्पादन के लिए राक फास्फेट, कोक और सिलिका मुख्य कच्चा माल है। पीले फास्फोरस के विनिर्माण की प्रक्रिया लगभग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोथर्मल रूट द्वारा सिलिका और कोक की उपस्थिति में राक फास्फेट का फास्फोरस में बदलना सिम्मिलित है। इण्डोथर्मिक प्रतिक्रिया के कारण, पीले फास्फोरस के विनिर्माण के लिए यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊर्जा प्रधान प्रक्रिया है। विद्युत ऊर्जा द्वारा उत्पादित उष्मा के माध्यम से इस ऊर्जा की उपलब्ध कराया जाता है।
- (vi) मारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित पीले फास्फोरस और मारत में आयातित फास्फोरस में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है । मारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित पीले फास्फोरस की तुलना विश्वमर में उत्पादित किसी के भी उत्पाद से की जा सकती है । उत्पादन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये बिना, उपमोक्ता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीले फास्फोरस और आयातित पीले फास्फोरस को अदल बदल कर उपमोग कर रहे हैं । यू.पी. एल./एस.सी.आई.एल. द्वारा उत्पादित पीला फास्फोरस और आयातित पीला फास्फोरस मौतिक विशेषताओ और रासायनिक संघटनों, उत्पाद विनिर्देश, विनिर्माण तकनीक, संयत्र और उपकरण, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य और उपयोग, विपणन और मूल्य निर्धारण, उपमोक्ता बोध की दृष्टि से एक समान हैं । दोनों तकनीकी और व्यापारिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य है । एस.सी.आई.एल. सहित मारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित पीला फास्फोरस, आयातित पीले फास्फोरस की तरह का पदार्थ है ।
- (vii) उनके द्वारा विनिर्मित पीले फास्फोरस के प्रमुख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उपमोक्ता प्लास्टीसाइजर और पालीमर योगात्मकों, लपट और अग्नि रोधकों, जल शुद्धिकरण एवं अभिक्रिया रसायनों आदि के विनिर्माता होने के अतिरिक्त कृषि रसायन माध्यमों जैसे फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, फास्फोरस पेन्टासल्फाइड आदि और कृषि रसायन देक्निकल जैसे मोनोकोटोफास, डी.डी.वी.पी., एसीफेट आदि के विनिर्माता हैं।
- (viii) गुजरात सरकार द्वारा विद्युत दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप, विद्युत की लागत में तीव्र वृद्धि के कारण आवेदकों के उत्पादन लागत में साल दर साल काफी वृद्धि हो गयी । वास्तव में, उत्पादन की परिवर्तनशील लागत स्वयं उस कीमत से महत्वपूर्ण रूप में अधिक थी जिसे कम्पनी बाजार में ला सकती थी और वह आयात के उतराई के समय की कीमत से पर्याप्त रूप में अधिक थी । कम्पनी ने वर्तमान एवं तत्कालीन विद्युत दर्शे पर संयंत्र की चलाना अव्यावहारिक पाया और इसके स्थान पर सस्ती विद्युत के उत्पादन के लिए उसने अपना कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया जो उत्पादन लागत को कम कर सकता था और जो पीले फास्फोरस के आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना करने का एकमान्न रास्ता है ।

- युनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड ने अपने पीले फास्फोरस के विनिर्माण में आगामी वर्षों में सकल 20 करोड़ रूपये का भारी विनिवेश किया जिसकी क्षमता 5000 मी.टन प्रतिवर्ष पीले फास्फोरस के उत्पादन की थी । फिर भी, आयातित पीले फास्फोरस के उतराई के समय की कीमत की तुलना में उत्पादन की महत्वपूर्ण उच्च लागत की दृष्टि से कम्पनी अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर सकी । विद्युत दर में कमिक वृद्धि के साथ कम्पनी ने राज्य विद्युत परिषद की विद्युत से संयत्र चलाना अव्यवहार्य पाया और अन्ततः इसने वियुत प्राप्त करने के लिए अपना वियुत संयत्र स्थापित करने का निर्णय लिया । वियुत संयत्र की स्थापना एस.सी.आई.एल. में की गयी और राज्य वियुत परिषद द्वारा अधिरोपित कटोर वियुत व्हीलिंग शर्तों के साथ-साथ एस.सी.आई.एल. से यू.पी.एल. को विद्युत आपूर्ति से संबंधित कंटिनाइयों की दृष्टि से, यू पी एल. ने अपने पीले फास्फोरस संयंत्र को भी एस.सी.आई.एल. को स्थानान्ति रित कर दिया । यू.पी.एल. की लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार इस संयंत्र को एस.सी.आई.एल. को इसके कुल वर्तमान मूल्य पर स्थानान्तरित किया गया था । इसलिए, एस.सी.आई.एल. ने यू.पी.एल से पीले फास्फोरस के 5000 टन प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिए सुविधाओं को प्राप्त जो गुजरात में भरूच जिले के अकलेश्वर में स्थित थी । एस.सी.आई.एल ने अब इन सुविधाओं को गुजरात में मरूच जिले के झगाडिया में स्थानान्तरित कर दिया है, और इस संयंत्र ने 14 जून 1999 से व्यावसायिक उत्पादन पुनः आरंग कर दिया है । इस विद्युत प्रधान प्रक्रिया के लिए न्यूनतम लागत पर विद्युत शक्ति की निर्बाध और लगातार आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एस.सी.आई.एल ने पीले फास्फोरस की सुविधाओं के वर्तमान स्थल के बगल में 1997-99 के दौरान क्रिमक रूप से संयुक्त चक्र 50 मेगावाट कैप्टिव विद्युत संयत्र की चालू किया है और बैकवर्ड इण्टीग्रेशन किया है । पीले फास्फोरस के लिए कुल लागत प्रतिस्पर्धा हेतु और विद्युत संग्रंत्र की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए एस सी.आई.एल. अपने विद्युत संग्रंत्र ईंधन को तरल नैच्या से प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करने के लिए भी प्रस्ताव कर रहा है । एस.सी.आई.एल., जिसके पास इस समय 4000 मी.टन प्रतिवर्ष की क्षमता है, 2500 मी.टन प्रति वर्ष की और अधिक वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में है और विस्तारीकरण कार्यक्रम के अंग के रूप में पीले फास्फोरस के 10,000 मी.टन प्रतिवर्ष की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक तथा पूरक सुविधाओं के साथ-साथ 3500 मी टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- (x) एस.सी.आई.एल. के पास पीले फास्फोरस का मंडार महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया है। पीले फास्फोरस संयत्र के 51% क्षमता उपयोग पर कार्य करने के बावजूद इसके कार्य करने के तीन महीने के अन्दर कम्पनी के पास 296 मी.टन की सूची जमा हो गयी है । यदि बिकी और उत्पादन का वर्तमान रुख जारी रहता है तो कम्पनी की सूची 880 मी.टन तक पहुंच जाएगी जो स्टांक में लगभग 111 दिन के स्टांक के बराबर होगा । स्पष्ट रूप से. कैप्टिब विद्युत से अपना कार्य पुनः आरंग करने के बावजूद कम्पनी अपने द्वारा उत्पादित माल के उपमोग और विपणन में किटिनाई का सामना कर रही है । प्रस्तुत किया गया है कि पीला फास्फोरस उच्च मूल्य वाला सामान है और कोई भी कम्पनी इतने ऊंचे स्तर की सूची का जमा होना सहन नहीं कर सकती है । इतने उच्च स्तर के मंडार को जमा रखना अत्यधिक किटन होगा और यदि बाजार में बिकी में वृद्धि नहीं होती है तो उत्पादन पुनःनियंत्रित करने के लिए इसे बाध्य होना पड़ेगा । यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूकि सभी अनुप्रवाही उत्पाद अपने उच्चतम क्षमता पर प्रचालन में है, इसलिए कम्पनी अपने कैप्टिव उपमोग को भी इसके वर्तमान स्तर से अधिक नहीं बढ़ा सकती है ।
- (xi) चूंकि पीले फास्फोरस की उतराई के समय की लागत, उत्पादन लागत से बहुत कम थी, इसलिए उत्पादन की लागत से बहुत कम कीमत पर बिकी करने के लिए कम्पनी को बाध्य होना पड़ा !

- (Xii) भारत में पील फास्फोरस का आयात आत्यतिक रूप में 1993-94 में 5350 मी टन से महत्वपूर्ण रूप में बढ़कर 1998-99 में 16504 मी टन हो गया है। उनके द्वारा उद्धृत की गयी आयात मात्रा 1998-99 के लिए डी.जी.सी.आई एण्ड एस. द्वारा अप्रैल- दिसम्बर 1998 की अवधि के लिए प्रदान की गयी सूचना के बहिवेंशन पर आधारित है।
- (Xiii) उनके अनुमवों के आधार पर पीले फास्फोरसत की माँग में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और पिछले चार वर्षों में लगमग स्थिर ही है । मारत में पीले फास्फोरस की माँग के संबंध में 1994-95 से 1997-98 की अविध के आकड़ें अधिक वास्तिवक चित्र प्रस्तुत करते हैं । आयात के आंकड़ों में निर्यात के उद्देश्य के लिए मी आयात सम्मिलित हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यधिक आयात 1998-99 में हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप मंडार बढ़ा है । वे महसूस करते हैं कि मारत में पीले फास्फोरस की माँग जानने के लिए वर्ष 1998-99 में किए गए आयात पर विचार नहीं किया जाना चाहिए तथा इसे 1994-95 से 1997-98 की अविध के लिए और अधिक वास्तिवक आयात पर आधारित होना चाहिए, जिसके लिए आयात के सबंध में आधिकारिक सुचना उपलब्ध है ।
- (XIV) उन्होंने अब डी.जी सी.आई एण्ड एस से 1998-99 के लिए वास्तविक आयात के आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं जो 12388 मी. टन हैं । उन्होंने सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध सूचना से विभिन्न पक्षों द्वारा किए गए आयातों की मात्रा को भी निकाला है जो 13380 मी टन निकलती है ।
- (xv) आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धी बनने तथा सकारात्मक समायोजन योजनाओं को प्रमावित करने हेतु इसे समर्थ बनाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की उद्योग को आवश्यकता है। उन्हें पीले फास्फोरस के समी आयातो पर रू० 50 प्रति कि.ग्रा तक रक्षोपाय शुल्क की तत्काल आवश्यकता है. जिसे कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये उत्पादन की लागत में मितव्ययिता के अनुपात में उत्तरोत्तर कम किया जा सकता है। तीन साल की रक्षोपाय शुल्क की माँगी गयी अवधि 5000 मी दन की अतिरिक्त संयंत्र क्षमता के विस्तार के लिए दो वर्ष तक तथा उसके बाद उत्पादन को स्थिर करने के लिए और एक वर्ष के कार्यान्वयन समय पर आधारित है।
- (XVI) उन्होंने पीले फास्फोरस का आयात अपनी सहायता के लिए और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाये रखने तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर फास्फोरस व्युत्पन्नों के अपने निर्यात को बढाने के लिए किया हैं । वे ध्यान दिलाना चाहेंगे कि पीले फास्फोरस के सस्ते आयात के परिणामस्वरूप, पीले फास्फोरस का प्रयोग करके बनाये गए विमिन्न उत्पादों की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। पीले फास्फोरस के किसी भी आयातक और उपमोक्ता ने सस्ता आयातित पीले फास्फोरस का लाम किसी को नहीं दिया है । सस्ते आयात ने केवल आयातको/ उपमोक्ताओं की निचली पिक्त को ही बढ़ाया है ।
- (XVIII) ऐतिहासिक दृष्टि से पीले फास्फोरस के उत्पादक, 1990 के आरम तक पीले फास्फोरस और इसके अनुप्रवाही उत्पादों दोनों के व्यापार में मुख्य खिलाड़ी रहे हैं । उसी समय, 1990 के आरम तक पीले फास्फोरस की घरेलू उत्पादन लागत आयातित माल से कम थी और इसने इसके अनुप्रवाही उत्पादों के व्यापार में नये सदस्यों के प्रवेश को रोका । उपरोक्त ने घरेलू बाजार में पीले फास्फोरस के विद्यमान उत्पादको पर प्रतिस्पर्धात्मक बब्द प्राप्त करने के लिए अनुप्रवाही सर्थवों के साथ पीले फास्फोरस सयव की स्थापना को आवश्यक बनाया । किन्तु इस व्यापार में प्रवेश करने के लिए इस पूर्व अपेक्षा का सामना करने के लिए बाजार में

नये प्रवेश करने वाले संमावित सदस्यों के पास न तो तकनीकी विशेषज्ञता थी और न ही वित्तीय संसाधन । 1990 के आरंग में आयातित पीले फास्फोरस की उतराई के समय की कीमत से अधिक होने वाली घरेलू उत्पादन लागत के साथ बहुत से अवसरवादी बाजारी खिलाड़ियों ने पीले फास्फोरस के उत्पादकों पर प्राप्त किए जाने वाले अचानक अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धी लाम को भुनाने के लिए पीले फास्फोरस के अनुप्रवाही उत्पादों के इस व्यापार में प्रवेश किया । चूँकि इन कम्पनियों ने आयातित पीले फास्फोरस का आश्रय लिया ( जो पीले फास्फोरस उत्पादकों को पड़ने वाली लागत से सस्ती थी ), इसलिए उन्होंने बाजार के लामों को प्राप्त किया । आयात की तुलना में घरेलू उत्पादकों की उच्चतर उत्पादन लागत को देखते हुए पीले फास्फोरस के इन उपमोक्ताओं ने घरेलू उत्पादकों से पीला फास्फोरस नहीं खरीदा ।

- (xviii) 1998-99 के दौरान मारत में पीले फास्फोरस की कुल माँग 13000 मी टन मानी जानी चाहिए जिसमें निर्यात के उद्देश्य से किया गया आयात सम्मिलित है । अनुमान है कि 1998-99 में पीले फास्फोरस का कुल शुल्क मुक्त आयात 7000 मी टन के दायरे में था, जबिक निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक आयात, संबंधित उत्पादों के निर्यातों को देखते हुए, 4700 मी टन के दायरे में था । इन आयातों में दोनो योजनाओं अर्थात डी.ई.ई.सी और डी.ई.पी बी. के अधीन आयात सम्मिलित हैं । यह प्रस्तुत किया गया है कि आयात का तरीका जिसके अधीन शुल्क मुक्त सामान का आयात किया गया है, माँग का निर्धारण करने के लिए संगत नहीं है। घरेलू माँग में से जिसे हटाये जाने की आवश्यकता है, वह वे आयात हैं जो अनुप्रवाही उत्पादों के निर्यात के कारण किए गए है, क्योंकि ये वे आयात हैं जिनका देश के व्यापार में प्रवेश नहीं हुआ ।
- (XIX) मैं० एक्सेल ने अपने उत्पादन को केवल स्थगित किया है और इसने अपना उत्पादन हमेशा के लिए बन्द नहीं किया है । इन परिस्थितियों में, घरेलू उद्योग से आशा नहीं की जा सकती है कि वे एक्सेल की माँग आवश्यकताओं को ध्यान में रखे । इसलिए मारत में पीले फास्फोरस की माँग से एक्सेल की आवश्यकता को हटा देना चाहिए ।
- (XX) फास्फोरस व्युत्पत्रों की कीमत का फास्फोरस के आयात मूल्य से कोई विशेष सबध नहीं है । जब 1998-99 के दौरान पीले फास्फोरस की कीमतें 18% कम हो गयी थी, वहीं सगत अवधि में फास्फोरस पेन्टासल्फाइड की कीमत 13% अधिक हो गयी थी । इसी तरह डी ई टी.सी.एल की कीमत 14% बढ़ गयी । पीले फास्फोरस की अधिकतम कीमत जो 1996 में 96/-फ थी, वह फास्फोरस पेन्टासल्फाइड और डी.ई.टी.सी.एल की तत्कालीन कीमत में समाहित हो गयी थी । फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के सबध में, घरेलू बाजार में अधिक क्षमता के कारण घरेलू मूल्य सदैव इसके उतराई के समय के आयातित मूल्य से कम रहे है । टी.एम.पी. के संबंध में, उतराई के समय की कीमत 1994-95 से अब तक की अवधि में 4% बढ़ गयी है, जबिक घरेलू मूल्य उक्त अवधि में अधिक क्षमता के कारण 9% कम हो गये ।
- (XXI) जहाँ तक अनुप्रवाही उद्योग और अन्ततोगत्वा कीटनाशक फार्मुलेशन पर प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के विपरीत प्रमाव का संबंध है. पीला फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जिसकी उपस्थित इसकी कीमतो से अधिक संकटपूर्ण है । पीले फास्फोरस का सकट इतना अधिक है कि 3000 करोड़ रूपये के फार्मुलेशन उद्योग का आधार 50 करोड़ रूपये का पीला फास्फोरस उद्योग है । जो कीटनाशक उद्योग में है, उनके लिए यह सामान्य जानकारी की बात है कि कीटनाशक फार्मुलेशन की कीमतो का इसकी लागत से कोई संबंध नहीं है । वास्तव में, उद्योग सूत्रों के अनुसार इसके प्रथम बिकी पर 100% या इससे भी अधिक का लाम है । उत्यादन

लागत और उपमोक्ताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच इतना अधिक अन्तर है कि कीटनाशक फार्मुलेशन के लागत मूल्य बॉचे पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के परिणामस्वरूप किसी विपरीत प्रमाव की संभावना बहुत ही कम है।

(XXII) प्रयोग किए गए पीले फास्फोरस की निम्न लागत से प्राप्त बचत की तुलना में विद्यमान क्षमता की बेकार रखने की लागत के संदर्भ में क्षित का जहाँ तक सबंध है, एक्सेल ने क्षित की गणना करने में बहुत बड़ी मूल की है। कम्पनी ने 5000 मी.टन पर 123.25 रू. प्रित कि ग्रा की उत्पादन लागत माना है, जबिक वह 105रू. होगी । आयातों की उतराई के समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए उच्च्सर लागत 30 रू. प्रित कि.ग्रा पहती है, जो 2750 मी टन के लिए 8.25 करोड़ रूपये की वृद्धि करता है, जिसकी यू.पी.एल को घरेलू बाजार के लिए आवश्यकता है । फिर भी सम्पूर्ण गलत परिकल्पना जिसे मैं० एक्सेल द्वारा अपनाया गया है, वह यह पूर्वानुमान हैं कि उत्पादन की लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा । यह प्रस्तुत किया गया है कि चौधे वर्ष अर्थात 2002-2003 में उत्पादन की लागत की तुलना आयातित कीमत से की जा सकेंगी और कोई अतिरिक्त लागत नहीं होगी, जबिक एक्सेल 3 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की आवर्ती लागत उटाती रहेगी, यदि संयंत्र को चालू न रखकर बेकार रखा जाता है । मुद्दा यह है कि 2000, 5000, 6500 और 10,000 मी. टन प्रति वर्ष फास्फोरस के उत्पादन पर एस.सी आई एल. की उत्पादन लागत क्या होगी । पीले फास्फोरस के उत्पादन का आर्थिक स्वरूप विमिन्न उत्पादन स्तरों पर महत्वपूर्ण रूप से अलग-अलग है, क्योंकि प्रति यूनिट विद्युत लागत महत्वपूर्ण रूप से मिन्न होगी जो विद्युत संयन्न उपयोग पर निर्मर करेगा । यदि कम्पनी पूर्ण स्तर पर फास्फोरस का उत्पादन नहीं करती है तो इसका नुकसान 30 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष तक हो सकता है ।

(XXIII) जनहित का अर्थ हैं अधिक संख्या में अधिक लोगों को लाम होना । रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनहित में होगा क्योंकि इससे उपमोक्ताओं को आपूर्तिकर्ताओं का अधिक विस्तृत विकल्प प्राप्त होगा तथा यह विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता सुनिश्चित करेगा, राजनीति संवेदनशीलता को समाप्त करेगा तथा आगे चलकर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कीमतो पर उत्पाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा, और इसके अतिरिक्त राज्य के स्वामित्व वाली खानो/राँक फास्फेट उद्योग के हित में होगा ।

## (ख) फास्फोरस एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (पी.ए.सी.टी.)

- (i) पी ए.सी.टी एकमात्र इकाई है जो दक्षिण भारत में सफेद/पीले फास्फोरस का विनिर्माण करती है जिसकी लाइसेंस क्षमता 2500 मी टन प्रति वर्ष और स्थापित क्षमता 1000 मी टन प्रतिवर्ष हैं । इसके पास केरल राज्य विद्युत परिषद ( के.एस ई बी) से 3000 के वी ए का सबद्ध विद्युत भार है । पी.ए.सी टी प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है ।
- (II) पीले या सफेद फास्फीरस के उत्पादन के लिए राक फास्केट, कोक, सिलिका और विद्युत शक्ति मुख्य कच्चा माल हैं। पीले फास्फीरस के विनिर्माण की प्रक्रिया लगभग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसके अतर्गत इलेक्ट्रोथर्मल रूट द्वारा सिलिका और कोक की उपस्थिति में राक फास्फेट का फास्फोरस में बदलमा सिम्मिलित हैं। इण्डोथर्मिक प्रतिक्रिया के कारण, पीले फास्फोरस के विनिर्माण के लिए यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊर्जा प्रधान प्रक्रिया है। विद्युत ऊर्जा द्वारा उत्पादित उष्मा के माध्यम से इस ऊर्जा को उपलब्ध कराया जाता है जो केरल सरकार से प्राप्त की जाती है। फिर भी 10% वार्षिक वृद्धि के अतिरिक्त, जो पहले से ही विद्यमान है,

हाल ही में केरल सरकार द्वारा 2.50 रूपये प्रति यूनिट की विद्युत दर में तीव्र वृद्धि से उनका प्रचालन पूर्णतः अव्यवहार्य हो गया है और वे अपना उत्पादन स्थिगत करने के लिए बाध्य हो चुके हैं । कम्पनी एक लघु हाइडिल विद्युत योजना कार्योन्वित कर रही हैं । जो पी.ए.सी.टी. को न केवल लगातार एवं निर्बाध विद्युत सुनिश्चित करेगी बल्कि, पील फास्फोरस के उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत की लागत को भी कम करेगी ।

- मारतीय उद्योग का घरेलू उत्पादन 1994-95 में लगभग 4750 मी.टन से 1998-99 में लगभग 612 मी टन अर्थात 87% कम हो गया । केरल राज्य में अपेक्षाकृत बहुत कम विद्युत दर के कारण पी ए.सी टी. अपना उत्पादन जारी रखने में समर्थ रहा । फिर भी केरल सरकार ने 10% वार्षिक वृद्धि, जो अभी भी विद्यमान है, के अलावा मई 1999 में विद्युत दर भी 2.50 रूपये प्रति यूनिट बढ़ा दिया । विद्युत दर के इस तीव वृद्धि के साथ पी.ए.सी.टी. के उत्पादन की परिवर्तनशील लागत महत्वपूर्ण रूपसे बढ़ गयी है और पी ए.सी टी. के उत्पादन की परिवर्तनशील लागत इस समय आयातित पीले फास्फोरस के उतराई के समय के मूल्य से अधिक है । पी.ए सी.टी. भी मई 1993 के अन्त से उत्पादन स्थिगत करने के लिए बाध्य हो गया है ।
- (iv) पाँच वर्षों में भारतीय उद्योग का क्षमता उपयोग लगभग 48% से घटकर 6% रह गया है । यह मुख्य रूप से आयात के 48% से लगभग 94% बढ़ने के कारण हैं जिसने भारतीय उद्योग को अपना उत्पादन तेजी से घटाने के लिए बाध्य किया ।
- (V) प्रतिस्पर्धात्मकता बढने से घरेंलू उत्पादक एक-एक करके अपना उत्पादन स्थागित/कम करने के लिए बाध्य हो गये ।
- (VI) उपलब्ध क्षमता की हद तक अपना उत्पादन बेचने में पी.ए.सी.टी समर्थ नहीं रहा है। आग्रात के उतराई के समय के महत्वपूर्ण रूप से कम मूल्य के कारण अपने बिकी मूल्य को कम करने के लिए घरंलू उद्योग को बाध्य होना पड़ा है। पुन यहाँ तक कि वर्तमान विकय मूल्य, जिससे कच्चे माल की लागत भी वसूल नहीं हो पाती है. आग्रात के उतराई के समय के मुख्य से अधिक है। इस तरह आग्रात के कारण बाजार में मूल्यों में गंभीर रूप कटौती करनी यह रही है।
- (Vii) व अपने एत्पाद को उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर बेचने को बाध्य हुए हैं. जिसके परिणामस्वरूप गभीर वित्तीय अति हुई हैं। भारत में पीले फास्फोरस के आयात ने घरेलू उद्योग को गंभीर रूप से अति पहुंचायी हैं। पीले फास्फोरस के सभी आयातो पर कम से कम 50/- रूपये प्रति कि.ग्रा रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से अति को सनाप्त किया जा सकता है।
- (viii) पी ए सी.टी के पास 1996-97 में लगभग 102 लोग थे । कम्पनी को वर्तमान कीमतो पर उत्पादन करने तथा बेचने में असमर्थता के कारण मानव शक्ति को कम करना पड़ा है । यदि कम्पनी अपना उत्पादन पुन आरम नहीं करती है तो सभी कर्मचारियों को रोजगार से विचत होना पड़ेगा ।
- (ix) पी.ए.सी.टी. 80 करोड़ रूपये की लागत से मट्दी में रूपान्तरण कर रहा हैं, जो उत्पादन तथा लागत दोनों की दृष्टि से मट्दी की कार्य कुशलता में वृद्धि करेगा । इस रूपान्तरण से सयब क्षमता उपयोग में वृद्धि होने, और लगमग 30% की क्षमता में स्वयं वृद्धि होने की आशा है । इसी तरह, मट्दी में रूपान्तरण से

आशा है कि समय बढ़ने के साथ-साथ संयंत्र वालन कुशलता में और सुधार होगा । इससे कच्चे माल (विद्युत, राक फास्फेट, कोक) के लिए यूनिट उपमोग में कमी लाने और अधिक मात्रा में निर्धारित लागत के वितरण में सुविधा होगी । आशा है कि पीले फास्फोरस की प्रति मी.टन लागत में महत्वपूर्ण रूप से कमी आयेगी ।

(X) पीले फास्फोरस के लिए विद्युत मुख्य कच्चा माल है जिस पर उत्पादन के कुल लागत के 50% से अधिक खर्च बैडता है। केरल सरकार की अधिसूचना के आधार पर केरल राज्य विद्युत परिषद (के एस ई बी) के साथ कम्पनी ने एक प्रारंमिक समझौता किया है और चार मेगावाट क्षमता के एक लघु जल विद्युत सर्यव की स्वीकृति प्राप्त की हैं। कम्पनी पहले ही केरल राज्य विद्युत परिषद (के.एस.ई बी) को तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत कर चुकी हैं। इस विस्तृत व्यावहारिकता रिपोर्ट का अध्ययन एक बाहरी एजेन्सी द्वारा किया गया है जो इस क्षेत्र मे विशेषज्ञ हैं। यह परियोजना जब पी.ए सी टी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी तो न केवल पीले फास्फोरस संयत्र को लगातार विद्युत आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने बल्कि बहुत सस्ती दरों पर विद्युत की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगा।

## (ग) आयातकों तथा उपयोगकर्त्ता उद्योगों के दृष्टिकोण

10(क) कीटनाशक विनिर्माता कीटनाशक उद्योग ने सामान्यतः निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उदाए हैं .-

- (i) उन्होंने याचिका का अध्ययन किया है तथा 50/-रू प्रति किलों के अत्यधिक रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के प्रस्ताव पर अधिक चिन्तित हैं जो कि पीले फास्फोरस के आयात पर लगमग 120% अतिरिक्त शुल्क के समान है। यदि यह शुल्क अधिरोपित कर दिया गया तो यह फास्फोरस आधारित मध्यवर्तियों की लागत को पर्याप्त माना में बढ़ा देगा, जो कि कीटनाशक टेक्निकल के विनिर्माण में जाता है।
- (ii) कीटनाशक व्यापार बहुत अधिक प्रतिस्पूर्धात्मक है जिसमें लामाश बहुत कम है और इसलिए इस अतिरिक्त लागत का प्रमाव ग्राहको अर्थात किसानों पर ही पड़ेगा जो पहले से ही अत्यधिक वित्तीय संकट में है।
- (iii) यू.पी.एल./ सर्च केम उद्योग जो सफेद/पीले फास्फोरस के मुख्य विनिर्माता है और अधिकतर टेक्निकलों मे प्रतिस्पर्धी हैं. उनका रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का अनुरोध, इस मुख्य कच्चे माल, जो सभी आर्गनो-फास्फोरस कीटनाशकों के विनिर्माण मे प्रयोग किया जाता है, को नियंत्रित करके वे कीटनाशक उद्योग पर अनुचित रूप से प्रमुख जमाने की स्थिति में हो जाएंगे।
- (iv) यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर दिया जाता है तो उनको जबरन फास्फोरस आधारित कीनाशकों के उत्पादन को बन्द करना पहेंगा और वे आयातित कीटनाशकों की उतराई के समय की लागत से प्रतिस्पर्धी नहीं होंगे । रक्षोपाय शुल्क का उदेश्य केवल दो अथवा तीन कम्पनियों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि घरेलू उद्योग को बचाना है । इस प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का परिणाम यह होगा कि वह दो से तीन कम्पनियों को शायद बचा ले लेकिन इसके परिणामस्वरूप बहुत सी ईकाइयाँ बन्द हो जाएगी और वह वास्तव में आवेदकों को एकाधिकार प्रदान करेगा । यह रक्षोपाय शुल्क पीले फास्पोरस जो कीटनाशक उद्योग के लिए मुख्य सामग्री है, के विनिर्माण तथा आपूर्ति में जरूरी तौर पर आवेदकों को एकाधिकार ही देगा ।

- (v) आयात इस तथ्य के कारण शुरू किए गए थे कि घरेलू विनिर्माता प्रतिस्पर्धात्मक कीमतो पर पर्याप्त माला में आपूर्ति की स्थिति में नहीं थे ! जिन कीमतों पर उत्पाद मारत में आयात किया जा रहा है वे अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बराबर हैं और इसलिए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मारतीय विनिर्माताओं/आयातकों को आपूर्ति करते समय विशेष रियायत अथवा सुविधा नहीं दी गई है ।
- (vi) यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो कीटनाशक विनिर्माताओं को फास्फोरस आधारित मध्यवर्तियों को वर्तमान स्थानीय बाजार से इटकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्पर्धात्मक लाम स्वतः ही सफेद/ पीले फास्फोरस के अन्तर्राष्ट्रीय उपमोक्ता, जो इसी प्रकार के उत्पादों का विनिर्माण कर रहे हैं, के पक्ष में होगे । इसके परिणामस्वरूप मी निर्यात व्यापार को काफी हद तक नुकसान हो सकता है । वास्तव मे आज भी कुछ निर्यात आदेश केवल इसलिए हाथ से निकल गए क्योंकि अन्य विकसित देशों के आपूर्तिकर्ताओं के मुकाबले भारतीय कीमते । से 15% अधिक हैं ।
- (vii) यह भी संभावना हो सकती है कि उपरोक्त शुल्क अधिरोपण से कीटनाशकों की उत्पादन लागत बहुत अधिक हो सकती है जिससे विभिन्न देशों से सीधे ही टेक्निकल के आयात को बढ़ावा मिलेगा । यदि यह स्थिति पैदा होती है तो अनेकों कम्पनियों को या तो अपना उत्पादन कम करने के लिए अथवा लम्बी अवधि में व्यापार से बाहर हो जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।
- (Viii) पूरा कीटनाशक उद्योग एक संकटकालीन समय से गुजर रहा हैं । स्थानीय उद्योग को विश्वव्यापीकरण के प्रमाव से अभी भी समलना है तथा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में बहु-राष्ट्रीय कम्पिनयों के साथ गंभीर प्रतिस्पर्धा है । फास्फोरस के शुल्क में कोई भी प्रस्तावित वृद्धि कृषि रसायन उद्योग के हितों के लिए हानिकारक हैं ।

इन मुख्य मुद्दों के अलावा कुछ पक्षों ने निम्नलिखित अतिरिक्त निवेदन किया है -

# (क 1) संघ्या आर्गैनिक केमिकल्स प्राइवेट लि., मुम्बई 400 057

- (i) 16 वर्षों से भी अधिक अवधि से वे कीटनाशक /जीवनाशी तथा फास्फोरस आधारित मिश्रण (एल्यूमीनियम फास्फाइड तथा जिंक फास्फाइड) के विनिर्माता हैं जो भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भांडागारण निगम, पंजाब भांडागारण निगम, हरियाणा भांडागारण निगम तथा अन्य, जो कि केन्द्र/राज्य सरकार के निकाय हैं, को आपूर्ति किया जाता है। फास्फोरस आधारित रसायन जैसे कि फास्फोरस आक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ट्राक्लोराइड तथा फास्फोरस पेन्टाक्साइड की आपूर्ति औषध तथा रंग सामग्री उद्योगों को की जा रही है।
- (ii) क्योंकि यू.पी एल. तथा एस.सी आई.एल. उनके प्रतिस्पर्धी हैं, उन्होंने मूतकाल में उनकों कभी भी सफेद/ पीला फासफोरस देने का प्रस्ताव नहीं किया तथा मविष्य में भी कोई मात्रा उन्हें नहीं देंगे । रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण को कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से सफेद/ पीले फास्फोरस का आयात करके केन्द्र/ राज्य सरकार के विभागों की आवश्यकता को पूरा कर सकें अन्यथा उनकी इकाई बन्द हो सकती है जिससे अनेकों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे ।

# (क.2) केमिनोवा इण्डिया लि., मुम्बई

- (i) कृषि रसायन उद्योग पीले फास्फोरस तथा उसके सम्मिश्रणों के लिए प्रमुख अन्तिम प्रयोगकर्ता उद्योग है । यह अनुमान लगाया जाता है कि 70% से अधिक पीले फास्फोरस की खपत आर्गैनों पास्फोरस (ओ.पी.) कीटनाशक के उत्पादन में हो जाती है ।
- (ii) अनुमान लगाया जाता है कि पीले फस्फोरस को सालाना घरेलू माग लगमग 18000 मी.टन हैं। दो मुख्य उत्पाद जो पीले फास्फोरस से विनिर्मित किये जाते हैं वे हैं फास्फोरस ट्राईक्लोराइड (पी सी एल 3) तथा फास्फोरस पेन्टासल्फाइड (पी 2 एस 5)। अनुमान हैं कि पी सी एल 3 के उत्पादन का लगमग 74%, पी 2 एस 5 के उत्पादन का 72% तथा लाल फास्फोरस के उत्पादन का 30% मारत में कीटनाशक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है।
- (iii) पिछले दशक में मुख्य "मार्किट फन्डामैन्टल्स" के जवाब में यूरोप तथा उत्तरी अमरीका में पीले फास्फोरस (वाई पी) के उत्पादन में गिरावट आई है। वाई पी की माग में भी गिरावट आई है क्योंकि शुद्धीकृत गीले एसिड जो कि पीले फास्फोरस से उत्पादित थरमल एसिड के लिए एक सस्ता स्थानापन्न है. उपलब्ध हो गया। नान फासफेट फास्फोरस व्युत्पन्नों के उत्पादन के लिए वाई पी की माग बनी रही हैं। तब 1980 के अन्त में यूरोपियन तथा उत्तरी अमरीकी उत्पादकों ने अपने वाई पी के सयन्न बन्द करने का और सस्ती दरों पर चीन से वाई पी आयात करने का निश्चय किया जिससे कि वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर नान-फास्फेट फास्फोरस व्युत्पन्नों का उत्पादन कर सकें।
- (iv) चीन एक ऐसा देश हैं जहां वाई पी के लगभग 60 उत्पादक हैं और कारखाने चीन के 4 मुख्य प्रान्तों में स्थित हैं । चीन के पास भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता की सरलता से खनन की गयी फासफेंट की चट्टानें, कोयला, पास में मिट्टियाँ तथा जल विद्युत शक्ति के स्त्रोत, निवेश तथा कार्यरत पूंजी के लिए अधिक सस्ती दर पर वित्तीय लागत की अधिकता है । चीनी विनिर्माताओं को कम लागत पर वाई पी. के विनिर्माण में इसने बड़ा लाम पहुंचाया है । ऐसा अनुमान है कि आज चीन में वाई पी. का लगभग 2,50,000 मी टन का उत्पादन होता है तथा इस उत्पादन का लगभग 50% संसार के अन्य भागों में निर्यात किया जाता है ।
- (v) पिछले दशक के दौरान भारत में वाई पी. की माग बहुत अधिक बढ़ी हैं। यह प्रमुख रूप से कीटनाशक उद्योगों में व्युत्पन्नों / मध्यवर्तियों पी.सी एल 3 / टी.एम.पी. तथा पी 2 एस 5 की बढ़ी हुई माग के कारण हुआ । 1970 के दशक के दौरान तथा 1980 के दशक के शुरूआत में भारत में वाई पी. सयत्रों को इसलिए स्थापित किया गया था ताकि उससे मध्यवर्तियों तथा कीटनाशकों को बनाने के लिए कैप्टिव आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । फिर भी. व्युत्पन्नों मध्यवर्तियों की माग बढ़ी तथा घरेलू क्षमता से अधिक हो गई । परिणामस्वरूप इनकी बढ़ती माग को पूरा करने के लिए वाई पी. व्युत्पन्नों के आयात की शुरूआत हुई ।
- (vi) शुरू में आर्रीनो फस्फोरस के विनिर्माताओं ने उच्च दरों के व्युत्पन्नों जैसे टी.एम पी. तथा डी ई.टी सी एल. का विकसित देशों से आयात किया । तथापि, जैसे-जैसे इन उत्पादों की माँग में वृद्धि हुई, अनेकों ने आयातित वाई पी. के आधार पर उसी प्रकार के स्वदेशी व्युत्पन्नों को बनाने का निश्चय किया । आयातित वाई पी. के आधार पर देशी वाई पी. व्युत्पन्नों के विनिर्माण का निर्णय भारत के लिए तथा उद्योग के लिए एक जबर्दस्त

सफलता के रूप में सामने आया । यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण हैं कि चीन से उच्च गुणवत्ता तथा कम कीमतों के वाई.पी. की सरल उपलब्धता ने वाई.पी. व्युत्पन्नों के भारतीय उत्पादकों को वहीं लागत संबंधी लामांश दिया जैसे कि उनके साथियों को यूरोप और उत्तरी अमरीका में मिला । भारत न केवल वाई.पी व्युत्पन्नों के लिए स्वावलम्बी हो गया बल्कि भारत अब एक उच्च गुणवत्ता वाले वाई.पी. व्युत्पन्नों जैसे कि पी सी एल 3 तथा टी एम पी का गंभीर निर्यातक भी बन गया है । रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण वाई पी. व्युत्पन्नों के सभी विनिर्माताओं को गंभीर क्षति पहुँचाएगा ।

- (Vii) घरेलू उत्पादन में कमी वाई.पी. के आयातों के कारण नहीं हुई बल्कि व्युत्पन्नो/मध्यवर्तियों को और अधिक मितव्ययिता पूर्वक उत्पादित करने तथा इन उत्पादों के आयात के विपरीत अपने हितों की रक्षा के लिए वाई.पी के आयात के लिए वाई.पी के तत्कालीन विनिर्माताओं के परिकलित निर्णय के कारण थी ।
- (Viii) मारत में वाई.पी. की उत्पादन क्षमता लगमग 3000 मी टन मात्र आँकी गई है । इसके विपरीत वाई.पी. की वार्षिक घरेलू माँग लगमग 17,000 मी. टन है । वर्ष 1999-2000 में माँग 19,000 मी टन तक पहुँचने की आशा है । यह स्पष्ट है कि पीले फास्फोरस की उपलब्ध घरेलू उत्पादन क्षमता माँग को पूरी करने में सक्षम नहीं होगी । वास्तव में उपलब्ध घरेलू उत्पादन क्षमता, 19,000 मी. टन की कुल घरेलू माँग के केवल 15% का प्रतिनिधित्व करती है । अतः भविष्य में पीले फास्फोरस का बड़ी मात्रा में आयात अपरिहार्य हैं ।
- (ix) पीला फास्फोरस विनिर्माण की तकनीक लगमग 50 वर्ष पुरानी है तथा निवेश प्रयोग अनुपात आदि की दृष्टि से बहुत अच्छी तरह स्थापित है । अतः यह ध्यान देने लायक है कि 17 सालों से भी अधिक समय से निरंतर उत्पादन होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर उत्पादन लागत को नीचे लाने में समर्थ नहीं हो सका । क्योंकि उद्योग अत्यधिक विद्युत प्रधान है तथा इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में विद्युत और पैट्रोलियम की लागत निरंतर बढ़ रही हैं. यह संभव नहीं है कि भारत में पीले फास्फोरस की उत्पादन लागत वर्तमान में चल रही अन्तर्राष्ट्रीय कीमतो की बराबरी तक नीचे लाई जा सके । पीले फास्फोरस के उत्पादन में अकेले विद्युत की लागत 50/% है,जबिक अन्य परिवर्तनशील लागत, कुल लागत की 30-45% पड़ती है,इसतथ्य के कारण उत्पादन क्षमता को अधिक बढ़ाने से भी स्तरीय मितव्ययिता (इकोनॉमी आफ स्केल) से लाम नहीं होगा।
- (X) रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए एस.सी.आई.एल ने आवेदन किया है, जिन्होंने याविका में दिए गए अपने बयान के अनुसार ऐसा लगता है कि सफेद/पीले फास्फोरस का विनिर्माण केवल 14-6-99 से शुरू किया है । अतः उनका फास्फोरस विनिर्माण का कोई पूर्व इतिहास नहीं है। अतः वे यह आरेप लगाने से रोके गए हैं कि वर्धित आयातों ने उनको गंभीर क्षति पहुँचाई है क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रथम स्थान पर वाई पी का विनिर्माण नहीं किया । अतः इस मामले में एस.सी.आई.एल की कोई वैद्यानिक स्थिति नहीं है । इसी प्रकार सह-आवेदक यू पी एल ने चूँकि पहले ही, सितम्बर,1996 में फास्फोरस का उत्पादन बन्द कर दिया है, इस तथ्य के कारण उनकी भी इस मामले में कोई भी अधिकारिता नहीं है । पी ए सी टी 1000 टी पी ए से भी कम की उत्पादन क्षमता के साथ पीले फास्फोरस के बहुत ही छोटे उत्पादक हैं तथा अपनी दो सहयोगी इकाइयों को आपूर्ति कर रहे हैं जो लाल फास्फोरस का विनिर्माण कर रहे हैं। उनका बाजार शेयर नगण्य है, इसलिए वे मुश्किल से कोई वैध स्थित रखते हैं।
- (Xi) वर्तमान स्थानीय आपूर्ति की तुलना में भारत में फास्फोरस मध्यवर्ती डी.ई.टी.सी एल की मॉग महत्वपूर्ण रूप से अधिक है तथा 1998 में डी.ई.टी.सी एल का लगमग 3000 मी टन प्रति वर्ष का अनुमानित

मात्रा का आयात किया गया । 1999 के आरम में पेनोली में 5000 मी. टन प्रति वर्ष डी.ई.टी.सी.एल. विनिर्माण संग्रंत्र स्थापित करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े निवेश का आरम किया । जून 2000 तक इस संग्रंत्र को शुरू करने के लिए यथेष्ट कार्य तथा निवेश का पहले ही वायदा किया जा चुका है तथा आशा है कि संग्रंत्र लगमग 100 व्यक्तियों को नियुक्त करेगा । यह मारत को इसकी डी.ई.टी.सी.एल. की आवश्यकताओं तथा मविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह आत्मनिर्मर बना सकेगा । पीले फास्फोरस पर 50 रू प्रति किलों के रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उनको गंभीर क्षति पहुँचाएगा तथा परिणामस्वरूप डी.ई टी सी.एल परियोजना को संभवत ताक पर रखवा देगा क्योंकि निवेश अन्य के साथ में वर्तमान आयातित पीले फास्फोरस की कीमतों के आधार पर न्यायसंगत था तथा इसे स्वीकृत किया गया था ।

## (क.3) नागार्जुन एग्रीकेम लिमिटेड, पंजागट्टा, हैदराबाद - 500 082

- (i) अन्य देशों के विपरीत, भारतीय कृषि में फसल की सुरक्षा के लिए कीटनाशक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत में बेचे जाने वाले फसल रक्षक उत्पादों की कीमतों का 70% से भी अधिक माग कीटनाशकों का है। वर्तमान में भारत में बहुतायत से प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों में आर्गेनो-फास्फेट का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। उत्पाद जैसे मोनोकोटोफास तथा क्लोरपाइरीफास को देश मर में मात्रा प्रयोग की दृष्टि से प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर माना जा सकता हैं। अन्य कई उत्पाद भी है जैसे डी.डी.वी.पी, क्वीनलफास आदि जिनका भी प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। ये सभी आर्गेनो फास्फेट कीटनाशक, फास्फोरस आधारित सम्मिश्रणों से प्राथमिक रूप में उत्पन्न किए जाते हैं। फास्फोरस के कच्चे माल की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि से मारतीय किसानों की निवेश लागतों में बढ़ोत्तरी होगी।
- (ii) मारंत के लिए निर्यात द्वारा आय में कृषि रसायन एक बड़ी मूमिका अदा करते हैं । कृषि रसायनों के निर्यात में वृद्धि, औषधियों की निर्यात दरों की तुलना में हो रही हैं । पहले से ही एक प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात बाजार में यदि वे आर्गेनो-फास्फेट कीटनाशकों के उत्पादन की लागत में वृद्धि करते हैं तो निर्यात बिकियों में तुरन्त गिरावट का रूख हो जाएगा जो मारंत से निर्यात को बढ़ाने की घोषित सरकारी नीति के प्रतिकृल होगा ।
- (III) प्राथमिक रूप से यू पी एल द्वारा एक कमजोर व्यापारिक निर्णय को सरकार के हस्तक्षेप से सुधारा नहीं जा सकता है। जबकि यू पी एल तथा इसकी सहायक सर्च केम को अत्यधिक फायदा हो सकता है, मारतीय किसान, फसल की उत्पादकता तथा अन्य अच्छी कम्पनियों जैसे नागार्जुन को मारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
- (iv) यू.पी.एल ने सर्च केम में कृत्रिम विद्युत उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है । गुजरात राज्य विद्युत परिषद ने सर्च केम से विद्युत न खरीदने का निर्णय लिया है, इसलिए सर्च केम के पास केवल एक ही विकल्प बचा है कि वह यू.पी.एल को विद्युत बेचे । यू.पी.एल में विद्युत आधारित संचालन, फास्फोरस का उत्पादन है । इसलिए, यू.पी.एल. जब तक फास्फोरस निर्मित नहीं करता तथा सर्च केम में उत्पादित विद्युत का प्रयोग नहीं करता, निकट मविष्य में सर्च केम एक व्यावहारिक कम्पनी नहीं होगी । यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह सर्च केम में यू.पी.एल. के कष्टप्रद निवेश से उसकी रक्षा करें ।
  - (VI) नागार्जुन सहित अनेक कम्पनियों ने विनिर्माण प्रक्रियाओं को बैकवर्ड इन्टीग्रेट करने का निर्णय लिया है । उन्होंने डी.एम टी.सी नामक कच्चे माल से टेक्निकल ग्रेड एसीफेट बनाने के लिए पर्याप्त स्त्रोतों को गँवाया

है। तथापि डी एम पी ए.टी. नामक एक मध्यवर्ती अब एक सस्ते विकल्प के रूप में चीन से उपलब्ध है। डी एम.पी.ए.टी. से एसिफेट बनाना अधिक लागत वाला है, इसलिए उन्होंने डी एम.पी.ए.टी. के प्रयोग करने की अपनी प्रक्रिया को बदल दिया है। डी एम.पी.ए.टी. के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के लिए वे सरकार के पास नहीं जा रहे हैं और इससे प्रतिस्पर्धात्मक लाम उढ़ा रहे हैं।

# (क.4) एक्सेल इंडस्ट्रीज लि. मुम्बई - 400 102

- (i) 1970-92 की अवधि के दौरान पीले फास्फोरस का उत्पादन करने वाली अधिकाश कम्पनियाँ उसे मध्यवर्तियों में परिवर्तित कर रही थीं । पीले फास्फोरस के विनिर्माण में बिजली सबसे अधिक महागा तत्व है तथा प्रति मी. टन. पीले फास्फोरस के लिए इसकी खपत लगमग 14000 किलो वाट है । मारत में विद्युत की कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि से विशेषकर महाराष्ट्र तथा गुजरात में ( जहाँ पीले फास्फोरस के सयंत्र स्थित हैं ) मारत में पीले फासफोरस का विनिर्माण करना तथा चीन. रूस, बल्गारिया, कज़ाकिस्तान तथा इसी प्रकार के अन्य देशों के आयातों से प्रतिस्पर्धा करना अव्यवहार्य हो गया । इसलिए, स्टार, यू.पी एल. तथा एक्सेल ने उसी कम में अपने पीले फासफोरस के उत्पादन को बन्द करने का निर्णय लिया तथा मूल्य वर्धित मध्यवर्तियों के उत्पादन के लिए उसके आयात का आश्रय लिया । यह स्थिति गत पांच वर्षों से चल रही है ।
- (ii) मैसर्स फास्फोरस एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि॰ (पी.ए.सी.टी) जो कि अपने उपलब्ध सस्ते जल विद्युत शक्ति के आधार पर अपने केरल स्थित संयत्र में पीले फास्फोरस के उत्पादन की एक अन्य कम्पनी थी, वे स्टार, एक्सेल तथा यू पी एल के मुकाबले अधिक लाम में थे तथा पिछले 10 सालों से अधिक समय से 500 मी.टन का एक नगण्य उत्पादन कर रहे थे। उनका पीले फास्फोरस पर आधारित कोई और उत्पादन नहीं हैं तथा एक वहीं कम्पनी थी जो उत्पादित समी पीले फास्फोरस की विक्रेता थी जबकि स्टार, एक्सेल तथा यू.पी.एल. अपने द्वारा उत्पादित लगमग सारा पीला फास्फोरस अपने ही कैप्टिव प्रयोग के लिए सदैव उपमोग करते रहे हैं।
- (iii) यू.पी.एल./एस.सी आई.एल. का मुख्य व्यापार पीले फास्फोरस व्युत्पन्नों का है, न कि स्वयं पीले फोस्फोरस का । अपने अधिकतर पीले फास्फोरस का उनके द्वारा स्वयं ही कैप्टिव उपमोग कर लिया जाता था तथा एक नगण्य मात्रा ही बाहरी पक्षों ध्ये बेची जाती थी ।
- (iV) मारत में उत्पादित पीले फास्फोरस का बहुत ही कम व्यापार हैं । पीले फासफोरस के अन्य सीधे उपमोक्ता हमेशा से आयात करते रहें है क्योंकि घरेलू उत्पादन मारत में कुल खपत से बहुत कम था । स्वयं आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया हैं, क्योंकि 16,000 मी.टन से भी अधिक कुल खपत के मुकाबले कुल स्थापित क्षमता 10,000 मी.टन हैं । अकेले इन तीन कम्पनियों अर्थात स्टार, एक्सेल तथा यू.पी.एल. द्वारा उत्पादित मध्यवर्तियों की कीमते 150 करोड़ रूपयें आँकी गई हैं जबकि उपमोग किए गए पीले फास्फोरस की कीमत 45 करोड़ रूपयें आकी गई हैं ।
- (V) 1996 से यू.पी.एल. ने अपनी पीले फास्फोरसं की मट्टी बन्द रखी थी । उनकी ग्रुप कम्पनी एस.सी.आई.एल. में स्थापित कैप्टिव विद्युत संयंत्र की उपमोग क्षमता बढ़ाने के लिए मट्टी स्थानांतरित करके एस.सी.आई.एल. में फिर से स्थापित की । भारत की 16,000 मी.टन की खपत की तुलना में क्षमता फिर भी लगमग 4000 मी.टन होगी । घरेलू उत्पादन इतना अधिक कम है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण भ्यायोचित

नहीं है जो समस्त उद्योगों को अव्यवहार्य बना देगा । वास्तव में यू.पी.एल. को भी हानि होगी क्योंकि यदि पीला फास्फोरस वर्तमान से अधिक महंगा कर दिया गया तो उनके द्वारा विनिर्मित अन्तिम उत्पादों का आयात शुरू हो जाएगा ।

- एक उद्योग मानदण्ड के आधार पर पीले फास्फोरस के प्रत्येक मी दन के उत्पादन पर लगमग (vi) 14,000 किलोवाट प्रति घंटा बिजली की आवश्यकता पड़ती हैं । 5/- रूपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा मूल्य से पीले फास्फोरस के लिए बिजली की ही कीमत 70/- का प्रति किलो है । राक फास्फेट तथा कोक के साथ जो कि अन्य कच्चे माल हैं, की पीले फास्फोरस की परिवर्तनशील कीमत लगभग 95/-रू प्रति किलों है । उनके हिसाब से सामान्य ऊपरी खर्चों तथा न्यूनतम लाम के साथ जब स्थानीय रूप से उत्पादन किया जाए तब पीला फास्फोरस 110/- रू० प्रति किलो से कम पर नहीं बेचा जा सकता । उत्पादन लागत पर्याप्त रूप में कम करने की कोई संभावना नहीं हैं जब तक कि स्वय बिजली की कीमत कम न हो । 3000 मी.टन प्रति वर्ष वाले पीले फास्फोरस के संयंत्र के लिए लगमग 6 मेगावाट की विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है । इसलिए पीले फास्फोरस के व्यक्तिगत संयंत्र कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना नहीं कर सकते । थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए विद्युत शृंखला की आवश्यकता बहुत कम है लेकिन डी जी सेटों के लिए बहुत अधिक हैं । कास्टिक क्लोराइन संयंत्र के लिए एस.सी.आई.एल. ने एक विद्युत संयंत्र स्थापित किया था तथा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत पीले फास्फोरस संयंत्र में इस्तेमाल के लिए यू.पी.एल. से उनकों स्थानातरित कर दी गयी थी । उनको यह पता नहीं है कि पीले फास्फोरत संयंत्र की दी गई विद्युत की क्या कीमत होगी तथा पीले फास्फोरस की उत्पादन लागत किस सीमा तक कम की जा सकती है । लेकिन यह स्थिति केंवल एस.सी.आई.एल. के लिए अनोखी है । यदि पीले फास्फोरस पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो भारत में पीले फास्फोरस के अन्य उत्पादकों की तुलना में स्पष्ट रूप से अनुवित ढंग से केवल एस.सी.आई.एल. की लाम होगा, तथा पूरे कीटनाशक उद्योग, आटोमोटिव उद्योग तथा रक्षा और सबसे अधिक भारतीय किसानों पर विपरीत प्रमाव पड़ेगा । इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि एस.सी.आई.एल. स्थापित क्षमता में वृद्धि करके उत्पादन लागत को कम कर सकता है ।
- (vii) 1994-95 में यू.पी.एल. द्वारा उत्पादित पीले फास्फोरस की उत्पादन लागत 91.20 रू० प्रति किलोग्राम थी जब विद्युत की कीमत 2.61 रू. किलोवाट प्रति घंटा थी। वर्तमान में एस.सी आई.एल. द्वारा उत्पन्न विद्युत की कीमत 3.60 रू. प्रति किलोवाट प्रति घंटा हैं। यदि विमिन्न उपायों को अपनाया जाय तो एस.सी.आई.एल. विद्युत उत्पन्न करने की लागत को 3.60 रू. प्रति किलोवाट प्रति घंटा से कम करके 2-61 रू. प्रति किलो वाट प्रति घंटा करने में सक्षम हैं तो उपरोक्त से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पीले फास्फोरस की उत्पादन लागत लगमग 91/- रू. प्रति किलो के दायरे में है जो कि 45% आयात शुक्क मिलाकर भी पीले फास्फोरस की वर्तमान उतराई के समय की लागत से 36% अधिक है।
- (viii) आवेदकों का यह कथन कि पीले फास्फोरस मध्यवर्तियों, जो कि निर्यात किए जाते हैं, के विनिर्माण के लिए पीले फास्फोरस की आवश्यकता को, पीले फास्फोरस की माग को आंकने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के आयात शुल्क मुक्त हैं तथा रक्षोपाय शुल्क उनको प्रमावित नहीं करेगा, ठीक नहीं है क्योंकि पीले फास्फोरस मध्यवर्तियों का एक बहुत बड़ा माग डी.ई.बी.पी. योजना के अधीन निर्यात किया जाता है न कि अग्रिम लाइसेंस योजना के अधीन । अतः उन पीले फास्फोरस के आयात जो अग्रिम लाइसेंस योजना के अधीन नहीं है, रक्षोपाय शुल्क को आकृष्ट करेंगे और इसलिए पीले फास्फोरस की मांग के आकलन के लिए इसको हिसाब में लेगा ही पड़ेगा ।

(ix) 5000 दन प्रति वर्ष की क्षमता वाले पीले फासफोरस के एक संयत्र की कीमत लगमग 10 करोड़ रू पहेगी । 15% प्रति वर्ष ब्याज दर से तथा 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन के रूप में लागत 2.50 करोड़ रू. होगी तथा 10 लाख रू. की अन्य आंकलित लागत के साथ क्षमता को खाली रखने की लागत 3 करोड़ रू. के दायर में होगी । इसके विपरीत पीले फास्फोरस के मध्यवर्तियों के विनिर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीले फास्फोरस की कम कीमतों के कारण प्राप्त बचत 24 13 करोड़ रू. प्रति वर्ष होगी जो उत्पादन लागत तथा उतराई के समय की लागत के बीच अन्तर होगी जो कि स्वय पीले फास्फोरस सयत्र में कुल निवेश से अधिक है। एक्सेल में, 3000 दन प्रति वर्ष क्षमता वाले पीले फास्फोरस के संयत्र को बेकार रखने की लागत (क्षः करोड़ रू.की लागत से स्थापित), जो 10% की दर से अवमूल्यन, 15% की दर से ब्याज तथा 0.6% की दर से बीमा के हिसाब से 1.54 करोड़ रू.प्रति वर्ष निकलती हैं, जिसके फलस्वरूप 14.40 करोड़ रू.की बचत होगी।

# (क.5) स्टार केमिकल्स ( बम्बई) लिमिटेड, मुम्बई

- (i) वे लगमग 1970 से फास्फोरस तथा इसके मध्यवर्तियों का विनिर्माण कर रहे हैं । महाराष्ट्र में स्थित संयंत्र में उनके वर्तमान विनिर्माण कियाकलापों में फस्फोरस व्युत्पन्नों जैसे फास्फोरस पेंटासल्फाइड, रेड फास्फोरस, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, फास्फोरिक एसिड (टेक्निकल तथा खाद्य श्रेणियाँ) इत्यादि सम्मिलित हैं । उनके द्वारा 1993 के मध्य में फास्फोरस का विनिर्माण बन्द कर दिया गया है । 1970 तक वे वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को सफेद/पीले फास्फोरस के मुख्य आपूर्तिकर्ता थे । मध्य 1993 में उत्पादन बन्द डोने तक उनका सफेद/पीले फास्फोरस का बाजार शेयर लगमग 80% था । वास्तव में जब तक (1980 के आसपास) यू.पी.एल. ने सफेद/पीले फास्फोरस का उत्पादन स्वय शुरू नहीं किया, वे उनको उनकी सफेद/पीले फास्फोरस की आवश्यकताओं की आपूर्ति कर रहे थे ।
- (ii) प्रतिकूल घरेलू उत्पादन लागत विशेषकर विद्युत की तेज कीमतो के कारण तथा साथ-साथ चीन से सस्ते आयात उपलब्ध होने से इसने यू पी.एल. को 1996-97 से सफेंद/पीले फासफोरस के उत्पादन को बन्द करने के लिए विवश कर दिया । इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि यू पी.एल के इतिहास में वे कभी भी वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को सफेंद/पीले फासफोरस के सिकंय आपूर्तिकर्ता नहीं थे तथा यू पी एल. द्वारा वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को नगण्य मात्रा में विकय किया गया । एक्सेल ने 1972 के आसपास समस्त सफेंद/पीले फास्फोरस का विनिर्माण अपने कैप्टिव आवश्यकताओं के लिए आरंभ किया । अव्यवहार्य लागतों के कारण 1996-97 से उन्होंने भी सफेंद/पीले फास्फोरस का उत्पादन बन्द कर दिया और वे भी सफेंद/पीले फास्फोरस के बड़े आयातकों में से एक हैं । पी.ए.सी.टी ने सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता हेतु 1000 मी टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक छोटा संयंत्र केरल मे लगाया । लेकिन विद्युत कटौतियों तथा अभिकं समस्याओं के कारण उनका सचालन सदा ही अनियमित रहा है । उनकी दो सहयोगी कम्पनियों कल्पतरू केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मजेन्था केमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड के माध्यम से लाल फास्फोरस के उत्पादन में सफेंद/पीले फास्फोरस की उन्हें कैप्टिव आवश्यकता है । उन्होंने भी सफेंद/पीले फास्फोरस का उत्पादन बन्द कर दिया है ।
- (iii) 1993 के मध्य तक एक सफेद/पीले फास्फोरस सयत्र के सचालन के उनके अनुभव तथा विभिन्न निवेशों के वर्तमान कीमत के स्तर के आकड़ों के आधार पर, एस सी आई एल. तथा पी ए सी टी जो सस्ती विद्युत पर कार्य करता है, के लिए सफेद/पीले फास्फोरस की आकंजित उत्पादन लागत लगभग 60/-फ़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। रॉक फासफेट जो कि सफेद/ पीले फास्फोरस उत्पादन के लिए एक मुख्य कच्चा माल है, के स्त्रांतों के

कारण कीमत और भी कम हो सकती हैं। जब नार्च 2000 से उत्पादन 5000 दन प्रति वर्ष तक बढ़ जाएगा और तदनन्तर अवस्था में जैसा कि एस.सी.आई एल द्वारा योजना बनाई गई हैं, जब उत्पादन 10000 दन प्रति वर्ष तक बढ़ जाएगा, तब लागत और भी बहुत कम हो जाएगी। विनिर्माण करने वाले संयंत्र काफी पुराने हैं, लगभग दो दशकों से सचाजन में हैं, पूरी तरह उनका अवमृत्यन हो चुका है और इसलिए कुल निर्धारित लागत पर्याप्त मात्रा में कम होगी।

- (V) यू पी एल./एस.सी आई.एल द्वारा रक्षोपाय शुल्क के लिए आवेदन अवसरवादी है और ऐसे समय में किया गया है जिससे प्रयोगकर्ता उद्योगों के लिए अपूरणीय तथा अन्यायपूर्ण क्षति उत्पन्न होगी । इसके अतिरिक्त इस उदेश्य के साथ कि क्लोरोअल्कली उत्पादों की मन्द बाजार परिस्थितियों (अधिक क्षमता के कारण) तथा अतिरिक्त कैप्टिंव विद्युत संयंत्र क्षमता के कारण एस सी आई एल को हुए भारी नुकसानों को समाप्त किया जा सके, इसके साथ एस सी आई एल. को इसके कारण अनुवित लाम मिल सके।
- (V) यह डर हैं कि जबकि यू.पी एल./एस.सी.आई एल. अपने फास्फोरस व्युत्पन्नों तथा कीटनाशकों के निर्यातों के विरूद्ध सफेट/पीले फास्फोरस के शुल्क मुक्त आयातों का लाम उठाते रहेंगे, फास्फोरस आधारित व्युत्पन्नों को विनिर्मित करने वाले उनके प्रतिस्पर्धियों को ऊँची कीमतों पर फास्फोरस लेने के लिए बाध्य होना पड़िंगा जो रक्षोपाय शुल्क, यदि कोई हो, के अधिरोपण के कारण संचालनों को अव्यवहार्य बना देगा।

# (क.6) घर्दा केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई.400 050

फास्फीरस (सफेद/पीला) की कीमत 900 से 1050 अमरीकी डालर प्रति मी.टन के आस पास रही है। यह प्रतिरूप पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। डालर के मुकाबले रूपया कमजोर होने से, पहले जो घटित हो रहा था उसकी तुलना में, भारतीय आयातक आयातित वस्तु के लिए वास्तव में अधिक कीमत दे रहे हैं।वर्तमान में पीले फास्फीरस का अयात मूल्य जो 43/- रू प्रति किलो निकलता है, के विरूद्ध 20/- रू प्रति किलो के वर्तमान सीमा शुल्क के विरूद्ध 50/- रू. के रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण एकदम असगत तथा अनुचित है विशेषकर तब, जब फास्फोरस की विश्वव्यापी कीमत 1000 अमरीकी डालर प्रति टन से अधिक नहीं है।

- (क.7) मैसर्स एस.टी एस केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई, मैसर्स सबीरो आर्गेनिक्स गुजरात लिमिटेड, मुम्बई, मैसर्स वाट्सल आर्गेनिक्स लिमिटेड हैदराबाद, मैसर्स स्टार केमिकल्स (बम्बई) लिमिटेड, मुम्बई ने भी उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित समान निवेदन प्रस्तुत किये हैं .-
- (i) आवेदकों द्वारा उनके आवेदन में दावा की गई मारतीय विनिर्माताओं की पीने फासफोरस की उत्पादन क्षमता गुमराह करने वाली है जैसा एक्सेल द्वारा माना गया है कि 1996 से पीने फासफोरस का विनिर्माण बन्द किया हुआ है और उन्होंने विनिर्माण फिर से शुरू करने की इच्छा के विषय में भी नहीं कहा है । इसलिए वास्तव में प्रमावित उत्पादन क्षमता 6000 मी टन के स्तर पर है। निम्नलिखित तथ्यों के सदर्भ में घरेलू बाजार में उत्पादन की उपलब्ध प्रमावित क्षमता को आकने के लिए पिरकल्पित उत्पादन क्षमता को जावने की आवश्यकता है । यू.पी एल तथा पी ए सी टी दोनों की वर्तमान क्षमताए मुख्यत उनकी सहयोगी इकाइयों की आवश्यकताओं की आपूर्ति करती है ।

- (ii) यू.पी एल./एस.सी.आई.एल. को पी सी एल. 3, पी 2 एस 5 तथा उनके अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए कम से कम 5000 मी.टन पीले फास्फोरस की आवश्यकता है । ऐतिहासिक तौर पर यू.पी.एल. मारत में पीले फास्फोरस का बड़ा आयातक था और है । यह सिद्ध करता है कि उन परिस्थितियों में भी जहाँ विनिर्माण सुविधाएँ पूरी तरह कार्यरत थीं, वे यू.पी.एल. की आवश्यकताओं को पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं । परिणामस्वरूप स्थानीय बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वास्तविक सामर्थ्य म्रामक है । जहाँ स्थानीय बाजार में लघु मात्राएँ, यदि कोई हों, दी गई है तो पूर्व सचालन के आधार पर यह स्थित अविवादित हैं।
- (iii) पूर्व में, स्थानीय बाजार में उत्पाद देने की अनिच्छा/ असमर्थता, यूपी एल./ एस.सी आई एल के बीच कुछ संविदात्मक तथा व्यापार व्यवस्थाओं से और अधिक बढ़ गई । दूसरी वस्तुओं के साथ एस.सी आई एल. के 26.2.99 के पब्लिक ईश्यू की विवरणिका से यह प्रतीत होता है कि अपने सभी खरीदने वालों में से एस.सी आई.एल., यूपी एल की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देगा और जहाँ तक संमव होगा जब वे अन्य खरीददारों को पूरी मात्रा की आपूर्ति करने में असमर्थ होंगे, सबसे पहले यूपी.एल. की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयास करेगे । यह तब तक रहेगा जब तक कम्पनी किसी मी कानून अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित लाइसेंस अथवा परमिट की शर्तों का उल्लंघन नहीं करती अथवा यूपी एल का इस प्रकार की प्राथमिकता देने के कारण कम्पनी को कोई नुकसान नहीं होता । इस अनुबन्ध के प्रचलन अवधि में कम्पनी ने माना है कि यूपी एल. को फास्फोरस द्राइक्लोराइड की आपूर्ति, उनको जितनी भी मात्रा की आवश्यकता होगी, प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में, आपस में निर्धारित की गयी कीमत पर, जिस कीमत में केन्द्रीय उत्पाद शुक्क, बिकी कर इयादि सम्मिलित है, और जो वर्तमान में 30,000 रूपये प्रति मी.टन निर्धारित किया गया है, की आपूर्ति करेगा । यह सुझाते हुए कि फास्फोरस का विनिर्माण अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, एस सी आई एल की वर्ष 1998-99 की सालाना रिपोर्ट भी कहती है कि कम्पनी तात्विक फास्फोरस के विनिर्माण के लिए एक सयत्र भी स्थापित कर रही है, जो कि कम्पनी का एक मुख्य निवेश (इन्पुट) है ।
- (iV) केरल में विद्युत की अनिश्चित उपलब्धता से पी ए सी दी की प्रभावी उत्पादन अमता बुरी तरह प्रभावित हुई है । इसकी सहयोगी/ सम्बद्ध कम्पनियो जैसे कि श्री मजेन्या केमिकल्स प्राइदेव लिमिटेड तथा कल्पतरू किमिकल्स प्राइदेव लिमिटेड तथा कल्पतरू किमिकल्स प्राइदेव लिमिटेड की कैप्टिव उपमीग आवश्यकताओं द्वारो स्थानीय बाजार में इसकी वस्तुएं देने की साम्थ्य को भी परिसीमित कर दिया गया है ।
- ें भारत में पीले कास्फोरस की 18 000 मी.टन की माग है । भारतीय विनिर्माताओं की प्रमावी विनिर्माण क्षमता केवल 3000 मी टन हैं, जो कि मुख्यत कैप्टिंव खपत के लिए हैं । स्थानीय बाजार की पूर्ति करने के लिए मारतीय विनिर्माताओं की प्रमावी सामर्थ्य अनिस्थित तथा अनिर्धारित है और ज्यादा से ज्यादा यह बढ़ती माग का कुछ प्रतिशत ही पूरों कर सकती हैं । भरत में पीले फास्फोरस की माग और पूर्ति में अत्याधिक तथा अपूर्णीय दूरी है जिसके कारण बड़ी सख्या में पीले फास्फोरस का आयात अपरिहार्य है । और फिर आवेदको द्वारा रखाकित योजनाए थाई समय में इस अन्तर की दूर करने की उनकी समर्थता/अभिकृति नहीं दशांती ।
- (vi) मारत में अनुप्रवाही प्रयोगकर्ता उद्योग अन्य के साथ-साथ आर्गेनो-फास्फोरस कीटनाशक, उर्वरक तथा माचिस उद्योग जो आज उत्पादन, विकय, राजस्व योगदान, निर्यात आय तथा रोजगार के लिए गिने जाते हैं घरेलू उत्पादक आवेदकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक आकड़ों से अवश्य ही 10 से 15 गुना बड़े हैं। आवेदक कम्पनियों द्वारा उत्पादन का प्रवाह अनिश्चित तथा अनियमित हैं। उत्पाद का मूल्य निर्धारण अप्रतिस्पर्धात्मक हैं। किसी भी प्रकार

का रक्षोपाय शुन्क अधिरोपण, सीधे ही ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जहां अनुप्रवाही उद्योग पूरी तरह से अनियमित आपूर्ति स्त्रोंतों पर निर्मर हो जाएंगे तथा शुन्क से बोझिल हो जाएंगे जो उनके उत्पादों को अप्रतिस्पर्धात्मक तथा न बिकने लायक बना देगा ।

- (vii) यह दावा किया गया है कि पीले फास्फोरस के सस्ते आयातों के कारण एस सी.आई.एल को अपना संयंत्र चलाना किया गया है है। पिछले कुछ वर्षों से एस.सी.आई एल बहुत ज्यादा नुकसान उठा रही है। इस विषय में यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि 200 करोड़ लागत वाले 50 मेगावाट के स्वतंत्र विद्युत संयंत्र की स्थापना से एस.सी आई एल. के वित्तीय सकट शुरू हो गए। आवेदक यह बताने में विफल रहे हैं कि स्वतंत्र विद्युत संयंत्र को कास्टिक क्लोराइन संयंत्र को विद्युत देने के लिए तथ्या अतिरिक्त विद्युत गुजरात विद्युत बोर्ड को देने की इच्छा से स्थापित किया गया था। एस.सी आई एल के दुर्भाग्य से उनके कास्टिक क्लोराइन संयंत्र में कठिनाई उत्पन्न हो गयी और फिर, विद्युत नीति बदल गई और इस प्रकार, वह केवल 40% क्षमता के संचालन वाले विद्युत संयंत्र के मरोसे रह गये तथा 1996-97 में इसका 5 करोड़ रू करों के बाद लाम के निम्न स्तर से 1998-99 में 49 करोड़ की हानि पर नीचे आ गया। एस सी आई एल की हानियों की दूर करने के लिए यू. पी. एल. को अपनी पीले फास्फोरस की सुविधाओं को स्थानांतरित करना पड़ा। उच्च अवमूल्यन तथा वित्तीय लागतों से विद्युत संयंत्र की निम्न उपयोग क्षमता और अधिक प्रमावित हो गई साथ ही साथ क्लोर-अल्कली उद्योग की परेशानियाँ भी एस.सी आई एल. के एक बीमार कम्पनी होने का कारण हैं तथा पीले फास्फोरस के नये स्थापित संयंत्र की फायदे में चलाने की कठिनाई का कारण पीले फास्फोरस के आयातों को नहीं माना जाना चाहिए। बल्कि एस.सी.आई.एल. के विद्युत उत्पादन तथा कास्टिक क्लोराइन विनिर्माण के असफल थावे की माना जाना चाहिए।
- (VIII) इसके अतिरिक्त यू.पी एल. द्वारा एस सी आई एल को विद्युत आधारित पीले फास्फोरस विनिर्माण सुविधा का स्थानातरण इस दृष्टि से था कि वह अपने मूल उत्पाद अर्थात पी सी एल 3, पी 2 एस 5 के लिए कच्चे माल के रूप में कैप्टिव तरीके से उपमोग के लिए पीले फास्फोरस का उत्पादन कर सके। यू.पी.एल द्वारा किया गया यह आवेदन पी सी एल 3, पी 2 एस 5 के अन्य घरेलू निर्माताओं के ऊपर वितीय बढत को सुनिश्चित करने के साथ-साथ पीला फास्फोरस बाजार को अपने लाम के लिए नियंत्रित करना मी था।
- (ix) पूरी रक्षोपाय कार्यवाही उत्पाद से सबधित हैं । विभिन्न अन्य उत्पादों या आवंदाकों के अन्य विभिन्न कियाकलापों के बारे में सूचना ने मुख्य मुद्दौं को धुधला कर दिया है और यह विचाराधीन मुद्दों हें तु सगत नहीं हैं । चूकि उद्ग्रहण एक उत्पाद के लिए मागा गया है, तो उस विशिष्ट उत्पाद से सबधित संगत सूचना उपलब्ध कराना आवंदाकों का दायित्व हैं । यू.पी.एल ने 1996 में पीले पास्फोरस का उत्पादन स्थिगित कर दिया था और केवल हाल में एस.सी.आई.एल ने पीले फास्फोरस का उत्पादन शुरू किया हैं । तथापि यू पी एल ने उस अवधि के होनि के आकड़ों को भी सदर्मित किया है जब पीला फास्फोरस निर्मित नहीं किया जा रहा था । उत्पाद के लिए संगत क्षति दर्शाने की जिम्मेदारी आवेदाकों की थी । यह प्रस्तुत किया गया है कि यू पी एल एक बहु उत्पाद कम्पनी है जिससे 50 से ऊपर उत्पाद सबद्ध है और जिसका दर्न ओवर 500 करोड़ रू० से अधिक है । पीला फास्फोरस उनके कुल व्यापार का लगभग 5% से 6% बैटता है । गत कुछ वर्षों को उनकों लेखा परीक्षा की गया वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने कही भी इस मुख्य तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि हानि पीले फास्फोरस के कारण हो रही है । वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों ने उल्लेख किया है कि लाम में 57 करोड़ से 32 करोड़ की गिरावट मुख्यत उच्च ब्याज लागत के कारण थी । इसमें पीले फास्फोरस का कही जिक नहीं है ।

- (x) आवेदकों ने पीले फास्फोरस के आयात के मुल्य नितान्त कम होने, एव पीले फास्फोरस के मारतीय विनिर्माताओं के उत्पादन की लागत आयातित पीले फास्फोरस के बिकी मूल्य से अधिक होने का मुद्दा हमेशा उदाया है । आवेदकों की पहली शिकायत कम मूल्य का आयात प्रतीत होती हैं, जिसके लिए उचित कार्यवाही रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं हैं, बल्कि एण्टी डिम्पेंग कार्यवाही हैं । इस संदर्भ में यह विश्वास किया जाता है कि आवेदकों ने एण्टी डिम्पेंग कार्यवाही शुक्त कराने की कोशिश की थी किन्तु सफल नहीं हुए । किसी भी परिस्थिति में, जबिक आवेदक स्वयं विशिष्ट आयातक हैं, वे एण्टी डिम्पेंग कार्यवाही से अयोग्य हैं । वर्तमान कार्यवाही इसलिए नहीं आरंभ की गयी है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु अपेक्षित अंशों को पूरा कर लिया गया है, बिल्क इस लिए आरंभ की गयी है कि उचित कार्यवाही शुक्त कराने में अयोग्य हो गये हैं ।
- (Xi) आदेदक यह उन्लेख करने में असफल रहे हैं कि बिजली की उच्च लागत के कारण यू.पी.एल ने अपना कार्य स्थागित कर दिया और यह तथ्य कि घरेंलू रूप में उत्पादित करने से पीले फास्फोरस का आयात करना अधिक लामकारी है। आवेदक यह भी उल्लेख करने में असफल रहे हैं कि पी ए.सी.टी. के साथ-साथ वे पीले फास्फोरस के बड़े आयातकों में से एक हैं।
- (Xii) आवेदक यह उल्लेख करने में असफल रहे हैं कि एक्सेल आवेदन करने में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि मिवष्य में पीले फास्फीरस का उत्पादन करने की उनकी कोई इच्छा नहीं हैं जैसाकि पीले फास्फीरस के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के विरूद्ध उनके विरोध पत्र से प्रमाणित होता है । दूसरे, आवेदकों ने यह भी उल्लेख करने से छोड़ दिया है कि पीले फास्फीरस के लगमग सम्पूर्ण उत्पादन का उपमोग उनकी सहायक/सबद्ध कम्पनियों द्वारा कैप्टिव रूप से कर लिया जाता है ।
- (Xiii) आवेदक एक असाधारण संरक्षण की माग कर रहे हैं और सटीक पारदर्शी रूप में सभी सगत तथ्यं प्रस्तुत करना उनकी अनिवार्य वैधानिक जिम्मेदारी हैं । उपरोक्त की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि आवेदक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असफल रहे हैं । इसके फलस्परूप यह आवेदन दोषपूर्ण हैं, और कार्रवाई योग्य नहीं हैं ।
- (XIV) रक्षोपाय शुल्क के अनुबंध के अनुसार, गमीर क्षित को जानने हेतु संबंधित उत्पाद अधिक वर्धित मात्रा में आयातित होना चाहिए । इसलिए यह पर्याप्त नहीं हैं कि मात्रा में कुछ वृद्धि हुई । मात्रा में वृद्धि जो अपेक्षित हैं वह यह कि यह "महत्वपूर्ण" हो । क्या आयात के बाजार शेयर के प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई है, इसका पता लगाने हेतु जिन कारकों के कारण आयात हुआ उन कारकों के सदर्भ में इन मुद्दों का परीक्षण किया जाना भी अपेक्षित है । यदि आयात का कारण यह है कि घरेलू बाजार में इसकी माग, घरेलू उद्योग की अक्षमता की वजह से हैं तो इस प्रकार के आयात को क्षित पहुँचाने वाला नहीं माना जा सकता है ।
- (xv) रक्षोपाय के सदर्भ में "गम्मीर क्षित "अपेक्षित है, जो "सामग्री क्षित " से मित्र है जो एण्टी डिम्पिंग जांच में निर्देशिवन्ह है । समझौते के अधीन यह टीक है कि शुक्क उद्ग्रहण को तर्कसंगत सिद्ध करने के लिए आयात के कारण घरेलू उद्योगों को कुल मिलाकर महत्वपूर्ण अपूर्णीय क्षित होनी चाहिए । न्यायिक व्याख्या एवं पूर्व उदाहरण में अपेक्षित है कि कोई भी "महत्वपूर्ण " शब्द के प्रयोग को अनदेखा या हटा नहीं सकता । अपेक्षित की अवसीमा अन्य कार्रवाइयों के मामलों की तुलना में अधिक है । यह देखा जाना है कि क्या इस मामले में "गम्मीर क्षित " का कारक पूरा है या नहीं । इस पृष्टभूमि में, सीमा शुक्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुक्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 (रक्षोपाय नियमावली ) के अनुलग्नक, समझौते में कहीं गयी बातों का

परावर्तकं हैं । और उन कुछ मानदण्डों की पहचान करता है जिन से हमें निर्देशित होना चाहिए कि क्षित हुई है या नहीं । यह प्रस्तुत किया गया है कि यह उन सभी पहचाने गये कारकों का संगम है जिस पर यह जानने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि "गम्मीर क्षित हुई है या नहीं हुई है "। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल कुछ पहचान वाले कारकों पर गंभीर क्षित का पता लगाना अपोषणीय होगा । वर्तमान मामले में चूँकि आवेदकों ने (क) कुछ स्तरों पर स्वैच्छिक रूप से निर्माण बंद कर दिया (ख) कैप्टिव उपमोग हेतु प्राथमिक रूप मे निर्माण किया जिसकी मांग निरतर है, (ग) घरेलू बाजार में प्रस्तुत करने हेतु उनके पास पीले फास्फोरस की सीमित मात्रा है, उनके पास क्षित का दावा करने के लिए पोषणीय आधार नहीं है ।

(XVI) आवेदकों ने दावा किया है कि पीले फास्फोरस का सस्ता आयात इसके उत्पादन और बिकी में कमी का कारण है जिसके परिणामस्वरूप बहुत से घरेलू उत्पादकों ने या तो पीले फास्फोरस का उत्पादन स्थिति कर दिया है या सभी ने उसका उत्पादन बंद कर दिया है । यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों ने पूरे आवेदन में स्वय कहा है कि घरेलू उद्योग सस्ते आयात (सीमा शुल्क ड्यूटी में कमी के कारण) के साथ-साथ घरेलू बिजली की लागत में वृद्धि से प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुए हैं । स्थानीय विनिर्माता प्रतिस्पर्धी अतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर पीले फास्फोरस का विनिर्माण करने में सामान्यत. सफल नहीं हो सके हैं इसका मुख्य कारण घरेलू बिजली की उच्च लागत है जिसमें कि पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक वृद्धि तुई है और उत्पादन और बिकी में कमी और आवेदकों की क्षमताओं की शिथिलता को पीले फास्फोरस के आयात का कारण मानना उचित नहीं होगा। इस संबंध में यह नोट करना दिलचस्प है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति यूनिट विद्युत की घरेलू लागत निम्नानुसार थी -

वर्ष	बिजली ( फं. प्रति इकाई)
1994-95	2.51
1995-96	2.46
1996-97	3.22
1997-98	4 16
1998-99	4.69
1999-2000	4.90

(XVIII) रक्षोपाय नियमावली और समझौते के अधीन, मूल्यों में सिर्फ ह्रास ही अपेक्षित नहीं है बल्कि मूल्य में कमी और महत्वपूर्ण रूप से मूल्य में कमी अपेक्षित है । वर्तमान कार्यवाही में, कोई मी महत्वपूर्ण मूल्य की कमी नहीं है । एक स्थिति जहाँ कि मूल्य विश्व स्तर पर कम हो रहे है और मारत में मूल्य उन मूल्यों का केवल परावर्तक है, यह स्थिति मूल्य में कमी होने की नहीं है । मूल्य में कमी करने हेतु, उस बाजार में अन्दर तक प्रवेश करने के लिए बाजार में मूल्य को कम करने अर्थात पूर्व दिनांकित मूल्य लगाने के लिए सचेतन प्रयास की आवश्यकता है । जैसा कि आवेदन में प्रस्तुत किया गया है, 1994-99 की अवधि के दौरान यह नोट करने योग्य है कि किसी मी देश से मारत में पीले फास्फोरस के उतराई के समय के मूल्य अधिक या कम एक समान हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि उद्धत मूल्य सही और उचित मूल्य हैं, जो पूरे विश्व में लागू हैं ।

(xviii) **यह भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष** 1994-95 के दौरान, जबकि आयात के लिए दावा किए गए उतराई के समय की लागत तथा उत्पादन की लागत में अन्तर लगभग <sup>18</sup> रू. था, उस समय क्षति का कोई दावा नहीं

किया गया जबकि 1999 - 2000 में जहाँ यह अन्तर लगभग 10 रू. है , आवेदक महत्वपूर्ण क्षति का दावा कर रहे हैं ।

- (XIX) आवेदकों ने आरोप लगाया है कि पीले फास्फोरस के आयात के कारण वे अब घरेलू बाजार की 4% मांग को पूरा कर रहे हैं । यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय विनिर्माताओं की प्रमावी विनिर्माण क्षमता कंवल 6000 मी दन है, जो कि प्राथमिक रूप में कैप्टिव उपमोग के लिए हैं, इसलिए बाजार शेयर की कमी का प्रश्न नहीं उडता, क्योंकि आवेदकों के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए न क्षमता है और न ही अभिरूचि ।
- (XX) यू.पी.एल और एक्सेल, मारत को निर्यातित कुल पीले फास्फोरस के लगमग 70% के आयातक है। फिर भी ये आयात शुल्क मुक्त है, क्योंकि वे अग्रिम लाइसेंस के तहत हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि यू.पी एल. का पीले फास्फोरस के सबसे बड़े आयातकों में से एक होना दर्शाता है कि माँग की पूर्ति करने के साथ-साथ घरेलू उद्योग की कैप्टिव आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आयात आवश्यक हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है. यू.पी एल द्वारा किया गया यह आवेदन पी. सी एल 3, पी 2 एस 5 आदि जो इसके मुख्य उत्पाद है और जिनका कैप्टिव प्रयोग फास्फोरस बिल्डिंग ब्लाक पर पुन. मूल्य वर्धित कीटनाशक बांड को बनाने के लिए मी किया जाता है, के अन्य स्थानीय उत्पादकों के विरूद्ध वितीय बबत सुरक्षित करने के लिए उपकरण प्रतीत होता है।
- (xxi) आवेदन उल्लेख करता है कि 400 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति अपने रोजगार से विवेत हो गए हैं क्योंकि उन्हें दोबारा पुनर्नियुक्त किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पुनर्नियुक्ति बेरोजगारी के बराबर नहीं है। फिर भी यह नोट करना प्रासंगिक है कि कई हजार व्यक्ति फास्फोरस व्युत्पन्नों और कीटनाशकों के विनिर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष या परीक्ष रूप में नियुक्त किए गए है। हजारों के लिए बेरोजगारी की आशका है, तो क्या पीले फास्फोरस पर रक्षोपाय शुक्क का अधिरोपण होना चाहिए क्योंकि इससे हजारों लघु, मध्यम और बड़ी विनिर्माण इकाईया अव्यावहारिक हो जाएगी और इन उद्योगों में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप में कार्यरत व्यक्ति बेरोजगारी के कगार पर आ जाएँगे।
- (xxii) आवेदको ने दावा किया है कि एक अनन्तिम शुल्क लगाया जाए । यह प्रस्तुत किया गया है कि अनन्तिम शुल्क के उद्ग्रहण हेंतु आवेदको को "विषम परिस्थितियो " की विद्यमानता को सिद्ध करना होगा जो कि "गम्मीर क्षति" से भी अधिक उच्च आरंभिक अपेक्षा है । इसलिए, चूँकि आवेदक गम्भीर क्षति सिद्ध करने के करीब भी नहीं है, "विषम परिस्थितियों " की विद्यमानता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

## (ख) रसायन योज्य विनिर्माता

पीले फास्फोरस पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की स्थिति में, उनको आपूर्ति किए जा रहे फास्फोरस पेंटासल्फाइड के मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाएगी और इससे तेल उद्योग को तैयार रसायन योज्यों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । इससे वे प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगे और तेल उद्योग अपने रसायन योज्यों को आयात के माध्यम से प्राप्त करेगा जो कि देश के विदेशी मुद्रा भड़ार को प्रभावित करेगा ।

## (ग) औषघ मध्यवर्ती विनिर्माता

वे फास्फोरस व्युत्पन्नो जैसे फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस पेन्टोक्साइड को घरेलू विनिर्माताओ

से प्राप्त करते हैं। सफेद/पीले फास्फोरस पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण से फास्फोरस व्युत्पन्नों की और उनकें तैयार उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी जो उन्हें घरेलू बाजार के साथ निर्यात बाजार में भी अप्रतिस्पर्धी बना देगा ।

## (ग.1) मै. रैन्कल केमिकल्स (इंडिया ) लि.

इसके अतिरिक्त, मैं. रेन्कल केमिकल्स (इंडिया) लि. नई मुम्बई ने उल्लेख किया हैं कि विश्व बाजार में आपूर्ति किए जाने वाले फास्फोरस का 90% चीन से, उनके बहुत कम लागत बांचे की वजह से, हो रहा है। विश्व में प्रत्येक देश ने इस तथ्य को स्वीकार किया है और इस बात से सतुष्ट हैं कि विश्व में चीन इस उत्पाद का सबसे कुशल उत्पादक हैं। इन परिस्थितियों के अधीन, प्रत्येक घरेलू उत्पादक की लागत प्रतिस्पर्धी होना आवश्यक हैं और अपनी विनिर्माण दक्षता के जिरए चीन से आयात के साथ प्रतिस्पर्धी करना होगा। दूसरी ओर, अतिरिक्त शुल्क लगाने से चीन से आयात को नियन्त्रित करने से केवल अकुशल भारतीय उत्पादकों को ही संरक्षण मिलेगा जो कि डब्ल्यू टी.ओ. के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है और इसलिए यूनाइटेड फास्फोरस और इसकी सहायक कम्पनियों के द्वारा किया गया यह आवेदन निरस्त कर देना चाहिए।

## (घ) लाल फास्फोरस विनिर्माता

सफेद/पीले फास्फोरस के विनिर्माता एकाधिकारवादी है जो कि कुछ चुनिदा घरानों द्वारा चलाया जा रहा है जो कि नियमित कीमतें कायम नहीं रख सके। इसके अलावा उनकी आपूर्ति मो नियमित नहीं थीं । उनके द्वारा कीमतें प्राय बढ़ाई गई अर्थात् मई 89 में 59 रू. प्रति कि.ग्रा. अक्टूबर 89 में 69 रू. प्रति कि ग्रा. जुलाई 90 में 80 रू प्रति कि.ग्रा., जनवरी 91 में 90 रू. प्रति कि.ग्रा. और मई 92 में 95 रू प्रति कि ग्रा. । यदि उन्हें घरेलू उत्पादकों से सफेद/पीला फास्फोरस खरीदना पड़ेगा तो वे लाल फास्फोरस की कीमते 20% तक बढ़ा सकते हैं । जो कि माचिस उद्योग को प्रतिकूल रूप में प्रमावित करेगा जो पहले से ही रुग्ण है ।

# (घ) निर्यातक/ निर्यातक सरकारों के दृष्टिकोण

## 11.(क) रिपब्लिक आफ बल्गारिया उच्चायोग, नई दिल्ली

बल्गारिया से केवल 55 मी. टन का आयात 1994-95 के दौरान हुआ और उसके प्रश्वात बल्गारिया से किसी भी आयात को दर्ज नहीं किया गया है । बल्गारिया के सरकारी साख्यिकीय आकड़ों के अनुसार कैलेन्डर वर्ष 1994 के दौरान 119.600 मी. टन मात्रा का फास्फोरस बल्गारिया से मारत में पुनर्निर्यात किया गया था । 1995-96 के बाद से बल्गारिया ने न तो सफेद/पीले फास्फोरस का उत्पादन किया है और न ही निर्यात किया है, और उसकी अपनी जरूरते आयात के जरिए पूरी की जा रही हैं ।

## (ख) मर्क के जी ए ए - डर्मस्टेड्ट, जर्मनी

उन्होंने उल्लेख किया है कि सफेद/पीला फास्फोरस उनके बिकी कार्यकम में नहीं है और यह भारत को निर्यात नहीं किया जाता है ।

## (ग) चीन से निर्यातक

- (i) वे आवेदक मैं यू.पी.एल. सिंहत भारत में मुख्य आयातकों को पीले फास्फोरस का निरन्तर निर्यात छरते हैं। किसी भी मामले में उन्होंने पश्चिमी एवं पूर्व यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व, आस्ट्रेलिया आदि में उनके फास्फोरस के खरीदारों से कम कीमत पर भारतीय आयातकों को पीले फास्फोरस को नहीं बेचा है चीन से पीले फास्फोरस के सभी निर्यात चीन से रसायन उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुझप्त और नियन्त्रित निर्यात कोटा द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। निर्यात के एक न्यून मूल्य को लागू किया गया है और यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो वह अपना निर्यात कोटा एक वर्ष या अधिक समय के लिए गवा देता है।
- (ii) 16 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के मूल्य का 16000 मी. टन प्रतिवर्ष के पीले फास्फोरस का भारतीय आयात, 160000 मी. टन प्रतिवर्ष से अधिक के चीन के उत्पादन का केवल एक छोटा हिस्सा है, जिसका मुख्य अंश चीन में कृषि रसायन और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न फैक्ट्रियों द्वारा उपमीग कर लिया जाता है । चीन बहुत बड़ी मात्रा ई ई सी देशों, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका आदि को निर्यात करता है । इसलिए चीन के उत्पादकों द्वारा भारतीय बाजार में इतनी कम मात्रा को, कम कीमत पर फास्फोरस बेचने का कोई तात्पर्य नहीं है जबकि अन्य उच्च मात्रा वाले देशों को ऐसा करने से उन्हें अधिक लाम होगा । इसके अलावा चीन सरकार द्वारा उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाएगा जो कि सभी निर्यातों को सख्ती से मानीटर करता है ।
- (iii) किसी भी देश द्वारा, जहाँ कि मारत की तुलना में व्यापार मात्रा/ क्षिति के आसार बहुत अधिक हैं, चीन के पीले फास्फोरस पर रक्षोपाय शुल्क या एण्टी डिम्पिंग शुल्क नहीं लगाया गया हैं। किसी एक विनिर्माता के हित के लिए पूरे देश के 16 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष के आयात पर किसी रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण अप्रतिस्पर्धी, एकाधिकारवादी है, और अन्य अनुप्रवाह मारतीय उद्योग के हितों के विरुद्ध है।
- (IV) चीन के पीले फास्फोरस उत्पादन की आर्थिक सफलता के लिए मुख्य कारण चीन में बड़ी क्षमता वाली फैक्टिरियाँ (100) हैं जो भारत की इकाइयों की तुलना में अधिक बड़ी क्षमता पर परिचालित की जाती है। बिजली की दरें कम हैं और खान एवं परिवहन के क्षेत्रों में अम लागत कम हैं, उच्च अेणी के राक फास्फेट (पी 2 ओ 5:33-37% कान्टेंट) का उच्च प्रमाणित संचय है जो कि भारतीय राक फास्फेट से बेहतर पैदावार/ परिवर्तन अनुपात प्रदान करता है।
- (V) यदि एस.सी आई.एल / यू.पी.एल. दोनों अपनी क्षमता को दुगुना बढ़ाकर 4000 मी टन प्रतिवर्ष तक भी कर लेते हैं तो भी शेष 12000 मी टन प्रतिवर्ष की वर्तमान मांग आयात से ही पूरी की जानी है । इस प्रकार के आयात को यदि 50% या अन्य किसी दर से रक्षोपाय शुक्क के जरिए महमा किया जाएगा तो वह भारत में पीले फास्फोरस के अनुप्रवाह उपमोक्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को गंभीर रूप में क्षतिग्रस्त करेगा और उन सभी को जोखिम और क्षति में डाल देगा ।
- (VI) रक्षोपाय शुल्क कैंग माग कर रहें एक विनिर्माता के जोखिम/लाम. 10 से अधिक मारतीय फास्फोरस तथा फास्फोरस मध्यवर्तियों के उपमोक्ता उद्योग और लाखों मारतीय किसानों, जो कीटनाशक निवेशों के लिए अधिक अदायगी करेंगे, के जोखिम/उच्च लागत से बहुत कम हैं। मारतीय कीटनाशकों के उपमोग में, मूल्य तथा मात्रा दोनों दृष्टि से, पीले फास्फोरस पर आधारित कीटनाशकों का माग्र महत्वपूर्ण हैं।

(vii) मैसर्स युनाइटेंड फास्फोरस लिमेटेड (यूपी.एल.) के ट्राईमिथाइल फास्फाइट (टी.एम.पी.) के नये सयंत्र में बढ़े हुए उपमोग तथा भारत से फास्फोरस आधारित उत्पादों जैसे कि टी.एम पी., एल्यूमिनियम तथा जिंक फास्फाइड्स इत्यादि के उन्नत निर्यातों के कारण पीले फास्फोरस के आयातों में वृद्धि हुई। इस प्रकार के आयातों के मुख्य लाम पाने वाले स्वयं मैसर्स यूपी एल. थे जिन्होंने टी.एम.पी. इत्यादि का निर्यात पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया और मारत के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित की। पीले फास्फोरस के चीन के निर्यातको द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक तथा समय पर आपूर्ति ने मैसर्स यूपी.एल. को बिना किसी क्षति के निर्यात में सफलता को अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया।

(Viii) रॉक फास्फेट का आयात भी बिना किसी रक्षोपाय शुल्क सरक्षण के, भारत में यहाँ तक कि स्टेट माइनिंग डेवलपमैंट कार्पोरेशन द्वारा भी किया जाता है क्योंकि यह कृषि में प्रयोग होने वाले उर्वरक के लिए प्रमुख कच्चा माल है। यही नीति पीले फास्फोरस के लिए लागू की जानी चाहिए जो कि कृषि रसायनों, लुबरीकैंट्स, जन-स्वास्थ्य क्षेत्रों इत्यादि से संबंधित फास्फोरस आधारित उद्योगों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। सल्फ्यूरिक एसिड विनिर्माताओं के लिए सल्फर की तरह ही पीले फास्फोरस के आयात को बिना किसी बाधा, आयात अतिमार, या अन्य पक्षपात अथवा रक्षोपाय शुल्क, जो डब्ल्यू.टी.ओ नियमो/अनुबन्धों के समान हों, स्वतन्न अनुमति होनी चाहिए।

## (ड.) संगठनों के दृष्टिकोण

## 12(क) मैच मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशस

भारत में माविस विनिर्माण के कई सगडन हैं। उनमें से कुछ ने उल्लेख किया है कि उनके सदस्यों में से अनेक हाथ से माविस का विनिर्माण करने वाले हैं जो कि लाखों मजदूरों को रोजगार दंते हैं और माविस के उत्पादन के लिए लाल फास्फोरस की बड़ी मात्रा का उपमीग करते हैं जो कि कच्चे माल की उच्च लागत में वृद्धि को नियन्त्रित करने की उनकी अक्षमता के कारण बड़ी प्रतिस्पर्धा में खड़े होने हेंटु अस्क्षम है। सफंद फास्फोरस के आयात के कारण वे लाल फास्फोरस लगातार प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर प्राप्त कर रहे हैं। यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो यह निश्चित रूप से सफेद फास्फोरस की कोमत 50% ज प्रति किलो तथा लाल फास्फोरस की कीमत 60% प्रति किलो से अधिक बढ़ा देगा। यह वृद्धि (40%) बहुत ही अधिक होगी जिससे हस्त निर्मित माविस उद्योग जो लाखो मजदूरों को रोजगार देता है, गमीर रूप से प्रमावित होगा। रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण सफेद फास्फोरस के स्वतन्त्र प्रवाह को प्रमावित करेगा तथा कृत्रिम अमाव उत्पन्न करंगा और सफेद फास्फोरस के व्यापार को एकाधिकारवादी बनने में मदद करेगा जिसके परिणामस्वरूप कच्चे माल का अमाव पैदा होगा तथा परिणामस्वरूप माविस ईकाइयाँ बन्द हो सकती हैं।

कुछ अन्य ने रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का यह सुझाते हुए सख्ती से समर्थन किया है कि पीले फास्फोरस के घरेलू उद्योग की विद्यमानता इसलिए जरूरी है जिससे वह पीले फास्फोरस की उपलब्धना की सुनिश्चित करे, जो लाल फास्फोरस के लिए एक मूल कंच्या माल है जो सुरक्षा माचिस के विनिर्माण के लिए मुख्य संघटक है । पीले फास्फोरस की घरेलू खरीदारी के लिए अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि सफेद/पीले फास्फोरस के आयात पर निर्मरता को कम किया जा सके और इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की काफी बचत हो सकेगी।

## (ख) पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन आफं इण्डिया, नई दिल्ली

- (i) यह संस्था 90 से अधिक कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका संयुक्त टर्न-ओवर भारत में कृषि रसायन टर्न ओवर के 90% से अधिक हैं । उनमें कीटनाशक मध्यवर्तियों, कोटनाशक टेक्निकल तथा फार्मुलेशन के विनिर्माता सम्मिलित हैं । यह संस्था अनेक मारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों आयातकों तथा वितरकों, जो लघु , मध्यम तथा बड़े पैमाने से संबधित हैं, का भी प्रतिनिधित्व करती हैं । सस्था के निदेशकों के बोर्ड ने पीले फास्फोरस पर रक्षोपाय शुल्क के मामले पर 8.10 99 को चर्चा की और पीले फास्फोरस पर किसी भी प्रकार के रक्षोपाय शुल्क का विरोध करने का निश्चय किया क्योंकि यह भारतीय कीटनाशक उद्योग, जो पीले फास्फोरस से शुक्त होने वाले सभी अनुप्रवाही उत्पादों के विनिर्माण में लगे हुए हैं, के आम हितों के विपरीत हैं।
- (ii) विद्युत की उच्च लागत और राक फास्फेट की खराब गुणवत्ता के रूप में, जिंटल बॉचागत कमजं। रियों की दृष्टि से भारत में पीले फास्फोरस के उत्पादन को कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं बमाया जा सकता है । भारतीय फास्फोरस उद्योग द्वारा निकट भविष्य में कोई सकारात्मक समायोजन करने की किसी भी संभावना को देखने में वे असफल हैं ।

## (ग) इण्डियन क्राप प्रोटेक्शन एसोसिएशन

उपरोक्त के अतिरिक्त इण्डियन काप प्रोटेक्शन एसोसिएशन, मुम्बई ने उल्लेख किया है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण टेक्निकल कीटनाशकों के आयात को बढावा दें सकता है तथा परिणामस्वरूप घरेलू संयंत्र क्षमताओं के प्रयोग को और अधिक कम कर सकता है।

# (घ) इण्डियन केमिकल मैन्युफैक्वरर्स एसोसिएशन ( आई सी एम ए )

उन्होंने कहा है कि आई.सी एम ए. की ट्रेड एण्ड बिजनेस डेवलपमैंट एक्सपर्ट कमेटी ने फास्फोरस के उत्पादको तथा उपमोक्ताओ दोनों को 13 अकूबर, 1999 को अपने पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय में सफेट/पीले फास्फोरस के उपमोक्ताओं तथा उत्पादकों के दृष्टिकोण को समझने के लिए आमन्त्रित किया था । उपमोक्ताओं से चर्चा के दौरान यह प्रकट हुआ कि :

- (i) फास्फोरस की कुल माँग लगभग 15,000 17,000 मी टन फास्फोरस की है तथा माँग में वृद्धि 20% प्रतिवर्ष की दर से है और यह लगभग सभी कृषि रसायनों के लिए हैं । कीटनाशक मध्यवर्तियों की उत्पादन लागत की फास्फोरस की लागत लगभग 25% से 60% के बीच पड़ती हैं ।
- (ii) यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो मध्यवर्तियों की विनिर्माण लागत बढ जाएगी तथा टी.एम.पी तथा डी.ई.टी.सी.एल. जैसे उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन बन्द होकर आयात शुरू हो जाएगा । सर्च केम इण्डस्ट्रीज लि ( एस सी आई एल ) ने कमी भी अन्य उपमोक्ताओं को किसी भी मात्रा की बिकी नहीं की । रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण यू.पी.एल. जो फास्फोरस से कीटनाशक मध्यवर्तियों का विनिर्माण करते हैं, की तुलना में अन्य उपमोक्ताओं को लागत संबंधी नुकसान पहुँचाएगा ।

-≰`

(III) सर्च केंम की वर्तमान क्षमता मुश्किल से उनकी अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं को पुरा कर पायेगी और शेष उपमोक्ता अपनी आवश्यकता की पूरी मात्रा का आयात करते रहेंगे ।

फास्फोरस के उत्पादकों ( यूनाइटेड फास्फोरस लि तथा सर्च केम इण्डस्ट्रीज लि ) से चर्चा के दौरान यह प्रकट हुआ कि -

- (IV) फास्फोर्स की लागत की 70% लागत विद्युत की हैं । खरीदी गई विद्युत से उत्पादित समस्त फास्फोर्स अलामकारी है और इसलिए एक्सेल इण्डस्ट्रीज लि तथा स्टार केमिकल (बम्बई) लि ने अपने प्रत्येक 4000 टन तथा 1500 टन वाली सुविधाओं को बन्द कर दिया । सर्च केम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, अधिक मितव्ययी विद्युत की निश्चित उपलब्धता से, प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर फास्फोर्स का उत्पादन कर सकती है ।
- (V) जहाँ सर्च केम इण्डस्ट्रीज लि. 25,000 टन की अपनी वर्तमान क्षमता का स्वय ही उपमोग करती रहेगी, वहीं वे उद्योग के लिए 3000 टन अतिरिक्त उत्पादन करने में समर्थ होगे। वर्तमान लागत के आधार पर सर्च केम इण्डस्ट्रीज लि ने पुष्ट किया कि उपरोक्तानुसार अतिरिक्त उत्पादन के साथ इसकी उत्पादन लागत 115/-फ किलो की फास्फोरस की कीमत को न्यायसंगत डहराती है, कैप्टिव विद्युत संयत्र के सुधरे हुए भार कारक के कारण यह बेहतर रूप में भी 75/-फ प्रति किलो तक नीचे जाएगा। वर्तमान आयातित पीले फास्फोरस की कीमत 59/-फ प्रति किलोग्राम थी।
- (vi) संस्था ने महानिदेशक (रक्षोपाय) से सफंद/पीले फास्फ्रोरस पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उपरोक्त मदौ को ध्यान में रखते हुए करने हेतु एक व्यावहारिक निर्णय लेने का अनुरोध किया है ।

## (ड) सी-।।, अहमदाबाद

कीटनाशक के विस्तृत क्षेत्र के लिए सफेद/पीला फास्फोरस विस्तृत श्रेणी के कीटनाशक का एक आवश्यक बिल्डिंग ब्लाक है जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है तथा यह सुरक्षा क्षेत्र के लिए भी एक अनिवार्य आवश्यकता है। कृषि और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत को पीले फास्फोरस के मामले में आत्मनिर्भर रहना आवश्यक है। कारण चाहें जो कुछ भी हो, इसकी कमी उन क्षेत्रों के विकास में हानि पहुचाएगी जो जी.डी.पी. के बड़े भाग को प्रदान करते हैं और बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करते हैं।

# (चं) घरेलू उत्पादकों को कच्चा माल/ इन्पुट की आपूर्ति करने वालों के दृष्टिकोण

## 13(क) कोक सप्लायर्स

उन्होंने भारत में सफेद/पीले फास्फोरस के सभी विनिर्माताओं, जैसे युनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टार केमिकल्स, पी ए सी टी आदि को बड़ी मात्रा में धातुकर्मीय कोक की आपूर्ति पहले किया है। क्योंकि यह उद्योग उनका एक बड़ा तथा नियमित खरीददार उद्योग है, उनकी आपूर्तियाँ तथा

व्यापार पिछले 3 सालों से बहुत बुरी तरह प्रमावित हुए थे तब उन्होंने अपने सफेद/पीले फास्फोरस का उत्पादन रोक दिया । भारत में सफेद/पीले फास्फोरस के आयात पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करके स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा वे इस विषय में मैसर्स सर्च केम इंडस्ट्रीज लिमिटेड/युनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड द्वारा किए गए आवेदन का पूरी तरह समर्थन करते हैं ।

## (ख) दि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

(i) पूर्व में वे सफेद/पीले फास्फोरस के सभी घरेलू निर्माताओं को अपनी खदानों से बड़ी मात्रा में रॉक फास्फेट चिप्स की आपूर्ति करते थे । लगमग 1996 के अन्त में, मारत में सफेद पीले फास्फोरस के सस्ते आयातों के कारण इकाइयाँ बन्द होने तक, फास्फोरस उद्योग उनका बड़ी मात्रा का तथा नियमित उपमोक्ता था । इसने उनके व्यापार तथा खदान के संचालनों को प्रभावित किया जो अन्य छोटे उद्योगों की बहुत थोड़ी सी आवश्यकता को पूरा करने के अलावा लगमग बन्द हो चुका था। वे घरेलू उद्योग को रॉक फास्फेट की 40.000-50,000 मी.टन की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं और यह केवल तभी संभव होगा जब सफेद/पीले फास्फोरस का उत्यादन भारत में किया जाय । रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए वे आवेदकों का समर्थन करते हैं जो भारतीय रॉक फास्फेट खदान उद्योग को प्रोत्साहन देगा तथा पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

#### (ग) सावर मिनरल

1996 तक वे फास्फोरस उद्योग को सिलिका ग्रेवल के मुख्य आपूर्तिकर्ता थे। फास्फोरस संग्रंत्रों के बन्द होने के कारण उनका काम रुक गया है तथा उनको मारी नुकसान उद्याना पड़ा। उन्होंने भारत में फास्फोरस उद्योग को फिर से शुरू करने की इच्छा प्रकट की है ताकि वे अपनी खदानों को शुरू कर सकें तथा पिछड़े क्षेत्रों में अम के लिए रोजगार पैदा कर सके।

## (छ) निष्कर्ष

14 मैंने मामले के रिकार्ड तथा घरेलू उत्पादकों, प्रयोगकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, निर्यातक देशों तथा विभिन्न सगडनो आदि द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को ध्यान पूर्वक देखा है । विभिन्न पक्षों द्वारा किये गए निवेदनों तथा उनसे उड़े मुद्दों को नीचे दिये गए निष्कर्षों में ध्यान में रखा गया है।

## 15 जांच के अधीन उत्पाद

जाँच के अधीन उत्पाद सफेद/पीला फास्फोरस है । सफेद/पीलो फास्फोरस रसायन सूत्र पी 4 के साथ एक इनआर्गैनिक रसायन है । सफेद/पीले फास्फोरस के विनिर्माण की प्रक्रिया में, विद्युत मट्टी में सिलिका और कोक की उपस्थिति में रॉक फास्फेट का रूपान्तरण निहित है । सफेद/पीला फास्फोरस रंगहीन अथवा सफेद, पारदर्शी, किस्टल, दिखने में मोम की तरह और प्रकाश में गाढ़ें रंग का हो जाता है । यह वाष्प्रशील, प्रकाश में साधारण वापमान पर वैक्यूम में उत्कृष्ट हो जाता है । अन्धेर में हवा में खोलने पर यह हरे रंग से मिलता जुलता प्रकाश फैलाता है और सफेट धूआ घोड़ता है । सफेद/ पीले फास्फोरस का प्रयोग मध्यवातियों जैसे फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, लाल फास्फोरस, फास्फोरस पैन्टासल्याइड, एल्युमीनियम फास्फाइड तथा जिकफास्फाइड

के उत्पादन में किया जाता है । विभिन्न कृषि रसायनों के लिए यह एक बिल्डिंग ब्लाक है जो सुरक्षा आवश्यकताओं में प्रयोग किये जाने के अलावा कृषि क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है ।

सफेद/पीले फास्फोरंस को सीमा शुल्क टैरिफ अधिरियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 2804.70 तथा हार्मोनाइन्ड कमोडिटी डिस्किप्शन (आई.टी.सी) पर आधारित मारतीय व्यापार वर्गीकरण के 28047003 के अधीन वर्गीकृत किया गया है । सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा आई.टी.सी के अधीन सफेद/पीले फास्फोरंस के इस वर्गीकरण को सुविधा के लिए दर्शाया गया है तथा किसी प्रकार से जान के अधीन उत्पाद को सम्मिलित करने में रुकावट नहीं डालता है ।

इन निष्कर्षों में सफेद और/अथवा पीले फास्फोरस के लिए किसी मी संदर्भ को सफेद/पीले फास्फोरस को सम्मिलित करने के लिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समझा जाना चाहिए ।

## 16 घरेलू उद्योग

पीले फास्फोरस के उत्पादन के लिए क्षमता सृजित करने वाली भारत में पांच कम्पनियाँ हैं जैसे यू पी.एल., मुम्बई, पी.ए.सी.टी., कोचीन, एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई, स्टार केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई, तथा एस सी आई.एल. मुम्बई । रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का आवेदन पी.ए.सी.टी. द्वारा किया गया है तथा यू.पी.एल. द्वारा इसका समर्थन किया गया है, जिन्होंने अपने संयंत्र तथा क्षमता को एस.सी.आई.एल. को स्थानातरित कर दिया है । एक्सेल तथा स्टार ने याचिका का विरोध किया है तथा वे सफेद/पीले फास्फोरस पर किसी भी प्रकार के रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के विरुद्ध हैं ।

वर्तमान मामले में 1994-95 से 1998-99 की अवधि के दौरान पाँच कम्पनियों, जिन्होंने पीले फास्फोरस की उत्पादन क्षमता सुजित की थी. का उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से था :-

सारणी-1 घरेलू उद्योग का उत्पादन (मी. टन)

कम्पनी	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
यू पी एल.	2081	2973	1772	-	-	6826
एस सी आई एल	-	-	-		_	
पो.ए सी टी	800	911	393	465	612	3181
एक्सेल	1469	1800	1400	-	-	4669
स्टार	400	-	•	-	<u>-</u>	400
कुल	4750	5684	<b>356</b> 5	465	612	15078

नीचे की सारणी 2 पाँच कम्पनियों की उत्पादन क्षमता के आँकड़े प्रदर्शित करती है -

#### सारणी-2

## घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता (मी.टन)

कम्पनी	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
यू.पी.एल.	4500	5000	5000	5000	-
एस.सी.आई.एल	-	<u> </u>	_	-	5000
पी.ए.सी.टी.	1000	1000	1000	1000	1000
स्टार	1800	1800	-	-	-
एक्सेल	2500	2500	4000	4000	4000
कुल	9800	10300	10000	10000	10000

यह तर्क दिया गया है कि एस सी.आई.एल ने केवल 14 6 1999 से पीले फास्फोरस का उत्पादन आरंग किया है तथा पीला फास्फोरस विनिर्मित करने का उनका कोई पूर्व इतिहास नहीं है । अत. एस.सी.आई.एल. का इस मामले में कोई अधिकारिता नहीं है । इसी प्रकार सह-आवेदक यू.पी.एल , जिन्होंने सितम्बर, 1996 से फास्फोरस का उत्पादन पहले ही बन्द कर दिया है, जिसके कारण इस मामले में उनकी कोई अधिकारिता नहीं है । बहुत थोड़ी उत्पादन क्षमता के कारण पी.ए सी टी. का भी इस मामले में मुश्किल से कोई अधिकार है ।

उपरोक्त सारणी-1 से यह स्पष्ट हैं कि 1994-99 के दौरान घरेलू उद्योग ने पीले फास्फोरस का कुल 15076 मी.टन का उत्पादन किया है । 15076 मी.टन में से, आवेदको (यू.पी एल. सहित) द्वारा 10007 मी.टन तथा एक्सेल के साथ स्टार द्वारा शेष 5069 मी.टन का उत्पादन किया । गत दो वर्षों अर्थात 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान अकेले पी.ए.सी.टी. ने ही क्रमशः 465 मी.टन तथा 612 मी टन पीले फास्फोरस का उत्पादन किया । इस प्रकार उत्पादकों ने 1997-99 के दौरान न केवल सम्पूर्ण उत्पादन किया, बल्कि 1994-99 की अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन के एक बड़े माग का भी उत्पादन किया ।

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 बी परिभाषित करती है कि "घरेलू उद्योग " का अर्थ उन उत्पादको से है जो -

- (कं) पूरी तरह से सदृश वस्तु के अथवा मारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु के उत्पादक हो, अथवा
- (ख) जिनका सदृश वस्तु अथवा मारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु का सामूडिक उत्पादन, भारत में कथित वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता हो ।

जैसे कि ऊपर चर्चा की गई हैं, 1997-99 के दौरान आवेदकों ने पीले फास्फोरस की समूची मात्रा का ही केवल उत्पादन नहीं किया बल्कि 1994-99 के दौरान घरेलू उत्पादन के बड़े मांग का मी उत्पादन किया। अतः यह माना जाता है कि पीले फास्फोरस का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन किया गया है।

## (17) वर्धित आयात :

मारत में सफेद/पीले फास्फोरस का आयात बुल्गेरिया, चीन, चीनी ताइपी ( ताइवान ), हांग-कांग, जर्मनी, जापान, कोरिया डी पी आर, नीदरलैंड, यू.के. तथा यू.एस.ए. से किया जाता है ।

1994-95 तथा 1995-96 में पीले फास्फोरस ने मूल्यानुसार 50% सीमा शुल्क आकर्षित किया जो कम होकर 1996-97 में 30% और 1997-98 में और 1998-99 में 35% हो गया । इस समय पीला फास्फोरस 35%+10% (35% का) की दर से सीमा शुल्क आकर्षित करता है ।

आवेदकों ने दावा किया है कि पीले फास्फोरस का आयात 1994-95 में 5350 मी. टन, 1995-96 में 7493 मी. टन, 1996-97 में 8829 मी. टन, 1997-98 में 12391 मी. टन तथा 1998-99 में 16504 मी. टन का किया गया । जहाँ 1994-98 की अवधि के लिए पीले फास्फोरस के आयात के आँकड़े. ही.जी.सी.आई.एस आँकड़ो द्वारा समर्थित किए गए हैं, वहीं वर्ष 1998-99 के लिए ही जी.सी.आई एस. के आँकड़ अभी तक उपलब्ध नहीं हैं । तथापि आवेदन में वर्ष 1998-99 के लिए स्वयं आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आयात आँकड़ों पर आवेदकों में विवाद है तथा उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा पहले प्रस्तुत की गई सूचना, वास्तविक सूचना की अनुपस्थिति में, आँकलित आयात के आधार पर थी । अब उनको वर्ष 1998-99 के लिए ही.जी.सी.आई.एस. से आयात आँकड़े प्राप्त हो गए हैं जो 12388 मी. टन है । फिर मी उन्होंने पुनः उल्लेख किया है कि उन्होंने पीले फास्फोरस के आयातों के आँकड़ों को विभिन्न पक्षों द्वारा दी गई सूचना से एकत्र किया है जिसके आधार पर विभिन्न आयातकों/प्रयोगकर्ताओं द्वारा किया गया कुल आयात 13380 मी. टन होता है ।

फिर भी, आयात आँकड़ों का सत्यापन किया जाना था । आयातकों के पास उपलब्ध आयात विवरण, जिनका सत्यापन किया जाना था, से पता लगता है कि अकेले इन आयातकों ने 1998-99 में 14086.513 मी. टन पीले फास्फोरस का आयात किया । अत:, कुल आयात कम से कम 14086.513 मी. टन था । इसे 1998-99 का आयात मानते हुए, 1994-99 की अवधि के दौरान पीले फास्फोरस का जो घरेलू उत्पादन तथा आयात था, वह नीचे सारणी- 3 में दर्शाया गया है -

सारणी - 3 वर्धित आयात

वर्ष	घरेलू उत्पादन (मी.टन)	आयात (मी.टन)	घरेलू उत्पादन के % वे रूप में आयात
1994-95	4750	5350	112.6
1995-96	5 <b>684</b>	7493	131.8
1996-97	3565	8829	247.7
1997-98	<b>46</b> 5	12391	2264.7
1998-99	612	14086.5	2301.7

उपरोक्त सारणीबद्ध ऑकड़ों से यह देखा गया कि जो आयात 1994-95 में 5350 मी.टन था. 1998-99 में बढ़कर 14086.5 मी. टन हो गया अर्थात 1994-95 के आयात से आयात 263.3% बढ़ गया। घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात 1994-95 में 112.6% से बढ़कर 1998-99 में 2301.7% हो गया। तुलनात्मक आधार पर आयात 2189.1% प्वाइंट अथवा 5 वर्षों की अविध में 20 गुना से भी अधिक बढ़ गया।

इस प्रकार, यह प्रमाणित है कि आयात घरेलू उत्पादन की तुलना में तथा पूर्ण रूप में दोनों तरह से बढ़ा है ।

# (18) गंभीर क्षति

1994-95 में घरेलू उद्योग ने पीले फास्फोरस का 4750 मी. टन उत्पादन किया जो 1995-96 में 5684 मी. टन तक बढ़ गया लेकिन उसके पश्चात तेजी से घट कर 1996-97 में 3565 मी. टन, 1997-98 में 465 मी. टन तथा 1998-99 में 612 मी. टन रह गया । पीले फास्फोरस का उत्पादन बन्द करने वाली पहली इकाई स्टार केमिकल्स थी जिसने 1995-96 के बाद से उत्पादन बन्द कर दिया । यू.पी.एल और एक्सेल इंडस्ट्रीज ने 1996-97 में उत्पादन बन्द कर दिया । केवल पी.ए.सी.टी. ने 1997-98 तथा 1998-99 में अपना उत्पादन वालू रखा लेकिन उन्होंने इन वर्षों के दौरान बहुत कम मात्रा में केवल कमशः 465 मी. टन तथा 612 मी. टन का उत्पादन किया । इस अवधि के दौरान स्पष्ट घरेलू उपमोग (कैप्टिव उपमोग सिहत घरेलू बिकी + आयात ) 1994-95 में 10658.48 मी. टन, 1995-96 में 12938.13 मी. टन, 1996-97 में 12671.799 मी. टन, 1997-98 में 12861 94 मी. टन तथा 1998-99 में 14737 276 मी. टन था (नीचे सारणी 4 देखें)

सारणी - 4 स्पष्ट घरेलू उपमोग

<u> चर्ष</u>	कैप्टिव उपभोग सहित बिकी (मी.टम)	आयात (मी. टन)	स्पष्ट घरेलू उपमोग (मी. टन)
1994-95	5306.48	5350	10656.48
1995-96	5445.13	7493	12938.13
1996-97	3842.79	8829	12671.79
1997-98	470 945	12391	12861 94
1998-99	650 776	14086 5	14737.276

इस प्रकार, घरेलू उत्पादकों को उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में एक गंभीर क्षिति हुई जो 1995-96 में 55.18% की उँचाई से गिरकर 1997-98 में 4.65% तथा 1998-99 में 6.12% तक नीचे आ गया । घरेलू उत्पादकों का स्पष्ट उपभोग में भी बाजार शेयर 1995-96 में लगभग 42% से गिरकर 1998-99 में मात्र 4.4% रह गया :

यह तर्क दिया गया है कि एस.सी.आई.एल. गंभीर क्षित होने का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका उत्पादन का कोई पूर्व इतिहास नहीं है तथा यू.पी.एल की कोई आधिकारिकता नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना संयंत्र एस.सी.आई एल. को स्थानांतरित कर दिया है और अब उनके पास पीले फास्फोरस के उत्पादन की कोई सुविधा नहीं है । यह भी तर्क दिया गया है कि एस.सी.आई.एल. एक नई इकाई है तथा एक नई इकाई बचाव के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता । तथापि, ये तर्क मान्य नहीं हैं, क्योंकि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के प्रयोजन के लिए घरेलू उच्चोग को पहुँची गभीर क्षित जैसे कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम. 1975 की धारा 8 बी के अधीन परिभाषित हैं, अर्थात कुल मिलाकर घरेलू उत्पादक अथवा वे जिनको बड़े अनुपात में घरेलू उत्पादन के लिए गिना जाता है, पर विचार किया जाना चाहिए।

इसलिए, सफेद/पीला फास्फोरस उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति प्रमाणित हैं।

# 19. क्षति का कारण

जबिक घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति हुई है तथा उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षित सस्ते आयातों के कारण हुई है, कुछ अन्य ने तर्क दिया है कि पीले फास्फोरस के घरेलू उत्पादकों को विद्युत की लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप पीले फास्फोरस की उत्पादन लागत ने वृद्धि हो जाने के कारण क्षिति हुई हैं । यह तर्क दिया गया है कि पीला फास्फोरस एक विद्युत आधारित उत्पाद है जिसमें, 30-35% अन्य परिवर्तनशील लागतों के साथ, पीले फास्फोरस के उत्पादन लागत का 50% खर्च विद्युत का खर्च हैं । यू.पी एल. के मामले में प्रति यूनिट विद्युत की कीमत 1994-95 में """ (गोपनीय) से 1998-99 में """ (गोपनीय) बढ़ गई है जिसने पीले फास्फोरस के घरेलू उत्पादन को अव्यवहार्य बना दिया है क्योंकि पीले फास्फोरस के एक मी टन उत्पादन के लिए 14,000 किलोवाट प्रति घटा (अथवा यूनिट) की आवश्यकता होती है ।

जबकि यह सही हो सकता है कि पीले फास्फोरस के घरेलू उत्पादक मुख्यतः उच्च विद्युत लागत के कारण परिवर्तनशील लागत बहुत अधिक हो जाने के कारण अप्रतिस्पर्धात्मक हो गए हैं, वहीं यह वास्तविकता है कि यह सस्ते आयात हैं जिन्होंने घरेलू उत्पादकों का बाजार शेयर छीन लिया तथा उनको अपनी उत्पादन सुविधाओं को बन्द करने के लिए बाध्य कर दिया ।

1994-95 की अवधि के दौरान, भारत में आयात 5350 मी. टन से बढ़कर 1998-99 में 14086.5 मी. टन हो गया जिनकी उतराई के समय के मूल्य औसतन घरेलू कीमतों से कही कम थे जैसा कि नीचे सारणी - 5 में दर्शाया गया है ।

## सारणी - 5

वर्ष	आयात (मी.टन)	औसत सी.आई.एफ कीमत रू./ किलो	उतराई के समय की औसत कीमत रूं /किलो	घरेलू बिकी (कैप्टिव उपमोग सहित ) (मी. टन)	औसत विक्रंय मूल्य रू/किलो
1994-95	5350	36 68	55.02	5306.48	73 52
1995-96	7493	45.35	68 03	5445.13	76.45
1996-97	8829	56.74	73.76	3842.79	99.60
1997-98	12391	48.47	65.43	470.945	83.83
1998-99	14086.5	47 52	64.15	650 776	75 58

याचिका में आवेदकों ने यू.पी.एल. के लिए उत्पादन की लागत के विषय में सूचना प्रदान की है, जो 1994-97 की अवधि के दौरान बड़ें उत्पादक थें । उससे यह देखा गया है कि यू.पी एल. के लिए पीले फास्फोरस के उत्पादन की लागत उनके विकय मुल्य से कहीं अधिक थीं और अभी भी वह आयातित पीले फास्फोरस की उतराई के समय की लागत से अधिक हैं । सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा के सामने घरेलू उत्पादकों को अपना विकय मूल्य, उत्पादन लागत से भी कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

कुछ पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मारत में पीले फास्फोरस का आयात घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य हो गया था क्योंकि पीले फास्फोरस के घरेलू उत्पादकों ने घरेलू माँग को पूरा नहीं किया तथा उन्होंने पीले फास्फोरस का उत्पादन मुख्यत. अपनी कैन्द्रिव आवश्यकताओं के लिए किया । इस विषय में यह देखा गया है कि 1994-99 की अवधि के दौरान पीले फास्फोरस का कुल घरेलू उत्पादन 15076 मी. टन था तथा आयात 48150 मी. टन था । 1994-95 की अवधि के दौरान स्पष्ट घरेलू उपमोग 10656 मी. टन प्रति वर्ष था जो धीरे-धीरे बबकर 1998-99 में 14737 276 मी टन प्रति वर्ष हो गया । विभिन्न पक्षों ने पीले फास्फोरस की घरेलू माँग के लिए विभिन्न ऑकड़े दिए है जो 13000 मी. टन प्रति वर्ष तथा 17000 मी. टन प्रति वर्ष के बीच मे हैं । फिर भी, यह देखा गया है कि 1995-98 से 1997-98 के दौरान पीले फास्फोरस का स्पष्ट उपमोग 12800 मी टन प्रति दर्ष का था । सत्यापन के अनुसार 1998-99 के दौरान अगवात 14086.5 मी. टन था तथा 1998-99 के दौरान घरेलू उत्पादन 612 मी. टन था। 1998-99 में 14737 275 मी टन प्रतिवर्ष के स्पष्ट उपमोग को 1998-99 के दौरान घरेलू माँग का प्रावर्तक माना गया है ।

लगमग समुची घरेलू मॉग आयातो द्वारा पूरी की गई क्योंकि पीए सी.टी के अलावा घरेलू उत्पादकों ने 1996 - 97 में पीले फास्फोरस का उत्पादन बन्द कर दिया था । 1997 - 98 तथा 1998 - 99 के दौरान पी.ए.सी टी ने मी कमश 465 मी.टन तथा 612 मी. टन की बहुत कम मात्रा का उत्पादन किया। यह भी देखा गया है कि 1994-99 के दौरान आवेदकों द्वारा उत्पादित 10007 मी टन पीले फास्फोरस में से यू पी एल. का हिस्सा 6826 मी टन था, जिसमें से उन्होंने फास्फोरस व्युत्पन्नों के विनिर्माण में 6474 मी टन का कैप्टिव उपमोग किया और केवल 352 मी टन को व्यापारिक बाज़ार में बेचा । स्पष्ट रूप से अपने कैप्टिव आवश्यकताओं के लिए घरेलू उत्पादको द्वारा स्वय पीले फास्फोरस के एक बड़े माग का भारत में आयात किया गया। नीचे सारणी 6 यू पी.एल /एस सी आई.एल , स्टार और एक्सेल द्वारा किये गये आयात के आकड़ों को प्रदर्शित करता है :-

सारणी <sup>6</sup> घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया आयात (मो टन में)

	आयातक				
तूर्ष	स्टार	एक्सेल	यू.पी.एल./एस सी.आई एल	(2),(3) और(4) का योग	कुल आयात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1996-97	1510	2042	2918	6470	8829
1997-98	1566	3380	4260	9206	12391
1998-99	900	4939	4665	10504	14086 5

उपरोक्त से यह देखा गया है कि जबकि यह सत्य है कि घरेलू उत्पादक घरेलू आवश्यकता को पूरा नहीं कर सके, और माँग तथा पूर्ति में अन्तर को मरने के लिए आयात को आवश्यक बना दिया गया था, यह भी सत्य है कि सस्ते आयात के कारण अधिकांश घरेलू उत्पादन सुविधाएँ बन्द हो गयी ।

इसलिए, बढे हुए आयात के कारण 'घरेलू उद्योग' को गम्भीर क्षति हुई ।

# 20. समायोजन योजना

आवंदनकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि कैप्टिव विद्युत का प्रयोग करके, सयत्र उपयोग को अधिकतम करके तथा स्तरीय मितव्यियता को प्राप्त करने के लिए अन्य दूसरी मद्दी लगाकर संयत्र की क्षमता 5000 मी दन बबाकर उत्पादन लागत को कम करने का प्रयास कर रहे हैं । उन्हें आशा है कि इन प्रयासों के द्वारा कम्पनी पर्याप्त मात्रा में लागत में बचत प्राप्त करेगी । 5000 मी दन से 10,000 मी दन की क्षमता के विस्तार में लगमग तीन वर्ष लगेंगे । इस विस्तार से उन्हें केवल स्तरीय मितव्यियता प्राप्त करने की ही आशा नहीं है बल्कि कच्चे माल (विद्युत, राक फास्फेट, कोक) के लिए उपमांग कुशलताओं में सुधार और बड़ी मात्रा में निर्धारित लागत के वितरण की भी प्राप्त करने की आशा है । पीले कास्फोरस के उत्पादन में चूकि विद्युत नुख्य लागत का कारक है, इसलिए एस.सी.आई.एल को आशा है कि वे विद्युत सयत्र के भार में अधिकतम स्तर तक बृद्धि करके विद्युत उत्पादन की लागत को कम कर सकेगे । एस सी आई एल यह भी प्रस्ताव कर रहा है कि वह विद्युत सयत्र ईधन को तरल नेष्या से प्राकृतिक गैस में परिवर्तन करेगे, जो विद्युत सयत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि करेगी और पीले फास्फोरस के लिए कुल मिलाकर लागत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बकार्यगी ।

पी.ए सी.टी. 80 लाख रूपये की लागत से अपने मट्टी को रूपान्तरित कर रहा है जो उत्पादन और लागत दोनों दृष्टि से मट्टी की कार्य कुशलता को बढ़ायेगा । इस आशोधन से लगमग 30% संयत्र क्षमता मे वृद्धि होने की आशा है । उन्होंने 4 मेगावाट के लघु जल विद्युत संयत्र को आरंभ करने के लिए केरल राज्य विद्युत परिषद (के.एस.ई.बी.) से एक प्राथमिक समझौता किया है । उन्होंने के.एस ई बी को तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । यह परियोजना कार्यान्वित होने पर न केवल पीले फास्फोरस सग्रंत्र को लगातार विद्युत आपूर्ति को सुविधाजनक बनाना सुनिश्चित करेगा, बल्कि बहुत अधिक सस्ती दर पर विद्युत की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा ।

आवेदकों द्वारा पुन समायोजन के सन्दर्भ में यह देखा गया है कि एस.सी.आई एल. कास्टिक सोड़ा का विनिर्माण कर रहे थे, जो एक विद्युत प्रधान उत्पाद है। उन्होंने 100 करोड़ रूपये के निवेश से 50 मेगावाट के एक विद्युत संयंत्र की स्थापना की थी। एस.सी.आई एल. को आशा थी कि अपने कास्टिक सोड़ा संयंत्र को आपूर्ति करने के बाद इस कैंप्टिव विद्युत सयत्र से बची हुई अधिक विद्युत को वे यू.पी.एल. को उनके पोले फास्फोरस उत्पादन के लिए प्रेषित कर देंगे, इस तरह पूरी कम्पनी को विद्युत कम लागत पर उपलब्ध हो जाएगी। फिर भी, एस.सी.आई एल. से यू.पी.एल. को विद्युत स्थानान्तरित करने में उनके सामने आने वाली किंदिनाइयों के कारण यू.पी.एल. ने अपने पीले फास्फोरस संयंत्र को एस.सी.आई एल. को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार पीले फास्फोरस के उत्पादन के लिए बची हुई अधिक विद्युत का उपयोग संमव हो गया।

## 21. जनहित

पीले फास्फोरस के बढ़े हुए आयात से पीले फास्फोरस के घरेलू उत्पादकों ने गमीर क्षति का सामना किया है । वे पुनः समायोजन हेंतु भी प्रयास कर रहे हैं । फिर भी, इसका परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है कि पीले फास्फोरस पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनहित में होगा या नहीं ।

इस संबंध में, यह देखा गया है कि पीले फास्फोरस की घरेलू माग लगमग 14700 मी टन प्रतिवर्ष थी । घरेलू उत्पादकों के पास 1994-95 में 9800 मी टन प्रति वर्ष की कुल स्थापित क्षमता थी जो 1995-96 में बढ़कर 10300 मी टन प्रतिवर्ष हो गयी लेकिन उसके बाद गिरकर 10000 मी टन प्रतिवर्ष रह गयी । घरेलू उत्पादकों का अधिकतम उत्पादन 1995-96 में 5684 मी टन था और 1996-97 में घट कर 3565 मी टन, 1997-98 में 465 मी टन और 1998-99 में 612 मी टन रह गया । इसलिए घरेलू उत्पादक पीले फास्फोरस की घरेलू आवश्यकता को पूरा नहीं कर सके, जिसे आयातकों द्वारा लगमग पूर्णतः पूरा किया गया । आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि उनके पास पीले फास्फोरस की 5000 मी टन प्रति वर्ष की क्षमता है, 1000 मी टन पी एसी टी. की, और 4000 मी टन एस सी आई एल की, जिसे यू पी एल. पीले फास्फोरस संग्रंत्र को एस सी आइ एल. को स्थानान्तरित करने से स्थापित किया गया था । एस सी आई एल. की और भी योजना है कि वे इस क्षमता को अगले 3 वर्षों में 5000 मी टन प्रति वर्ष तक बढ़ायेंगे । पी एसी टी के पास 1000 मी टन की स्थापित क्षमता है जिसको बढ़ाकर वे 1300 मी टन फरने की योजना बना रहे हैं । इस तरह आवेदकों की योजना है कि वे अगले 3 वर्षों में पीले फास्फोरस की 11300 मी टन प्रति वर्ष की क्षमता प्राप्त कर लेगे ।

यहाँ यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि लगभग 14700 मी टन प्रतिवर्ष की माग के विरुद्ध घरेलू उद्योग के पास पीले फास्फोरस के उत्पादन की उपलब्ध क्षमता आवेदक कम्पनियों की केवल 5000 मी टन प्रतिवर्ष थी क्योंकि अन्य दोनों कम्पनियों जैसे एक्सेल और स्टार ने पीले फास्फोरस के उत्पादन को पुनः आरम्म करने के किसी भी इरादें से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। आवेदकों ने तर्क दिया है कि एक्सेल ने अपने संयंत्र को अभी उखाड़ा नहीं है, इसलिए यदि उनकी क्षमता को सम्मिलित नहीं किया जाता है तो घरेलू मांग को निर्धारित करते समय पीले फास्फोरस की उनकी आवश्यकता पर भी विचार नहीं किया जाना चाहिए।

फिर भी, यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि पी.ए.सी.टी. के अलावा अन्य सभी घरेलू उत्पादकों ने पिछले दो वर्षों अर्थात 1997-98 और 1998-99 के दौरान पीले फास्फोरस के उत्पादन को बन्द कर दिया था। एक्सेल को यह निर्णय करने का अधिकार है कि वे उत्पादन को पुनः आरम करने का इरादा करें या नहीं । एक्सेल द्वारा स्थापित पीले फास्फोरस की क्षमता का किसी प्रकार का कोई भी प्रमाव यू.पी.एल./एस सी.आई.एल. के उत्पादन पर नहीं पड़ा है, या उनकी स्थिति को अन्य किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि विशेषकर यू.पी.एल / एस.सी.आई.एल. ने अपने सम्पूर्ण पीले फास्फोरस उत्पादन का उपमोग लगभग पूर्ण रूप से कैप्टिव आवश्यकताओं के लिए किया और घरेलू बाजार मे मुश्किल से कोई पदार्थ बेचा । इस संदर्भ में यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि 1996 में जनता के लिए जारी की गयी अपनी विवरणिका में एस.सी.आई.एल. ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वे अपने सभी खरीददारों में से यूपी एल. की आवश्यकताओं को वरीयता देंगे और किसी भी समय उनके सभी खरीददारों को पूरी मात्रा में आपूर्ति करने में यदि वे असमर्थ रहे तो यथासम्मव वे पहले यू.पी.एल. की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समी समुचित प्रयास करेंगे । इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एस.सी.आई एल. सबसे पहले यू पी.एल. की कैप्टिव आवश्यकता के लिए पीला फास्फोरस उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, यह विश्वास करना किंटन है कि आवेदक किसी भी महत्वपूर्ण सीमा तक घरेलू व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते है। इस तरह, पीले फास्फोरस के आग्रात पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण, पीले फोस्फोरस के उन अधिकाश घरेलू उपमोक्ताओं में हितों को गंभीरतापूर्वक प्रभावित करेगा, जो आयात के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पुरा करते हैं ।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यू.पी.एल/एस.सी आई एल. स्वयं फास्फोरस व्युत्पन्नों के उत्पादक हैं. और वे फास्फोरस व्युत्पन्नों के अन्य उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं । फास्फोरस व्युत्पन्नों के यही उत्पादक आयातित पीले फास्फोरस का प्रयोग करते रहें हैं । यू पी.एल/ एस. सी.आई.एल. का इरादा अपने केव्विव आवश्यकताओं के लिए पीले फास्फोरस के उत्पादन का है. किन्तु आयातित पीले फास्फोरस की तुलना में पीले फास्फोरस के उत्पादन की उनकी लागत अधिक हैं । इसलिए, यदि वे अपने स्वयं के पीले फास्फोरत का प्रयोग करें तो फास्फोरस व्युत्पन्नों के अन्य उत्पादकों के साथ वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं । पीले फास्फोरस पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण आयातित पीले फास्फोरस के उतराई के समय के मूल्य को देशी पीले फास्फोरस से तुलनीय स्तर पर ला देगा, जो यू पी एल/एस.सी.आई.एल. को फास्फोरस व्युत्पन्नों के घरेलू व्यापारिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बना देगा । इस तरह रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल आवेदकों को ही लाम पहुंचाने वाला है, क्योंकि यह पीले फास्फोरस के उन अन्य प्रयोगकर्ताओं/ आयातकों की तुलना में उन्हें लाम पहुंचाएगा, जो फास्फोरस व्युत्पन्नों के उत्पादन में आवेदकों से प्रतिस्पर्धा करते हैं । इस संदर्भ में आवेदकों ने यह भी तर्क दिया है कि कीटनाशक माध्यमों के विनिर्माण में पर्याप्त लाम है और यह रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के परिणामस्वरूप पीले फास्फोरस की कीमतों में वृद्धि को भी समाहित कर सकता है । ऐसा लगता है कि यह तर्क आवेदकों पर भी समान रूप से लागू होता है । वृद्धि को वोदक स्वय फास्फोरस व्युत्पन्नों जैसे कीटनाशक माध्यमों आदि का उत्पादन करते हैं इसलिए वे भी इसी तरह का लाम प्राप्त कर रहे होंगे और यदि वे पीले फास्फोरस का

उत्पादन स्वयं करने का निर्णयं लेते हैं और कैप्टिंव रूप से उसका उपमोग करते हैं तो पीले फास्फीरस की लागत में कुछ वृद्धि को समाहित कर लेने में उन्हें समर्थ होना चाहिए। यदि वे चाहते हैं कि अन्य लोग अतिरिक्त लागत पण पहण करें तो उन्हें स्वयं ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, विशेषकर जैसा स्वीकार किया गया है कि उन्हें फास्फीरस व्युत्पन्नों के उत्पादन में कुछ लाम तो है ही। ऐसा लगता है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की उनकी माँग यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी हैं कि अन्य लोगों को, जो फास्फोरस व्युत्पन्नों का विनिर्माण करते हैं, पीला फास्फोरस उस कीमत पर उपलब्ध न हो जिसके नीचे अर्थात उनके उत्पादन की लागत के नीचे, वे उनके कैप्टिंव उपमोग के लिए पीले फास्फोरस का स्थानान्तरण करते हैं।

इस सदर्भ मे, यह दंखना भी महत्वपूर्ण है कि यू पी.एल./एस सी.आई.एल ने स्वय उल्लेख किया है कि "---- हमने अपने निर्यात वस्तुओं के लिए पीले फास्फोरस का आयात किया है, इसने हमें अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाये रखने में सहायता की हैं और हम अत्यधिक प्रतियोगी मूल्यों पर अपने निर्यात को बढ़ा सके । पुन. स्थान को अवधि के दौरान, अपने कैप्टिव उपमोग के लिए पीले फास्फोरस के आयात ने कम्पनी को अनुप्रवाही सामानों में बेहतर लाम दिलाया है, जो उस समय उपलब्ध नहीं था, जब कम्पनी को सामृहिक रूप में विचार किया जाता है, जब हम अपने स्वय के पीले फास्फोरस का उपमोग कर रहे थे ।" इसलिए, आयातित पीले फास्फोरस का उपयोग उनके लिए स्वीकृत रूप से लामदायक था । ऐसा होने से यह समझ में नहीं आता है कि यू पी.एल./एस.सी.आई एल. ने पीले फास्फोरस के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए अनुरोध क्यों किया है । फिर भी, यू पी.एल./एस सी.आई.एल. ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का अनुरोध घरेलू उद्योग के पूर्णत. नष्ट हो जाने से बचाने के लिए किया है । उनके अनुसार निर्यातक एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करते रहे हैं कि यदि घरेलू उद्योग एक बार पूरी तरह नष्ट हो जाए तो वे मनचाही कीमत उसूल कर सकें । उनके अनुसार, निर्यातको ने पीले फास्फोरस की कीमतो को नहीं बढ़ाया क्योंकि वे जानते थे कि यदि वे कीमत बढ़ाते तो घरेलू उत्पादक पीले फास्फोरस का उत्पादन पुन आरम कर सकते हैं ।

इस संदर्भ में विभिन्न पक्षों द्वारा अनेक तर्क दिए गए हैं । उन तर्कों में से एक हैं, पीले फास्फोरस का वास्तविक रूप में उत्पादन किए बिना सयत्र को चालू हालत में बनाये रखने के निर्णय से प्राप्त होने वाले लाम पर विचार करना । एक्सेल के प्राक्कलन के अनुसार, 5000 मी टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक पीला फास्फोरस संयत्र की लागत लगमग 10 करोड़ रूपये होगी । 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन के रूप में लागत लगमग 2.5 करोड़ रूपये होगी और 50 लाख रूपये के अन्य अनुमानित लागत से, क्षमता को बेकार रखने की कुल लागत 3 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष के आसपास होगी । जैसािक इसके विरुद्ध, 50 रूपये प्रति कि.ग्रा. (आवंदकों द्वारा मॉंगे गए रक्षोपाय शुल्क की धनरािश ) की दर से आयाितत पीले फास्फोरस की कम कीमत के परिणामस्वरूप प्राप्त बचत, फास्फोरस व्युत्पन्नों के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए 5000 मी टन के लिए, रू. 5000 x 50 000 अर्थात लगमग 25 करोड़ रूपये की होगी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस प्रकार से प्राप्त की गयी बचत के एक छोटे से अंश को खर्च करने से दोनो उद्देश्यों की प्राप्त किया जा सकता था ।

यू पी.एल./एस.सी आई.एल. द्वारा प्रस्तुत किए गए आकड़ों से यह भी देखा गया है कि विद्युत की लागत को कम करने और उच्चतर उत्पादन कुशलताओं को प्राप्त करने में उनके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रस्तावित प्रयासों के साथ, तीन साल की उस अवधि, जिसके लिए रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए अनुरोध किया गया है, के बाद भी आयातित पीले फास्फोरस की तुलना में वे लागत - प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकते हैं।

यू पी.एल./ एस.सी.आई.एल. का बड़ा प्रयास विद्युत की लागत को कम करने में हैं । उनका इरादा तीन वर्षों में """ प्रति यूनिट से लगमग """ ( गोपनीय ) प्रति यूनिट तक विद्युत की लागत को कम करने का है । फिर भी. पी.ए.सी.टी., जो केरल राज्य विद्युत परिषद से लगमग 2.50 रूपये प्रति यूनिट विद्युत प्राप्त कर रहे थे, जो यू.पी.एल./एस.सी.आई.एल को विद्युत की लागत की तुलना में बहुत कम है, पीले फास्फोरस का उत्पादन प्रतिस्पर्धी कीमत पर करने में समर्थ नहीं हैं । वास्तव में, उत्पादन की उच्चतर लागत के कारण उन्होंने पीले फास्फोरस का उत्पादन बन्द कर दिया है । इसलिए, यह मानना किंदन है कि तीन वर्ष के बाद भी घरेलू उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर देशी पीला फास्फोरस उपलब्ध कराया जा सकता है ।

एकं तर्क दिया गया है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से पीले फास्फोरस का शुल्क मुक्त आयात प्रमावित नहीं होगा । इस संबंध में, यह देखा गया है कि पीले फास्फोरस का शुल्क मुक्त आयात दो श्रीणयों में आता हैं । पहला वह हैं जो अग्रिम लाइसेंस के तहत आयातित हैं और निर्यात उत्पाद में प्रयोग के लिए हैं, तथा दूसरा वह हैं जो डी.ई.पी.बी. योजना के अंतर्गत आयातित हैं । जहाँ तक अग्रिम लाइसेंसों के तहत आयातों का संबंध हैं, ऐसा माना जा सकता है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का असर इस तरह के आयातों पर नहीं पड़ सकता हो, क्योंकि सरकार सामान्यत इन आयातों को रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से मुक्त रखती रही है । डी.ई.पी.बी आयात उस आधार पर नहीं हैं, जिसपर डी.ई.ई सी. आयात है । डी.ई.पी.बी. योजना के अधीन आयात पर सभी शुल्क देय हैं लेकिन उसी सीमा तक जहाँ तक शुल्क डी.ई.पी.बी. जमाधन के माध्यम से मुग्रतान किया जाता है, आयातों पर शुल्क प्रमारित नहीं होता है । इसलिए डी.ई.पी.बी. योजना के अधीन आयात, रक्षोपाय शुल्क के मुगतान के अधीन है, यदि लगाया जाता है ।

जैसा सत्यापित किया गया है, 1998-99 के दौरान डी.ई.ई.सी. (अग्रिम लाइसेंस) और डी.ई पी.बी. योजना के अधीन 7143.028 मी टन पीले फास्फोरस का आयात किया गया था, जिसमें से डी.ई ई.सी योजना के अधीन केवल 2245.926 मी.टन का आयात किया गया था। 14086.5 मी.टन के कुल आयात में से डी.ई.ई सी. के आयात को निकाल देने पर भी लगभग 11841 मी टन की मात्रा फिर भी बची रहेगी. जिसपर यदि आवेदकों के अनुरोध के अनुसार 50 रूपयें प्रति कि ग्रा. की दर से रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किया जाता है तो इसके परिणामस्परूप उपयोगकर्ता उद्योग को लगभग 60 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा।

इन तथ्यों को ध्यान में रखकर कि पीले फास्फोरस के घरेलू उत्पादकों ने 1997-98 और 1998-99 में केंवल बहुत थोड़ी मात्रा में ही उत्पादन किया, आवेदकों की स्थापित क्षमता केंवल 5000 मी.टन है जो कभी भी प्राप्त की गयी अधिकतम उत्पादन के साथ घरेलू मांग के एक छोटे हिस्से का ही लेखा जोखा देता है. अब भी कम है और जिसमें से अधिक का उपयोग कैंप्टिव उपमोग के लिए कर लिया गया था। यू पी.एल /एस.सी आई.एल., फास्फोरस व्युत्पन्नों के उत्पाद में पीले फास्फोरस के प्रयोगकर्ताओं/आयातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, यू पी.एल., एस सी.आई.एल. आयातित पीले फास्फोरस के प्रयोगकर्ताओं/आयातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, यू पी.एल., एस सी.आई.एल. आयातित पीले फास्फोरस के प्रयोग से स्वयं लामान्वित हुए हैं, संयंत्र को बेकार रखने की लागत, आयातित पदीर्थों के प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाम का केंवल एक अश मान्न है, और यह कि समायोजन करने के बाद भी आयातित पीले फास्फोरस की तुलना में यू पी.एल./एस.सी.आई.एल. लागत प्रतिस्पर्धी न हो सकें, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनहिंत में प्रतीत नहीं होता है।

# 22 निष्कर्ष एवं संस्तुतियां :

सफेद/पीले फास्फोरस के बढ़े हुए आयात के कारण सफेद/पीले फास्फोरस के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति उदानी पड़ी है । फिर भी, सफेद/पीले फास्फोरस के आयात पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनहित में नहीं है । इस लिए, मारत में आयातित सफेद/पीले फास्फोरस पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए कोई सस्तुति नहीं को जाती है ।

[ सं. एस.जी./आई.एन.वी./2/99]

आर.के. गुप्ता, महा निदेशक

# OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS) NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2000

Subject: Safeguard investigation concerning imports of White/Yellow Phosphorus into India Final Findings.

G.S.R. 126(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof

#### A **PROCEDURE**

The Notice of Initiation of safeguard investigation concerning imports of White/Yellow Phosphorus into India was issued on 15.09.99 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on 15.09 99. A copy of the Notice was sent to all known interested parties, namely:

#### **Domestic Producers**

- (i) United Phosphorus Ltd., Mumbai, (UPL)
- (ii) Search Chem Industries Ltd, (SCIL), Mumbai
- (iii) Phosphorus and Chemicals Travancore Ltd.(PACT), Cochin
- (iv) Star Chemicals (Bombay) Ltd., Mumbai, (Star)
- (v) Excel Industries Ltd., Mumbai, (Excel)

#### **Importers & Users Industries**

- (i) Sri Majentha Chemical (P) Ltd., Tamilnadu
- (ii) Kline Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai
- (iii) Nerka Chemicals Pvt. Ltd , Mumbai
- (iv) Watsol Organics Ltd, Hyderabad
- (v) Anan Drugs & Chem Ltd., Bhavnagar
- (vi) Sabero Organics Gujarat Ltd, Mumbai
- (vii) STS Chemicals Ltd., Mumbai
- (viii) Cheminova, Mumbai
- (ix) Aquapharm Chemicals Company Ltd., Pune
- (x) Kalpataru Chemicals, Tamilnadu
- (xi) Metal Powder Company Ltd., Madurai
- (xii) Prachi Poly Products Ltd, Mumbai

## **Exporters**

- (i) China National & Chemicals I/E Corpn., China
- (ii) Shee Hing (China) Development Ltd., Hong Kong
- (iii) Wuhan Chemicals I/E Corp., China
- (iv) Doultsons Ltd., Hong Kong
- (v) Yunnan Provincial Chemicals I/E Corpn., China
- (vi) Jiagmen Chemicals I/E Company of Guangdong China, China
- (vii) Kunming Import & Export Corpn., China
- (viii) China Hunan Chemicals Imp. & Exp. Copn., China
- (ix) FMC Corporation, USA
- (x) Monsanto Company, USA
- (xi) Nippon Chemical Industrial Co. Ltd., Japan
- (xii) Rasa Industries Ltd., Japan
- (xiii) KazNLL Khimproyokt, Kazakhstan
- (xiv) Elf Atochem, SA, France
- (xv) Hoechst Aktiengesellschaft, Germany
- (xvi) E Merck, Germany
- (xvii) Albright & Wilson Ltd., UK
- (xviii) Hoechst Holland HV, Netherland

(The notices sent to Doultsons Ltd., Hong Kong and Nippon Chemical Industrial Co. Ltd., Japan were returned undelivered by the postal authorities).

#### **Associations**

- (i) Indian Chemical Manufacturers Association, Mumbai
- 2. A copy of the notice alongwith the application and questionnaire was also sent to the governments of exporting countries through their High Commissions/Embassies in New Delhi namely Bulgaria, China, Chinese Taipei, Hongkong, Germany, Japan, Korea DPR, the Netherlands, UK and USA.
- 3. Questionnaires were also sent on the same day to all known domestic producers, exporters and importers who were asked to submit their response by 25.10.99.
- 4. Request for extension of time to submit their reply upto 30th November, 1999 was made by M/s. Guiyang Phosphorus Chemicals General Factory through the Economic & Commercial Counselor's office of People Republic of China, New Delhi. Keeping their request in mind and the need to complete the investigation within the statutory period extension upto 9th November, 1999 was allowed and they were informed accordingly. They were also further informed that they have been taken on record as an interested party and they may participate in the Public Hearing.
- 5. Replies to the Notice dated 15.09.99 and to the questionnaire were received from the following parties:

#### **Domestic Producers**

- (i) United Phosphorus Ltd., Mumbai
- (ii) Search Chem Industries Ltd., Mumbai
- (iii) Phosphorus and Chemicals Travancore Ltd., Cochin
- (iv) Star Chemicals (Bombay) Ltd., Mumbai
- (v) Excel Industries Ltd., Mumbai

UPL and SCIL have filed a common reply. Star Chemicals (Bombay) Ltd., Mumbai have filed the reply as an importer. Excel Industries Ltd., Mumbai have filed a reply but did not furnish any details to the questionnaire sent to them.

## **Importers & Users Industries**

- (i) Sri Majentha Chemical (P) Ltd., Tamilnadu
- (ii) Kline Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai
- (iii) Nerka Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai
- (iv) Watsol Organics Ltd., Hyderabad
- (v) Sabero Organics Gujarat Ltd., Mumbai
- (vi) STS Chemicals Ltd., Mumbai
- (vii) Cheminova, Mumbai
- (viii) Aquapharm Chemical Company Ltd., Pune
- (ix) Kalpataru Chemicals, Tamilnadu
- (x) Metal Powder Company Ltd., Madurai
- (xi) Prachi Poly Products Ltd., Mumbai

#### **Associations**

- (i) Indian Chemicals Manufacturers Association, Mumbai
- 6. Response to the notice has also been filed by the following parties which includes importers/user industries; associations and exporters:
- (i) Shaw Wallace & Company Ltd., Chennai-600 001,
- (ii) Ralchem Limited, Secunderabad-500 003
- (iii) Nagarjuna Agrichem Ltd., Hyderabad-500 082
- (iv) Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd., Hyderabad-500 034
- (v) Novartis India Ltd., Mumbai-400 020.
- (vi) Bhaskar Agro Chemicals Ltd., Hyderabad-500 004.
- (vii) India Pesticides Ltd., Bareilly-243001.
- (viii) Venkateswara Pesticides & Allied Chemicals Pvt. Ltd., Hyderabad.
- (ix) Rhyme Organics & Chemicals Ltd., Hyderabad-500 020
- (x) Mitsu Ltd., Mumbai-400 059.
- (xi) De-Nocil Crop Protection Ltd., Mumbai-400 079.
- (xii) Pioneer Products Ltd., New Delhi-110 041.
- (xiii) Vantech Industry Ltd., Hyderabad-500 016:
- (xiv) Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad-382 445.
- (xv) Krishna Antioxidants Pvt. Ltd., Mumbai-400 103.
- (xvi) Lubrizol India Ltd., Mumbai-400 025.

- (xvii) Anil Pesticides Ltd., Punchkula-134113.
- (xviii) M.R.Pharma Pvt. Ltd., Mumbai-400 004.
- (xix) Rencal Chemicals (India) Ltd., New Bombay-400 705.
- (xx) HPM Industries Ltd., New Delhi 110005.
- (xxi) E.I.D. Parry (India) Ltd., Chennai-600 001.
- (xxii) Tri-Chem Enterprises (Bombay) Pvt. Ltd., Bombay-400 016.
- (xxiii) Waman Industrial Chemicals Ltd., Bombay-400 062
- (xxiv) Sudarshan Chemical Industries Ltd., Pune-41 001.
- (xxv) Bayer India Ltd., Mumbai-400 076
- (xxvi) Gharda Chemicals Ltd., Mumbai-400 050
- (xxvii) Transmissions Ltd., Mumbai-400 078.
- (xxviii)Ravi Organics Ltd.New Delhi 110 005.
- (xxix) Ficom Organic, Mumbai-400 021.
- (xxx) Sumex Chemicals Ltd., Mumbai-400 018.
- (xxxi) Alchemie Organics Ltd., Mumbai-400 080.
- (xxxii) Spectrum Ethers Ltd., Mumbai-400 055.
- (xxxiii)Northern Minerals Ltd., New Delhi- 110 005.
- (xxxiv)Rajasthan Insecticides & Fertilizer Company Pvt. Ltd., New Delhi
- (xxxv) Dhanuka Pesticides Ltd., New Delhi-110 005.
- (xxxvi)Rallis India Ltd., Mumbai-400 001.
- (xxxvii) AgrEvo India Ltd., Mumbai-400 093.
- (xxxviii) Sandhya Organic Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai-400 057.
- (xxxix) Cyanamid Agro Ltd., Mumbai-400 020
- (xl) Gujarat Superphosphate Industries (P) Ltd., Ahmedabad-380 002
- (xli) Pesticides India Ltd., Udaipur-313 001.
- (xlii) The All India Chambers of Match Industries, Sivakashi-626 123.
- (xlii) Jayshree Vyapar Ltd., Rajkot, Gujarat
- (xliii) The Indian Smelting & Refining Co. Ltd., Mumbai-400 078.
- (xliv) The Indian Smelting & Refining Co. Ltd., Mumbai-400 078.
- (xlv) Tirupati Coal & Coke Suppliers, Dhanbad (Bihar).
- (xlvi) Kunvarji Ramji & Co., Bombay-400 086
- (xlvii) Shivalik Rasayan Ltd., New Delhi-110 019.
- (xlviii) Guizho Jinsha Yellow Phosphorus I/E Corp., China
- (xlix) Wock-hardt Limited, Mumbai-400 018
- (1) Nisarg Pharmachem, Bhawnagar-364 002.
- (li) Hindustan Coal Movers Pvt. Ltd., Jamnagar-361 001.
- (lii) AIMCO Pesticides Ltd., Mumbai-400 055.
- (liii) Federation of Kamarajar District Chamber of Commerce & Industries, Sattur
- (liv) Ipca Laboratories Ltd., Kandivli (West), Mumbai-400 067.
- (lv) Mangalam Drugs and Organics Ltd., Mumbai-400 002.
- (lvi) Graphite India Ltd., Calcutta-700 016.
- (lvii) Madhya Pradesh State Mining Corporation, Bhopal-462 011.
- (lviii) Arlabs Ltd., Mumbai-400 001.
- (lix) Ranbaxy Fine Chemicals Ltd., Mumbai- 400 001.
- (lx) Guizhou Provicial Chemicals I/E Corp., China-550 001.
- (lxi) All India Chamber of Commerce and Industries, Tuticorin-628 001.
- (lxii) Yunnan Minmetals & Chemicals I/E Group Corp., China
- (lxiii) Tamilnadu Chamber of commerce & Industries, Madurai-625 009.

- (lxiv) Confederation of India Industry (CII), Ahmedabad-380 006.
- (lxv) Bimol International Ltd., Bangbon, Bangkok.
- (lxvi) Sabar Mineral, Himatnagar Distt. SK-383 001.
- (lxvii) Indian Crop Protection Association, Mumbai-400 098.
- (lxviii) Ankleshwar Industries Association, Ankleshwar-393 002.
- (lxix) The Sattur Chamber of Commerce & Industries, Sattur-626 203.
- (lxx) Sattur Merchants & Industrialists Association, Sattur -626 203.
- (lxxi) Northern India Pesticides Manufacturers Association, Delhi-110 033.
- (lxxii) Pesticides Association of India, New Delhi-110 001
- (lxxiii) Haryana Pesticides Manufacturers' Association, New Delhi-110 005.
- (lxxiv) Pesticides Manufacturers & Formulators Association of India, Mumbai
- (lxxv) South India Match Manufacturers Association, Kovilpatti-628 501.
- (lxxvi) The South India Swedeshi Match Manufacturers Association, Sattur.
- (lxvii) Gujarat Pesticides Formulators Association, Ahmedabad-389 009
- (lxxviii)Ramanathapuram District Cottage Match Manufacturers Association, Sattur-626 203.
- (lxxix) Association of Small & Medium Chemical Manufacturers, Mumbai
- (lxxx) All India Cottage Match Industry Federation, Sattur-626 203.
- (lxxxi) Guiyang Phosphorus Chemicals General Factory, China
- 7. Verification of the information considered necessary for the investigation was done and to this end a team of officers visited the premises of Domestic Producers, Importers and User industries. The outcome of the investigations was conveyed to the concerned parties who were visited and a copy of the investigation report was also placed in Public File.
- 8. A Public Hearing was given to all interested parties on 23.12.99, notice for which was sent on 22.11.99. During the Public Hearing the interested parties were requested to file their written submission of oral arguments made by them by 31 12.1999, collect replies filed by others on 3.1 2000 and to file rebuttals, if any, by 10.1.2000. The following parties attended the Public Hearing.
- (i) United Phosphorus Ltd., Mumbai
- (ii) Search Chem Industries Ltd., Mumbai
- (iii) Phosphorus and Chemicals Travancore Ltd., Cochin
- (iv) Star Chemicals (Bombay) Ltd., Mumbai
- (v) Excel Industries Ltd., Mumbai
- (vi) Watsol Organics Ltd., Hyderabad
- (vii) Sabero Organics Gujarat Ltd., Mumbai
- (viii) STS Chemicals Ltd., Mumbai
- (ix) Cheminova, Mumbai
- (x) Lubrizol India Ltd., Mumbai
- (xi) Sandhya Organic Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai
- (xii) Federation of Kamarajar District Chamber of Commerce & Industries, Sattur
- (xiii) Madhya Pradesh State Mining Corporation, Bhopal
- (xiv) All India Chamber of Commerce and Industries, Tuticorin.
- (xv) Pesticides Association of India, New Delhi

- (xvi) Ramanathapuram District Cottage Match Manufacturers Association, Sattur
- (xvii) All India Cottage Match Industry Federation, Sattur-626 203.
- (xviii) Embasy of the Republic of Bulgaria, New Delhi
- (xix) Embassy of People Republic of China, New Delhi.
- (xx) European Commission, New Delhi.

## B. <u>VIEWS OF THE DOMESTIC PRODUCERS</u>

- 9. (a) United Phosphorus Ltd./Search Chem Industries Ltd.
- (i) UPL has legally and physically transferred its entire Yellow Phosphorus capacity to SCIL for operational reasons and UPL continues to be the controlling company of SCIL. SCIL is a subsidiary of UPL by virtue of UPL holding 53% equity stake in SCIL. Also, the management control of UPL and SCIL is vested with the same promoter group. Furthermore, UPL itself was producing Yellow Phosphorus in India till 1996-97 and even today, UPL holds interests in the Yellow Phosphorus production as its subsidiary is producing this vital material.
- (ii) SCIL was promoted by UPL with the main objective of setting-up its existing 50MW Power Plant, which was a capital-intensive proposition, and has different types of operational and financial risks as compared to UPL's primary business interests. The purpose of this Power Plant was to meet the captive requirements of power for various plants of both UPL and SCIL, but more particularly of the power intensive Yellow Phosphorus (YP) Plant and Chlor-Caustic Plant, where power constitutes more than 50% of the cost of production. In order to facilitate transmission of power at minimal cost to these power intensive plants, it was consciously decided to legally and physically transfer the Yellow Phosphorus Plant from UPL to SCIL. Both these plants are presently situated adjacent to the Power Plant of SCIL at the same site.
- (iii) SCIL generates electric power for captive consumption by UPL and SCIL and markets major part of the other products mainly in the local market. It utilizes part of the production of Yellow Phosphorus and Chlorine Gas for the manufacture of Phosphorus Trichloride (PTC) which is an intermediate for Agrochemical/Technicals. PTC is further partly utilized for the manufacture of downstream products like Phosphorus Oxychloride (POC), HEDP and Phosphorus Pentachloride (PPC). SCIL is selling PTC, POC, HEDP and PPC in both the local and export markets.
- (iv) UPL is engaged in the manufacture of wide range of products relating to Agrochemical Industry namely Agrochemical formulations, Agrochemical technicals, Agrochemical intermediates and Industrial chemicals. SCIL is backward integration of UPL. UPL and SCIL together constitute the only company of its kind with fully integrated facilities in India for the production of Agrochemical Formulations for consumer market and Agrochemical Technicals for industrial market from the basic raw materials.

7

- (v) Rock Phosphate, Coke and Silica are the major raw materials for production of Yellow / White phosphorus. The process for the manufacture of Yellow Phosphorus is a semi-continuou and involves conversion of rock phosphate into phosphorus in the presence of Silica and Coke by Electro-thermal route. This process for the manufacture of Yellow Phosphorus is highly energy intensive due to endothermic reactions. This energy is made available through heat generated by electric energy.
- (vi) There is no significant difference in the Yellow Phosphorus produced by the Indian industry and that imported into in India. Yellow Phosphorus produced by the Indian industry is comparable to any other producer wold-over. The consumers are consuming Yellow Phosphorus produced by the domestic industry and imported Yellow Phosphorus interchangeably, without making any significant changes in the production process. Yellow Phosphorus produced by UPL/SCIL and imported Yellow Phosphorus is similar in terms of physical characteristics and chemical composition, product specifications, manufacturing technology, plant and equipment, manufacturing process, functions and uses, marketing and pricing, consumer perception. The two are technically and commercially substitutable. Yellow Phosphorus produced by the Indian industry, including SCIL is a like article to imported Yellow Phosphorus.
- (vii) The major direct and indirect consumers of Yellow Phosphorus manufactured by them are the manufacturers of Agrochemical Intermediates like Phosphorus Trichloride, Phosphorus Pentasulfide etc. and Agrochemical Technicals like Monocrotophos, DDVP, Acephate etc. besides the manufacturers of plasticisers and polymer additives, flame and fire retardants, water purification and treatment chemicals etc.
- (viii) The cost of production of the petitioners increased significantly over the years in view of steep increase in the cost of power, as a result of the hike in the power tariff by the Government of Gujarat. In fact, the variable cost of production itself was significantly higher than the prices, which the company could fetch in the market, and was substantially higher than the landed price of imports. The company found it unviable to run the plant with the present and contemporary power tariff and rather decided to set up its own captive power plant for generating cheaper power, which would reduce the cost of production and is the only way to meet the competition from the imports of Yellow Phosphorus
- (ix) United Phosphorus Ltd made a gross investment of Rs. 20 Crs. in its Yellow Phosphorus manufacturing in a gradual manner over the years, which had a capacity to produce 5000 MT per annum of Yellow Phosphorus. However, in view of significantly higher cost of production as compared to the landed price of the imported Yellow Phosphorus, the company could not produce to its optimum capacity. With gradual increase in the power tariff, the company found it unviable to run the plant with power from State Electricity Board and eventually decided to set up its own captive power plant for sourcing electric power. The power plant was set up in SCIL and in view of the difficulties relating to supply of power from SCIL to UPL alongwith stiff power wheeling conditions imposed by State Electricity Board, UPL transferred its Yellow Phosphorus plant also to SCIL. The

1

plant was transferred to SCIL at its net present value as per the books of accounts of UPL. SCIL has, therefore, acquired the facilities for the production of 5000 tpa Yellow Phosphorus from UPL, which were located at Ankleshwar, Dist. Bharuch in Gujarat. SCIL has now shifted these facilities to Jhagadia, Dist. Bharuch in Gujarat and the plant has re-commenced commercial production from June 14, 1999. SCIL has integrated backwards and has constructed and commissioned a combined cycle 50 MW Captive Power Plant in phased manner during 1997-1999 adjacent to the present location of Yellow Phosphorus facilities, for ensuring continuous and smooth supply of electric power at minimal cost for this power intensive process. SCIL is also proposing to convert its power plant fuel from liquid naphtha to natural gas to augment efficiency of the power plant and overall cost competitiveness for Yellow Phosphorus. SCIL who are presently having a capacity of 4000MTpa are in the process of commercialising another 2500 Mtpa and planning to set-up additional capacity of 3500 MTpa alongwith ancillary and auxiliary facilities for augmenting its capacity to 10000 MTpa of Yellow Phosphorus, as a part of expansion programme.

- (x) The stocks of Yellow Phosphorus with SCIL have increased significantly with the company. The company is saddled with an inventory of 296 MT in just about three months of its working, in spite of operating the Yellow Phosphorus Plant at 51% capacity utilization. In case the present trend of production and sales continues, the inventory with the company would reach about 880 MT, representing about 111 days production in stock. Evidently the company is finding it difficult to consume and market the goods being produced by it, in spite of restarting its operations with captive power. It is submitted that Yellow Phosphorus is a high value item and no company can afford to hold such high level of inventories. It would be extremely difficult to hold so high level of stocks and should the sales not pick up in the market, it may be forced to restrict the production again. It is also submitted that the company can not increase its captive consumption also from the present level as all the downstream products are operative at their optimum capacities.
- (xi) As the landed price of Yellow Phosphorus was much lesser than the cost of production, the company was forced to sell at prices significantly below cost of production, resulting in substantial discounts.
- (xii) Imports of Yellow Phosphorus in India has increased significantly in absolute terms from 5350 MT in 1993-94 to 16504 MT in 1998-99. The import volumes for 1998-99 quoted by them are based on extrapolation of the information provided by DGCI&S for the period April-Dec., 1998.
- (xiii) Based on their experience the demand of Yellow Phosphorus has not shown an appreciable increase and more or less stagnant over the past four years. The figures for the period 1994-95 to 1997-98 present a more realistic picture with regard to the demand of Yellow Phosphorus in India. The import figures include imports for export purposes also. It appears that excessive imports have taken place in 1998-99 resulting in build up of stocks. They feel that the imports in the year 1998-99 should not be considered to arrive at demand of Yellow Phosphorus in India and the same should be based on more realistic imports for

>

the period 1994-95 to 1997-98, for which authentic information with regard to imports is available.

- (xiv) They have now received the actual import data for 1998-99 from the DGCI&S which is 12388MT. They have also worked out the quantities of imports made by various parties from the information available in the Public file which works out to 13380 MT.
- (xv) The industry needs imposition of safeguard duty for a period of three years in order to enable it to effect positive adjustment plans and be competitive to face competition from the imports. They need immediate safeguard duty to the extent of Rs 50 per kg on all imports of yellow phosphorus, which can be progressively reduced commensurate with the economies in cost of production achieved by the company. The requested safeguard duty period of three years is based on implementation time of upto two years for expansion of the plant capacity by additional 5000 MT and another one year for stabilization of the production thereafter.
- (xvi) They have imported Yellow Phosphorus for helping them and in maintaining their competitiveness and increase their exports of Phosphorus derivative at most competitive prices. They would like to point out that the prices of various products produced using Yellow Phosphorus have not undergone any significant change as a result of cheap imports of Yellow Phosphorus. None of the importers and consumers of Yellow Phosphorus have passed on the benefits of cheaper imported Yellow Phosphorus. Cheaper imports have simply added to the bottom-lines of the importers/consumers.
- (xvii) Historically the producers of Yellow Phosphorus have been the main players in the business of both Yellow Phosphorus and its downstream products till early 1990s. At the same time, till early 1990s, the domestic production cost of Yellow Phosphorus was lower than imported material and this prevented new market entrants in the business of its downstream products. The above also necessitated setting-up of Yellow Phosphorus Plant alongwith its downstream plants for getting competitive edge over the existing producers of Yellow Phosphorus in the domestic market. But, the potential new market entrants neither had the technical expertise nor the financial resources to meet this prerequisite for entering this business. With the domestic cost of production exceeding the landed price of imported Yellow Phosphorus in early 1990s, many opportunistic market players entered this business of Yellow Phosphorus downstream products to cash on the sudden unexpected competitive advantage gained over the producers of Yellow Phosphorus. Since these companies resorted to imported Yellow Phosphorus (which was cheaper than the costs to the Yellow Phosphorus producers), they gained market advantages. These consumers of Yellow Phosphorus did not buy Yellow Phosphorus from the domestic producers in view of higher cost of producers in view of higher cost of production of the domestic producers as compared to imports.
- (xviii) The gross demand of Yellow Phosphorus in India during 1998-99 should be considered as 13000 MT which includes imports for export purposes. It is

1

estimated that the total duty free imports of Yellow Phosphorus in 1998-99 were in the region of 7000 MT, while imports required for export production were in the region of 4700 MT considering exports of related products. These imports includes imports under both the schemes, i.e. DEEC and DEPB. It is submitted that manner of imports under which duty free goods have been imported is not relevant for assessing the demand. What is required to be removed from the domestic demand is the imports which have taken place because of exports of downstream products, as these are the imports which have not entered the commerce of the country.

- (xix) M/s.Excel has merely suspended its production and has not stopped its production forever. Under the circumstances, the domestic industry can not be expected to have taken into account the demand requirements of Excel. The requirement of Excel is, therefore, required to be removed from the demand of Yellow Phosphorus in India.
- (xx) The price of Phosphorus derivatives have no specific relation to the import price of Phosphorus. While the prices of Yellow Phosphorus decreased by 18% during 1998-99 the price of Phosphorus Pentasulphide rose by 13% during the relevant period. Similarly the price of DETCL rose by 14%. The peak price of Yellow Phosphorus which was Rs.96/- in 1996 was absorbed in the then prevailing prices of Phosphorus Pentasulphide and DETCL. In respect of Phosphorus Trichloride, the domestic price has always been lower than its imported landed price due to over capacity in the domestic market. With regard to TMP the landed price has increased by 4% over a period from 1994-95 till date while the domestic prices decreased by 9% due to over capacity during the said period.
- (xxi) With regard to the adverse impact of the proposed safeguard duty imposition on the downstream industry and eventually on the pesticides formulations, Yellow Phosphorus is a material whose presence is much more critical than its prices. Such is the criticality of Yellow Phosphorus that Rs.50 crores Yellow Phosphorus industry is the base for Rs.3000 crores formulations industry. It is a matter of common knowledge for those in the pesticides industry that the prices of pesticides formulations have no bearing on the costs. In fact, according to industry sources the profit margin to the first point sale is even 100% or more. So wide is the gap in the cost of production and maximum retail price to the consumers that the possibility of any adverse impact as a sequel to imposition of safeguard duty on the cost-price structure of the pesticides formulations, is remote.
- (xxii) As regards measuring injury in terms of the cost of keeping the existing capacity idle as compared to the saving resulting from lower cost of Yellow Phosphorus used Excel has grossly erred in calculating injury. The company has considered cost of production as Rs.123.25 per Kg at 5000 MT, while the same would be Rs 105. Considering the landed price of imports, the higher cost comes to Rs.30 per Kg., which adds to Rs.8.25 crores for 2750 MT which UPL needs for the domestic market. However, the whole wrong hypothesis adopted by M/s.

>

Excel is the assumption that the cost of production will remain unchanged. It is submitted that in the fourth year, i.e. 2002-2003, the cost of production would be comparable to the imported price and there would be no extra cost, whereas Excel would continue to incur a recurring cost of Rs. 3 crores per year in case the plant is not run and kept idle. The issue is what the cost of production of SCIL would be at 2000, 5000, 6500 and 10000 MT production of Phosphorus per annum. The economics of Yellow Phosphorus production are significantly different at different production levels, as the power cost per unit would differ significantly depending upon the power plant utilization. In case the company does not undertake full scale production of Phosphorus its losses may be to the extent of Rs.30 crores per year.

- (xxiii) Public interest means maximum good of the maximum number. The imposition of safeguard duty would be in public interest since it would ensure much wider choice of suppliers to the consumers; ensure dependable supplier; eliminate political sensitivity: availability of the product at internationally competitive prices in the long run besides will be in the interest of state owned mining/rock phosphate industry.
- (b) Phosphorus and Chemicals Travancore Ltd. (PACT)
- (i) PACT is the only unit engaged in the manufacture of white/yellow phosphorus in South India with licensed capacity of 2500 MT per annum and installed capacity of 1000 MT per annum. It has a connected power load of 3000 KVA from Kerala State Electricity Board (KSEB). PACT provides employment to about 300 persons directly and indirectly.
- (ii) Rock Phosphate, Coke, Silica and Electric Power are the major raw materials for production of Yellow or White Phosphorus. The process for the manufacture of Yellow Phosphorus is a semi-continuous and involves conversion of Rock Phosphate into phosphorus in the presence of Silica and Coke by Electrothermal route. This process for the manufacture of Yellow Phosphorus is highly energy intensive due to endothermic reactions. This energy is made available through heat generated by electric energy which is being obtained from the Government of Kerala. However, with steep increase in the power tariff to Rs. 2.50 per unit by the Government of Kerala recently apart from annual increase by 10% which is already existing, their operations have become completely unviable and they have been forced to suspend the production. The company has been implementing a Mini Hydel Power project, which would not only ensure continuous and uninterrupted power to PACT, but also reduce the cost of power for production of Yellow Phosphorus substantially.
- (iii) Domestic production of Indian industry has declined by 87% in the five years from around 4750 MT in 1994-95 to around 612 MT in 1998-99. PACT was able to continue its production in view of relatively much lower power tariff in the State of Kerala. However, the Government of Kerala also increased power tariff in May, 1999 to Rs. 2.50 per unit apart from annual increase by 10% which is already existing. The variable cost of production of PACT has increased significantly with this steep increase in the power tariff and the variable cost of

1

production of PACT is now higher than the landed price of the imported Yellow Phosphorus. PACT has also been forced to suspend production since end of May, 1999.

- (iv) The capacity utilization of the Indian industry has reduced from around 46% to 6% in five years. This is mainly due to increase in imports from 48% to around 94% over the period forcing the Indian industry to reduce the production drastically.
- (v) The domestic producers one after the other have been forced to suspend/curtail their production in view of increasing uncompetitiveness.
- (vi) PACT has not been able to sell its production to the extent of available capacity. The domestic industry has been forced to reduce its selling prices in view of significantly lower landed price of imports. Further, even the current selling prices which as such does not permit recovery of even raw material cost are higher than the landed price of imports. The imports are thus causing severe price undercutting in the market.
- (vii) They have been forced to sell their produce at prices significantly below the cost of production, resulting in severe financial losses. The imports of Yellow Phosphorus in India have very severely injured the domestic industry. The injury can be removed by imposing Safeguard Duty amounting to at least Rs.50/- per kg. on all imports of Yellow Phosphorus.
- (viii) PACT had about 102 persons in its rolls in 1996-97. The company has resorted to layoff of the manpower in view of its inability of produce and sell at present prices. Should the company not be able to restart its production, all the employees would loose employment
- (ix) PACT is modifying the furnace at a cost of Rs. 80 lacs, which would increase the efficiency of the furnace both in terms of production as well as cost. This modification is expected to increase the plant capacity utilization and increase the capacity itself by about 30%. Similarly, the modification in the furnace is expected to improve further plant operational efficiency over a period of time. This would facilitate reduction in unit consumption for the raw materials (power, rock phosphate, coke) and distribution of fixed costs over larger volumes. This is expected to significantly reduce the cost per MT of Yellow Phosphorus.
- (x) Power is the major raw material for Yellow Phosphorus, constituting more than 50% of the total cost of production. The company has signed a preliminary agreement with the Kerala State Electricity Board (KSEB) based on Kerala Government notification and got sanctioned a mini hydel power plant of four MW capacity. The company has already got prepared and submitted the Techno Economic Feasibility Report to the Kerala State Electricity Board (KSEB). This detailed feasibility study has been done by an outside agency, who is expert in this area. This project, when implemented by PACT, will ensure relief not only in terms of continuous power supply to the Yellow Phosphorus plant, but also availability of power at much cheaper rates.

#### C. <u>VIEWS OF IMPORTERS AND USER INDUSTRIES</u>

#### 10.(a) Pesticides Manufacturers

The Pesticide industry in general have made the following main points.

- (i). They have studied the petition and are deeply concerned about the proposal to impose a steep safeguard duty of Rs.50/- per Kg. which is equivalent to approximately 120% additional duty on import of Yellow Phosphorous. If this duty is imposed, then it will increase the cost of Phosphorous based intermediates substantially, which go into the manufacture of pesticide technicals.
- (ii) Pesticides business is highly competitive with very low margins and therefore, this additional cost will have to be passed on to customers i.e. the farmers, who are already under acute financial pressure.
- (iii) UPL/Search Chem Industries being major White/Yellow Phosphorous manufacturer and competitors in most of the technicals their request to impose safeguard duty will only put them in a position to unfairly dominate the pesticide industry by controlling this key raw material which is used in the manufacture of all organo Phosphorous pesticides.
- (iv) If safeguard duty is imposed they may be forced to shut down production of Phosphorous based pesticides and will not be competitive with the landed costs of imported pesticides. The objective behind the Safeguard Duty is to protect the domestic industry and not just two or three companies. The result of this proposed safeguard duty which may protect two to three companies, will result in the closure of a large number of units giving virtual monopoly to the Petitioners. This Safeguard Duty is bound to give the applicants a virtual monopoly in the manufacture and supply of Yellow Phosphorous which is a vital raw material for pesticides industry.
- (v) The imports were undertaken mainly because of the fact that the domestic manufacturers were not in a position to supply adequate quantities at competitive rates. The prices at which the product is getting imported into India is in line with the international price and as such no special concession or consideration has been shown while effecting supplies to Indian manufacturers/Importers, by the suppliers.
- (vi) If safeguard duty is imposed, the pesticides manufactures may be forced to shift buying of phosphorous based intermediates to international market from current local market. It is important to note that, international users of Yellow/White Phosphorous and manufacturing similar products will automatically have the competitive advantage to their favour. This may also result into the loss of export business to a substantial extent. As a matter of fact today also some of the export orders are lost just because Indian prices are higher by 1 to 1.5% than that of a supplier based in other developed countries.

7

~

- (vii) There may be a possibility that cost of production of pesticides consequent to the above imposition of duty may be very high encouraging thereby import of technicals directly from different countries. If such a situation arises, many companies may be forced to either cut down production, to start with, or go out of business in the long run.
- (viii) The entire pesticide industry is passing through a difficult phase. The local industry is still to recover from the impact of globalisation and there has been a severe competition with multi-national companies both in the domestic and international market. Any proposed increase in the duties of Phosphorous is detrimental to the interest of the agrochemical industry.

Besides these main points, some of the parties have made following additional submissions:

- (a.1) Sandhya Organic Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai-400 057.
- (i) They are manufacturers of Pesticides/Insecticides and Phosphorous based compounds (Aluminum Phosphide and Zinc Phosphide) over a period of 16 years which are being supplied to Food Corporation of India, Central Warehousing Corporation, Punjab Warehousing Corporation, Haryana Warehousing Corporation and Others which are Central/State Government bodies. Phosphorous based chemicals namely Phosphorous Oxychloride, Phosphorous Trichloride and Phosphorous Pentoxide are being supplied to Pharmaceutical and Dyestuff Industries.
- (ii) Since UPL and SCIL are their competitors, they have never offered them White/Yellow Phosphorous in the past and they will never offer any quantity in future too. The imposition of Safeguard Duty should not be implemented to enable them to import White/Yellow Phosphorous freely to cater to the requirement of Central/State govt. departments, otherwise their unit may close which will leave many workmen unemployed.
- (a.2) Cheminova, India Ltd., Mumbai.
- (i) The agrochemical industry is the major end-user industry for Yellow Phosphorus and its compounds. It is estimated that over 70% of Yellow Phosphorus is consumed for the production of organo Phosphorus (OP) pesticides.
- (ii) It is estimated, that the total annual domestic demand for Yellow Phosphorus is around 18000 MT. The major two products which are manufactured from Yellow Phosphorus are Phosphorus Trichloride (PCL3) and Phosphorus Pentasulfide (P2S5). It is estimated, that around 74% of the production of PCL3, 72% of the production of P2S5 and 30% of the production of Red Phosphorus is used for the production of pesticides in India.
- (iii) The production of Yellow Phosphorus (YP) has fallen in Europe and N.America over the last decade in response to key "market fundamentals".

Demand for YP has also fallen as Purified Wet Acid, a cheaper substitute for thermal acid produced from Yellow Phosphorus became available. YP continues to be in demand for the production of non-phosphate Phosphorus derivatives. European and N.American producers then decided in the late 1980s' to close down their plants of YP and to import YP at much cheaper rates from China, in order to produce non-phosphate Phosphorus derivatives at internationally competitive rates.

- (iv) China is a country with approximately 60 producers of YP and the factories are located in 4 major provinces of China. China has an abundance of easily mined high quality phosphate rock, coal, onsite furnaces and sources of hydroelectric power and much cheaper financial costs for investment and working capital. This has given the Chinese manufacturers great advantage in manufacturing YP at low cost. It is estimated that around 250,000 MT of YP is being produced in China today and approximately 50% of this production is being exported to all parts of the world.
- (v) The demand for YP in India has increased significantly during the last decade. This has primarily been caused due to the increased demand for the derivatives/intermediates PCL3/TMP and P2S5 in the pesticide industry. During the 1970s and early 1980s YP plants were put up in India in order to cater to the captive requirements for making intermediates and pesticides. However the demand for the derivatives/intermediates grew and became larger than the domestic capacity. Consequently in order to meet the growing demand for these, the import of YP derivatives started.
- (vi) Manufacturers of organo Phosphorus pesticides initially imported high valued derivatives such as TMP and DETCL from developed countries. However, as the demand for these products increased, many decided to manufacture the same derivatives indigenously based on imported YP. The decision to manufacture YP derivatives indigenously based on imported YP has turned out to be a tremendous success for the industry and for India. It is important to note that easy availability of high quality and low priced YP from China has given the Indian producers of YP derivatives the same cost advantage as their counterparts in Europe and N.America. Not only has India become self sufficient in most of the YP derivatives but India has now also become a serious exporter of high quality YP derivatives such as PCL3 and TMP. The imposition of a Safeguard Duty would cause serious injury to all the manufacturers of YP derivatives.
- (vii) It is not the imports of YP which reduced domestic production but it was the calculated decision of the then manufacturers of YP to import YP in order to produce derivatives/intermediates more economically and safeguard their interest against import of these products.
- (viii) The production capacity of YP in India is estimated to be around 3000MT only. As against this, the annual domestic demand for YP is around 17,000 MT. The demand is expected to reach 19,000MT in the year 1999-2000. It is evident that the domestic available production capacity of Yellow Phosphorus will not be

able to meet the demand. In fact the domestic available production capacity only represents around 15% of the total domestic demand of 19,000 MT. Large imports of Yellow Phosphorus are therefore inevitable in the future.

- (ix) Technology for manufacture of Yellow Phosphorus is around 50 years old and very well established in terms of inputs, usage ratios etc. It is, therefore, worth noting that despite being in continuous production for over 17 years, the domestic industry could not bring down the cost of production to international level. Since the industry is extremely power intensive and considering the fact that power and petroleum cost in India are continuously rising, it is unlikely that cost of producing Yellow Phosphorus in India can be brought down to current prevailing international price levels. Also scaling-up production capacity would not benefit from economies of scale on account of the fact that power alone constitutes 50% of the cost of production of Yellow Phosphorus while other variable costs account for 30-45% of the total cost.
- (x) The application for imposition of Safeguard Duty has been made by SCIL who are supposed to have started manufacturing Yellow/White Phosphorus only from 14.6.99 as per the statement made by them in the Petition. They have therefore, no past history of manufacturing Phosphorus and therefore they are estopped from alleging that the increased imports have caused serious injury to them, as they never manufactured YP in the first place. SCIL, therefore, have no locus-standi in this matter. Similarly the co-petitioner UPL by virtue of the fact that they have already discontinued the production of Phosphorus in September 1996, have no locus-standi in this matter. PACT are very small producers of Yellow Phosphorus with production capacity of less than 1000 TPA and are catering to two of their sister concerns who are manufacturing Red Phosphorus. Their market share is negligible and hence, they hardly have any locus-standi.
- The demand for the Phosphorus intermediate DETCL in India is (xi) significantly larger than the current local supply and an estimated quantity of approximately 3000 MT/year of DETCL was being imported into India in 1998. In the beginning of 1999 they initiated a large investment for setting up a 5000 Considerable work and MT/year DETCL manufacturing plant at Panoli. investment has already been committed in order to get this plant commissioned by June 2000 and the plant is expected to employ about 100 people. This would enable India to become totally self sufficient in its requirements for DETCL and for meeting future requirements. The imposition of a Safeguard Duty of Rs.50 per Kg. on Yellow Phosphorus would cause serious injury to them and would probably result in the shelving of the DETCL project since the investment was justified and approved on the basis, amongst others the prevailing imported Yellow Phosphorus prices.
- (a.3) Nagarjuna Agrichem Ltd., Panjagutta, Hyderabad-500 082
- (i) Unlike many other countries, Insecticides play a very key role in the crop protection segment of Indian Agriculture. Insecticides account for over 70% of the value of crop protection products sold in India. The most widely used insecticides in India currently are Organo-Phosphates. Products such as

Monocrotophos and Chlorpyriphos can be considered as the number one and two products country wide in volume usage terms. There are many other products such as DDVP, Quinalphos etc. that are also very widely used. All these Organo-Phosphate insecticides are primarily derived from Phosphorous based compounds. Any increase in the raw material cost of Phosphorous will result in increased input costs of the Indian Farmer.

- (ii) Agro-chemicals play a major role in export earnings for India. Exports of Agro-Chemicals are growing at a rate comparable to Pharmaceuticals. In an already competitive export market, if they increase cost of production of Organophosphate insecticides, there will be an immediate downward trend in export sales, which will be contradictory to a stated government policy to increase exports from India.
- (iii) A poor business decision primarily on the part of UPL, cannot be rectified through government intervention. While UPL and its subsidiary Search Chem may benefit tremendously, the Indian farmer, crop productivity and many good companies like Nagarjuna will pay a very steep price.
- (iv) UPL has made substantial investments into setting up a sophisticated power generation facility at Search Chem. The Gujarat state electricity board has decided not to buy power from Search Chem, therefore the only option left to Search Chem is to sell power to UPL. The most power intensive operation at UPL is the production of Phosphorous. Therefore, unless UPL manufactures Phosphorous and uses power generated at Search Chem, Search Chem will not be a viable company in the foreseeable future. It is not the government's responsibility to rescue UPL from its troubled investment at Search Chem.
- (vi) Many companies including Nagarjuna have made decisions to backward integrate their manufacturing processes. They have spent substantial resources to make technical grade Acephate from a raw material called DMTC. However, an intermediate called DMPAT is now available as a cheaper alternative from China. Making Acephate from DMPAT is more cost effective and they have, therefore, changed their process to use DMPAT. They are not approaching the government to impose protectionist duties on DMPAT imports and thereby gain a competitive advantage.
- (a.4) Excel Industries Ltd., Mumbai-400 102.

\*

(i) During the period 1970-92 most of the companies producing Yellow Phosphorus were converting it into intermediates Electricity is the highest cost element in the manufacture of Yellow Phosphorus and the consumption is approximately 14000 kWh per MT of Yellow Phosphorus. With the spiraling costs of electricity in India, particularly in Maharashtra and Gujarat (where the Yellow Phosphorus plants are located), it became unviable to manufacture Yellow Phosphorus in India and compete against the imports from China, Russia, Bulgaria, Kazhakhstan and such other countries. Hence, Star, UPL and Excel, in that order, decided to close down their Yellow Phosphorus production and

≺

resorted to import the same for production of value added intermediates. This situation has been operating in the last 5 years.

- (ii) M/s. Phosphorus and Chemicals Travancore Ltd. (PACT) who were the other Yellow Phosphorus producing company with their plant in Kerala based on their cheaply available Hydroelectric Power, were at an advantage against Star, Excel and UPL and were able to produce a paltry 500 MT per year for over 10 years. They do not have any other product based on Yellow Phosphorus and hence were the only company selling all the Yellow Phosphorus produced whereas Star, Excel and UPL have always been consuming almost their entire portion of the Yellow Phosphorus produced for their captive use.
- (iii) Yellow Phosphorus derivatives has been the main business of UPL/SCIL and not Yellow Phosphorus itself. Large part of their Yellow Phosphorus was being consumed by themselves captively and an insignificant quantity was being sold to outside parties.
- (iv) There has been an extremely low merchantability of Yellow Phosphorus produced in India. The other direct consumers of Yellow Phosphorus have always been importing as the domestic production was far short of total consumption in India. This fact is borne out by the statistics presented by the petitioners themselves as the total installed capacity is 10,000 MT against total consumption of over 16,000 MT. The values of intermediates produced by these three companies namely Star, Excel and UPL alone is estimated at Rs.150 Crore while the value of Yellow Phosphorus consumed is estimated at Rs.45 Crores.
- (v) UPL had also kept their Yellow Phosphorus furnace closed since 1996. In order to enhance the capacity utilization of the captive power plant installed in their group company SCIL, their furnace was shifted and reinstalled in SCIL. Even then the capacity will only be about 4000 MT against India's consumption of 16,000 MT. With the domestic production being so insignificant it is unjustifiable to impose safeguard duty thus making the entire industry unviable. In fact UPL themselves stand to lose as the end products manufactured by them will start getting imported if the Yellow Phosphorus is rendered much costlier than prevailing today.
- (vi) As an industry standard, approximately 14,000 kWh of electricity is required for the production of each MT of Yellow Phosphorus. Valued at Rs.5 per kWh, the cost of electricity itself is Rs.70 per Kg. of Yellow Phosphorus. With Rock Phosphate and Coke being the other raw materials, the variable cost is approximately Rs.95 per Kg. of Yellow Phosphorus. With normal overheads and minimum profit, in their estimate Yellow Phosphorus can be sold, when produced locally, at not less than Rs.110 per Kg. There is no possibility of reducing this cost of production significantly unless the cost of electricity itself is reduced. A 3000 MT per annum plant of Yellow Phosphorus requires a connected power of about 6 MW and thus, individual plants of Yellow Phosphorus can not establish captive power plants. The range of power needed is too small for thermal power plants but too large for DG sets. SCIL had established a power plant for supporting the Caustic Chlorine plant and have

surplus power available for utilizing in the Yellow Phosphorus plant transferred to them from UPL. It is not known to them as to what will be the cost of power input to the Yellow Phosphorus plant and to what extent the cost of production of Yellow Phosphorus can be reduced. But this situation is unique only to SCIL. If Safeguard Duty is imposed on Yellow Phosphorus, only SCIL stands to gain, with the distinctly unfair advantage over other producers of Yellow Phosphorus in India and at the cost of entire Pesticides Industry, Automotive Industry and Defence and the Indian farmer at large. There is no truth in argument that SCIL can reduce the cost of production by increasing the installed capacity.

- (vii) The cost of production of Yellow Phosphorus by UPL in the year 1994-95 was Rs.91.20 per Kg when the cost of electric power was Rs.2.61 per kWh. The cost of generation of power in SCIL is Rs.3.60 per kWh at present. Even if, by adoption of various measures, SCIL is able to reduce the cost of generation of power from Rs.3.60 per kWh to Rs.2.61 per kWh, it can be inferred from the above that the cost of production of Yellow Phosphorus is likely to be in the range of Rs.91 per Kg., 36% higher than the current landed cost of Yellow Phosphorus even with 45% import duty.
- (viii) The Applicant's contention that the requirement of Yellow Phosphorus for manufacture of Yellow Phosphorus derivatives which are exported, should not be taken into account for estimating the demand for Yellow Phosphorus since such imports are duty free and will not attract safeguard duty is not correct since a large part of Yellow Phosphorus derivatives are being exported under DEPB Scheme and not under Advance Licence Scheme. Accordingly, the imports of Yellow Phosphorus which are not under Advance Licence Scheme, will attract safeguard duty and hence will have to be taken into account for the purpose of estimating the demand for Yellow Phosphorus.
- (ix) A Yellow Phosphorus Plant of a capacity of 5000 tpa would cost about Rs.10 crores. The costs in the form of interest @ 15% per annum and depreciation @ 10% per annum would be about Rs.2.50 crores and with other estimated cost of Rs.50 lacs, the total cost of keeping the capacity idle would be in the range of Rs.3 crores. As against this, the saving resulting from the lower cost of Yellow Phosphorus used for manufacture of Yellow Phosphorus derivatives will be Rs.24.13 crores every year being the differential between the cost of production and the landed cost, which is more than the total investment in the Yellow Phosphorus Plant itself. At Excel, the cost of keeping the Yellow Phosphorus plant of 3000 tpa capacity idle (put up at a cost of Rs.6 crores) works out to Rs.1.54 crores every year on account of depreciation at the rate of 10%, interest at the rate of 15% and insurance at the rate of 0.6%. resulting in savings of Rs.14.40 crores.

#### (a.5) Star Chemicals (Bombay) Ltd., Mumbai

(i) They have been manufacturing phosphorus and its derivatives since around 1970. Their existing manufacturing activities include the manufacture of Phosphorus derivatives viz. Phosphorus Pentasulphide, Red Phosphorus, Phosphorus Trichloride, Phosphoric Acid (Technical and Food Grades) etc. at

their plant located in Maharashtra. Manufacture of phosphorus has been suspended by them since mid 1993. They were the major supplier of White /Yellow Phosphorus to the actual users, since 1970. Until suspension of production in mid 1993, their market share of White Yellow/Phosphorus was around 80%. In fact until UPL commenced its own production of White/Yellow Phosphorus (around 1980), they were catering to their requirements of White /Yellow Phosphorus.

- The unfavourable domestic cost of production mainly due to steep cost of (ii) power coupled with availability of cheap imports from China compelled UPL to suspend production of White/Yellow Phosphorus since 1996-97. UPL have been and still are amongst the biggest importers of White /Yellow Phosphorus in India from China. It must be stressed that at no stage in the history of UPL, they were active suppliers of White/Yellow Phosphorus to the actual users and very negligible quantities were sold by UPL to the actual users. Excel commenced manufacture of White/Yellow Phosphorus almost entirely for its captive requirement, in or around 1972. Due to unviable costing they too have suspended production of White/Yellow Phosphorus since 1996-97 and are also one of the biggest importers of White/Yellow Phosphorus. PACT put up a small plant in Kerala with installed capacity of 1000/MT per annum mainly due to availability of cheap hydel power. However, their operations have always been erratic on account of power cuts and labour problems. They have captive requirement of White/Yellow Phosphorus in production of Red Phosphorus through their two associate companies viz. Kalpataru Chemicals Pvt. Ltd. and Sri Majentha Chemicals (P) Ltd. They have also suspended production of White/Yellow Phosphorus.
- (iii) In their experience of operating a White/Yellow Phosphorus plant till mid 1993 and based on data of the current price levels of various inputs, the estimated cost of production of White/Yellow Phosphorus for SCIL and PACT which operate on cheap power sources should not exceed Rs.60/- Kg. approximately. The cost could be even lower depending on the source of rock phosphate, the key raw material for White/Yellow Phosphorus production. The costs will reduce further to a very large extent when the production is scaled upto 5000 TPA from March 2000 and further when production is scaled upto 10000 TPA at a subsequent stage as planned by SCIL. The manufacturing plants are fairly old, in operation for about two decades, fully depreciated and hence overall fixed costs would be substantially lower.
- (iv) The application for Safeguard duty by UPL/SCIL is opportunistic and timed to create irreparable and unjust harm to the user industries. Moreover, it would result in unjust profits by SCIL with an intent to wipe off huge losses suffered by SCIL on account of the depressed market condition for their Chloroalkali products (due to over capacity) and surplus captive power plant capacity.
- (v) It is feared that while UPL/SCIL may continue to avail of duty free imports of White/Yellow Phosphorus against their exports of Phosphorus derivatives and Pesticides, their competitors manufacturing Phosphorus based

>

derivatives will be forced to procure Phosphorus at higher prices making operations unviable due to imposition of Safeguard duty, if any.

## (a.6) Gharda Chemicals Ltd., Mumbai-400 050

The price for phosphorus (white/yellow) has been in the range of USD900 to 1050 per MT. This pattern has been noticed for the last several years. With the weakening of rupee against dollar, Indian importers are effectively paying more price for the imported item compared to what was happening earlier. Against the present import price which works out to Rs.43/- per kg of yellow phosphorus imposition of safeguard duty of Rs.50/- against the present custom duty of Rs.20/- per kg. is totally uncalled for and unjustified particularly when the global price of phosphorus is not more than USD 1000 per ton.

- (a.7) M/s. STS Chemicals Ltd., Mumbai; M/s.Sabero Organics Gujarat Ltd., Mumbai; M/s.Watsol Organics Ltd., Hyderabad; M/s. Star Chemicals (Bombay) Ltd., Mumbai have also made in addition to what has been stated above, the following common submissions:-
- (i) The production capacity of the Indian manufacturers of Yellow Phosphorus claimed by the applicants in their application is misleading, as admittedly Excel has since 1996 discontinued the manufacture of Yellow Phosphorus and has not stated their intention to restart manufacture. The effective production capacity is, therefore, realistically at a level of 6000 MT. The hypothetical production capacity is required to be examined in the context of the following critical factors to determine the effective capacity available of the product in the domestic market. The existing capacities of both UPL and PACT cater mainly to the requirements of their sister concerns.
- (ii) UPL/SCIL require a minimum of 5000 MT of Yellow Phosphorus for the production of PCl3, P2S5 and their other products. Historically UPL has been and continues to be one of the largest importer of Yellow Phosphorus into India. This establishes that even in a situation where the manufacturing facilities were fully functional they were not adequate to fully satisfy the requirements of UPL. Consequently the real ability to address the requirement of local market is illusory. This position is indisputable in terms of the past conduct, where miniscule quantities, if at all, were offered into the local market.
- (iii) The past reluctance/inability to offer the product into the local market is further enhanced by certain contractual and business arrangements between UPL and SCIL. It appears from the prospectus of SCIL's Public issue on 26.02.99 interalia, that SCIL shall give preference to the requirements of UPL amongst all its buyers and, as far as possible, make all reasonable efforts to meet the requirement of UPL first in case it is unable to supply full quantities to all its buyers at any point of time; so long as by giving such preference, the Company does not violate any law or the conditions of license or permits granted by the Government or giving such preference to UPL does not result in any loss to the Company ... The company agrees to supply Phosphorus Trichloride to UPL of whatever quantity required by them throughout the currency of this Agreement at

a price to be mutually decided at the beginning of each year and the said price including excise duty, sales tax etc. is currently fixed at Rs.30,000/- per MT. The Annual Report of SCIL for the year 1998-99 also states that the company is also installing a plant to manufacture elemental Phosphorus which is a main input of the company; suggesting manufacturing Phosphorus to meet their captive needs.

- (iv) PACT's effective production capabilities are heavily influenced by the uncertain power availability in Kerala. Its ability to offer goods in the local market is also circumscribed by the captive consumption needs of its sister concerns/associate companies viz. Sri Majentha chemicals Pvt. Ltd. and Kalpataru Chemicals Pvt. Ltd.
- (v) The demand for Yellow Phosphorus in India is 18,000 MT. The effective manufacturing capacity of the Indian Manufacturers is merely 3000 MT, which is primarily meant for captive consumption. The effective ability of Indian manufacturers to address the local market is indeterminate and inconsistent, and can at the highest, address only a very small percentage of the ever growing demand. There is a significant and insurmountable demand-supply gap for Yellow Phosphorus in India, which renders large scale imports of Yellow Phosphorus inevitable. Further the plans outlined by the Applicants do not indicate any ability or inclination in the short term to bridge this gap.
- (vi) The down stream user industry in India includes *interalia* the organophosphorus pesticides, fertilizers and match industry which today account for production, sales, revenue contribution, export earnings and employment collectively at a level 10 to 15 times greater than the comparative figures for the Applicant domestic producers. The flow of the product from the Applicant companies is uncertain and erratic. The pricing of the product is non-competitive Any levy of safeguard duty will directly result in a situation where the down stream industry will be wholly dependent on a erratic supply source and will be burdened with a levy which will render their own products non-competitive and unmarketable
- It has been claimed that SCIL is finding it difficult to run its plant in view of cheap imports of Yellow Phosphorus. SCIL has been making huge losses over past few years. In this connection it is pertinent to note that the financial woes of SCIL began with the setting up a 50 MW independent power plant at a cost outlay of Rs.200 crores. The applicants have failed to mention that the independent power plant was set up with the intention of providing power for the Caustic Chlorine plant and excess to the Gujarat Electricity Board (GEB) Unfortunately for SCIL, their Caustic Chlorine plant ran into trouble and further the Power Policy changed and hence they were left with a power plant that operated only at 40% capacity and its bottom line plummeted from Rs.5 crores post tax profit in 1996-97 to a loss of Rs.49 crores in 1998-99. UPL had to transfer its Yellow Phosphorus manufacturing facility to curb the losses of SCIL. Low capacity utilisation of the power plant coupled with high depreciation and finance costs as well as the problem with Chlor-Alkali industry are reasons why SCIL is virtually a sick company and the difficulty in running the newly set up Yellow Phosphorus plant profitably should not be attributed to the imports of Yellow Phosphorus but

to the SCIL's unsuccessful foray into power generation and Caustic Chlorine manufacture.

- (viii) In addition, the transfer of power intensive yellow phosphorus manufacturing facility to SCIL by UPL was with a view to produce Yellow Phosphorus to be captively consumed as raw materials for its core products i.e. PCl3,P2S5. This application appears to be made by UPL as a tool to secure a financial edge over the other local manufacturers of PCl3,P2S5 as also to control for their own benefit the Yellow Phosphorus market.
- The entire safeguard proceedings are product specific. The information as regards various other products or various other streams of activity of the Applicants has clouded the issues and is not relevant to the issues under consideration. As the levy is sought for a product, the onus is on the Applicants to furnish information relevant to that particular product. UPL suspended production of Yellow Phosphorus in 1996 and only recently has SCIL started production of the same. UPL have however referred to figures of loss even in the period when Yellow Phosphorus was admittedly not manufactured. The onus was on the Applicants to establish injury relevant to the product. It is submitted that UPL is a multi product company involving over 50 products with a total turnover exceeding Rs.500 crores. Yellow Phosphorus accounts for only around 5% to 6% of their total business. No where in their audited annual reports of last few years have they mentioned this important fact that losses are accruing on account of Yellow Phosphorus. In the annual report for the Year 1996-97, the Directors have stated that the drop in profit from Rs.57 crores to Rs. 32 crores was mainly on account of high interest costs with no mention whatsoever of Yellow Phosphorus.
- (x) The Applicants have constantly raised the issue of price of the imports of Yellow Phosphorus as being extremely cheap and that the cost of production of the Indian Manufacturers of Yellow Phosphorus was considerably higher than the selling price of the imported Yellow Phosphorus. The primary grouse of the Applicants appears to be low priced imports, the appropriate proceedings for which clearly are not Safeguard but Anti-dumping proceedings. In this context, it is believed that the Applicants had tried to initiate Anti-dumping proceeding but were not successful. In any event since the Applicants are themselves significant importers they are disqualified from Anti-dumping proceedings. The present proceedings have been initiated not because the required ingredients for the imposition of safeguard are satisfied but on account of the disqualification in initiating the appropriate proceeding.
- (xi) The Applicants have failed to mention that UPL suspended its operations because of the high cost of power coupled with the fact that it is more profitable to import Yellow Phosphorus than to produce it indigenously Further the Applicants have failed to mention that they alongwith PACT are one of the major importers of Yellow Phosphorus.
- (xii) The Applicants have failed to mention that Excel has not joined the application as it has no intention of producing Yellow Phosphorus in the future as is evident from their letter of protest against the imposition of Safeguard Duty on

1

the import of Yellow Phosphorus. Secondly the Applicants have omitted to mention that nearly the entire production of Yellow Phosphorus is captively consumed by their sister concerns/associate companies.

- (xiii) The Applicants are seeking an extraordinary protection and it is a mandated statutory onus cast on them to present all relevant facts in an accurate and transparent manner. In view of what is set out above it is apparent that the Applicants have failed to discharge this onus. This Applicant consequently stands vitiated and is rendered non-actionable.
- (xiv) In terms of the Agreement of Safeguards, for a finding of serious injury the relevant product must be imported into the community in greatly increased quantities. Therefore it is not sufficient that there is a certain quantum rise. The quantum rise which is required must be "significant". These issues are also required to be examined in the context of the factors which caused the imports when appraising whether there is a great increase in the percentage of market share of imports. If the reason for imports is that there is demand in the local market which is required to be serviced owing to the incapability of the domestic industry then such imports cannot be seen as injurious.
- In the context of safeguards, what is required is 'serious injury' as (xv) distinguished from 'material injury' which is the benchmark in anti dumping investigations. Under the Agreement it is qualified that to justify the levy the imports must cause a significant overall impairment to the domestic industry. Judicial interpretation and precedent requires that one cannot obviate or overlook the use of the word 'significant'. The threshold of injury required is more than in case of other actions. It is to be seen whether the factor of 'serious injury' is satisfied or not in this case. In this background the Annexure to the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 ('the Safeguard Rules') is reflective of what is stated in the Agreement and identifies certain parameters on which we must benchmark whether or not there is injury. It is submitted that it is the confluence of all those identified factors, which must be considered to come to the finding of whether 'there is or there is not serious injury'. It is submitted that it would be unsustainable to find serious injury on only some of the identified factors. In the present case since the Applicants have: (a) Voluntarily at some stage discontinued manufacture (b) Manufactured primarily for captive consumption which demand is constant (c) Have had very limited quantities of Yellow Phosphorus to offer in the domestic market, they have no sustainable basis to claim injury.
- (xvi) The Applicants have claimed that the cheap imports of Yellow Phosphorus have caused reduction in production and sales and consequently many of the domestic producers have either suspended their production of Yellow Phosphorus or stopped production of the same altogether. It is submitted that the Applicants have themselves throughout the Application stated that, the domestic industry has been adversely affected by the increasing domestic cost of electricity coupled with cheap imports (due to reduction of Customs Duty). The local manufacturers have simply not been able to manufacture Yellow Phosphorus at competitive international prices mainly because of the high cost of domestic power which has

#

>

increased significantly over the last few years and it would be incorrect to attribute the reduction in production and sales and idling of capacities of the Applicants to the imports of Yellow Phosphorus. In this connection it is interesting to note that the domestic cost of electricity per unit over the past few years was as under:

Year	Electricity (Rs. per Unit)
1994-95	2.51
1995-96	2.46
1996-97	3.22
1997-98	4.16
1998-99	4.69
1999-2000	4.90

(xvii) Under the Agreement and the Safeguard Rules, what is required is not merely an erosion of price but price undercutting and significant price undercutting. In the present proceeding there is no significant price undercutting. A situation where prices are falling globally and the pricing in India is only reflective of that pricing, it is not a situation of price undercutting. Undercutting requires a conscious effort of lower pricing in a market to penetrate that market viz. predatory pricing. Throughout the period 1994-99 as mentioned in the Petition, it is worth noting that the landed price of Yellow Phosphorus into India irrespective of the country of origin has been more or less uniform, which clearly indicate that the price quoted are true and fair price applicable globally.

(xviii) It is also significant that in the year 1994-95 when the divergence between the claimed landed cost for imports and the cost of production was approximately Rs.18 there was no claim of injury whereas in 1999-2000 when this divergence is approximately Rs.10 the Applicants are claiming significant injury.

- (xix) The Applicants have alleged that owing to the import of Yellow Phosphorus they are now meeting a meager four percent of the local demand. It is submitted that the effective manufacturing capacity of the Indian Manufacturers is merely 6000 MT, which is primarily meant for captive consumption therefore the question of erosion of market share does not arise as the Applicants neither have the capacity nor inclination to meet the domestic demand.
- Phosphorus exported to India. However these imports are duty free as they are against Advance Licences. It is submitted that the fact of UPL being one of the largest importers of Yellow Phosphorus shows that imports are essential to meet the demand as well as the captive requirements of the domestic industry. As stated earlier this application appears to be made by UPL as a tool to secure a financial edge against the other local manufacturers of PCI3, P2S5 etc. which are its core products, and which are also used captively to make further value added pesticides brand on the phosphorus building blocks.

Ė

4

11

(xxi) The application states that more than 400 persons have lost their jobs as they have been re-deployed. It is submitted that re-deployment does not tantamount to unemployment. However it is pertinent to note that several thousand persons are employed directly or indirectly by the manufacturers of phosphorus derivatives and pesticides. There is an employment threat for the thousands, should there be a levy of Safeguard duty on Yellow Phosphorus as it would result in hundreds of small, medium and large manufacturing units becoming unviable and would expose the personnel directly/indirectly employed in such industries to unemployment.

(xxii) The Applicants have claimed that a provisional duty must be levied. It is submitted that in order to levy a provisional duty the Applicants would have to prove the existence of 'critical circumstances' which is an even higher threshold requirement than 'serious injury'. Therefore as the Applicants are not even close to establishing serious injury the question of the existence of 'critical circumstances' does not arise.

## (b) Chemical Additives Manufacturers

In the event of imposition of SGD on Yellow Phosphorus there will be a huge increase in the price of Phosphorus Pentasulphide being supplied to them and will force them to increase the price of finished chemical additives to oil industries. They will not remain competitive and the oil industries will source their chemical additives by way of import which will affect the foreign exchange reserve of the country.

## (c) Drug Intermediates Manufacturers

They procure Phosphorus derivatives such as Phosphoric Acid and Phosphorus Pentoxide from local manufacturers. In the event of imposition of safeguard duty on White/Yellow Phosphorus, the cost of phosphorus derivatives will go up and in turn cost of their finished product, which will make them non-competitive in domestic as well as export market.

## (c.1) M/s. Rencal Chemicals (India) Ltd.

In addition, M/s. Rencal Chemicals (India) Ltd., New Mumbai have stated that 90% of the Phosphorous supplies in the world market are originating from China due to their very low cost structure. Each and every country in the world has accepted this fact and also reconciled to the point that the China is the most efficient producer of this item in the world. Under these circumstances, it is a must for any domestic producers to be cost competitive and compete with Chinese imports through manufacturing efficiencies. On the other hand curbing the Chinese Imports through extra duties will lead only to the protection of inefficient Indian producers which is entirely against WTO principles and hence the move by United Phosphorous and its sister concerns should be dismissed.

# (d) Red Phosphorus Manufacturers

- 4. Limitation.- The appellant further declares that the appeal is within the limitation as prescribed in section 22D of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).
- 5. Facts of the case and the details of the order against which appeal is filed:

## The facts of the case are given below:

(give here a concise statement of facts and grounds of appeal against the specified order in a chronological order, each paragraph containing as neatly as possible as separate issue, fact or otherwise)

- 6. Relief(s) sought.- In view of the facts mentioned in paragraph 5 above, the appellant prays for the following relief(s) (Specify below the relief(s) sought explained the grounds for relief(s) and the legal provisions, if any, relied upon).
- 7. Interim order, if prayed for.- Pending final decision of the appeal the appellant seeks issue of the following interim order:

  (Give here the nature of the interim order prayed for with reasons)
- 8. Matter not pending with any other court etc.- The appellant further declares that the matter regarding with this appeal has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal.
- 9. Particulars in respect of the fee paid in terms of rule 9 of these rules.-
  - (1) Amount of fees
  - (2) Name of the Bank on which Demand Draft is drawn
  - (3) Demand draft number
- 10. Details of Index.- An index containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.
- 11. List of enclosures.-

(Signature of the appellant/Authorised Representative)

## Verification

I,	son/daughter/wife of
(N	ame in block letters)
Sh	ri being the appellant/Authorised Representative of do hereby verify
(N	ame of the appellant)
	at the contents of para 1 to 11 are true to my personal knowledge and belief and that I have suppressed any material facts.
	Signature of the appellant/Authorised Representative
Pla	ace:
Da	te:
То	
Th	e Registrar

of their inability to control the increase in high cost of raw materials. They are getting Red Phosphorous regularly at competitive price because of the import of white phosphorous. If the Safeguard Duty is imposed, this will definitely increase the cost of White Phosphorous by Rs.50/- per Kg. and Red Phosphorous by more than Rs.60/- Kg. This increase (40%) will be too much and the handmade matches industry giving employment to lakhs of workers will be seriously affected. Imposition of safeguard duty will affect free flow of white Phosphorous and create artificial shortage and will help monopoly trade of White Phosphorous which will result in shortage of raw materials and as a sequel may lead to closure of match units.

There are certain others who have strongly supported imposition of Safeguard Duty suggesting that the existence of domestic Yellow Phosphorus industries is essential to ensure regular availability of Yellow Phosphorus, which is the basic raw material for Red Phosphorus, which in turn is the major component for the manufacture of safety matches. Maximum encouragement should be given to domestic purchase of yellow phosphorus so that over dependence on imports of White /Yellow Phosphorus is considerably reduced and this may also result in considerable saving of foreign exchange.

- (b) Pesticides Association of India, New Delhi.
- (i) The Association represents over 90 companies whose combined turnover exceeds 90% of agrochemicals turn over in India. They include manufacturers of Pesticide intermediates, pesticide technical and formulations. The Association is also represented by several importers and distributors belonging to small scale, medium scale and large scale; both Indian and multinational. The Board of Directors of the Association discussed the issue of Safeguard Duty on Yellow Phosphorus on 8th October 1999 and it was decided to oppose any Safeguard Duty on Yellow Phosphorus, since it is against the larger interest of the Indian Pesticides industry involved in the manufacture of all downstream products beginning with Yellow Phosphorus.
- (ii) The production of Yellow Phosphorus in India can never be made internationally competitive in view of intrinsic infra-structural weaknesses, in the form of high cost of electricity and poor quality of Rock Phosphate. They fail to see any possibility of the Indian Phosphorus Industries to make positive adjustment in the near future.

# (c) Indian Crop Protection Association

In addition to the above, Indian Crop Protection Association, Mumbai have stated that the imposition of Safeguard Duty could lead to import ot 'technical pesticides' and as a sequel lead to more under utilisation of the domestic plant capacities.

(d) Indian Chemical Manufacturers Association (ICMA)

\*

大

⋠`

They have stated that the Trade & Business Development Expert Committee of ICMA invited both producers and consumers of Phosphorus on 13th October 1999 at its Western Regional Office to understand view of consumers and producers of White/Yellow Phosphorus. It transpired during the discussions with the consumers that:

- (i) The total demand of Phosphorus is around 15,000-17,000 MTs of Phosphorus and growth in demand is @ 20% per annum, almost all of it being for agrochemicals. Cost of Phosphorus constitutes anywhere between 25% to 60% of cost of production of pesticide intermediates.
- (ii) In case safeguard duty is applied, cost of manufacturing of intermediates would go up and products such as TMP and DETCL would start getting imported closing down the indigenous production. Search Chem Industries Ltd.(SCIL) have never sold any quantity to the other consumers. The imposition of safeguard duty would give all the other consumers a cost disadvantage vis-a-vis UPL who also manufactures pesticides intermediates from Phosphorus.
- (iii) Search Chem's present capacities would hardly go to meet their captive requirements and rest of the consumers would continue to import all the quantity required by them.

Further it transpired during discussions with the producers of Phosphorus (United Phosphorus Ltd. and Search Chem Industries Ltd.), that

- (iv) The cost of power constitutes 70% of the cost of Phosphorus. All the Phosphorus produced out of bought out power has been non-remunerative and hence, Excel Industries Ltd. and Star Chemical (Bombay) Ltd. have closed down their facilities of 4,000 tons and 1,500 tons each. Search Chem Industries Ltd. can with assured availability of power more economically, produce Phosphorus at competitive rates.
- (v) While with the present capacity of 2,500 tons, Search Chem Industries Ltd. would be consuming the quantity for itself, they would be able to produce additional 3,000 tons for the industry. Based on the present cost, Search Chem Industries Ltd. confirmed that its cost of production justifies Phosphorus price of Rs.115/- per Kg. with additional production as above, it may at best go down to Rs.75/- per Kg. largely due to the improved load factor of the captive power plant. The present price of imported Yellow Phosphorus was Rs.59/- per Kg.
- (vi) The Association has requested Director General (Safeguard) to take a pragmatic decision for imposition of safeguard duty on White /Yellow Phosphorus keeping in view the above points.

#### (e) CII, Ahmedabad

White/Yellow Phosphorus is an essential building block of wide range of pesticide finding application in the agricultural sector and is also an essential requirement for the defence sector. It is necessary for India to be self sufficient in

Yellow Phosphorus keeping in view its strategic importance for the core sectors namely, Agriculture and Defence. Its shortage for any reason whatsoever would be detrimental to growth of sectors which contribute major part of GDP and provide employment to a vast population.

# F. <u>VIEWS OF SUPPLIERS OF RAW MATERIALS/INPUTS TO THE</u> DOMESTIC MANUFACTURERS

#### 13.(a) Coke Suppliers

They have supplied in the past lot of quantity of metallurgical coke to all the White/Yellow Phosphorous manufacturers in India such as United Phosphorous Ltd., Excel Industries Ltd., Star Chemicals, PACT etc. Since this industry was one of their major and consistent buyer Industry, their supplies and business were affected very severly since last 3 years when they stopped their White/Yellow Phosphorous production. A boost should be given to indigenous industry by imposition of safeguard duty on import of White/Yellow Phosphorous into India and they fully support the application made in this regards by M/s. Search Chem Industries Ltd./ United Phosphorus Ltd..

- (b) The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd., Bhopal.
- (i) They had been supplying in the past bulk quantities of Rock Phosphate Chips from their mines to all the domestic White/Yellow Phosphorus manufacturers. The phosphorus industry had been their bulk and regular consumer till the units closed down due to cheap imports of White/Yellow Phosphorus into India, some time in the end of 1996. This affected their business and mining operations which had almost stopped except for very small requirement for other minor industries. They are in a position to supply 40000-50000MT of Rock Phosphate to the domestic industry and this would be possible only if the White Yellow Phosphorus is produced in India. They support the applicants for imposition of SGD which will give a boost to the Indian Rock Phosphate mining industry and employment opportunity in backward areas.

#### (c) Sabar Mineral

They were the main suppliers of Silica Gravel to Phosphorus Industry till 1996. Due to the closure of Phosphorus plants their work has stopped and they had to incur heavy losses. They have expressed their desire for revival of the Phosphorus Industry in India to enable them start their quarry and create employment for labour from backward areas.

# G FINDINGS

14. I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers, users, importers, exporters, exporting countries and various associations etc. Submissions made by various parties and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places in the findings below:

\*

⋠

### 15. Product under Investigation

The product under investigation is White/Yellow Phosphorus. White/Yellow Phosphorus is an inorganic chemical with chemical formula P<sub>4</sub>. The process for the manufacture of White /Yellow Phosphorus involves conversion of Rock Phosphate in the presence of Silica and Coke in electric furnace. White/Yellow Phosphorus is colourless or white, transparent, crystal, having waxy appearance and darkens on exposure to light. It is volatile, sublimes in vacuum at ordinary temperature when exposed to light. When exposed to air in the dark it emits a greenish light and gives off white fumes White/Yellow Phosphorus is used in the production of intermediates like Phosphorus Trichloride, Red Phosphorus, Phosphorus Pentasulphide, Aluminum Phosphide and Zinc Phosphide It is a building block for various agro-chemicals which are extensively applied in the agricultural sector besides finding applications in defence needs.

White/Yellow Phosphorus is classified under Sub-heading 2804 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and under 28047003 of the Indian Trade Classification based on the Harmonised Commodity Description (ITC). This classification of White/Yellow Phosphorus under Customs Tariff Act, 1975 and the ITC has been indicated for the purpose of convenience and in no way restricts the scope of the coverage of the product under investigation.

Any reference to White and/or Yellow Phosphorus in these findings should be understood to include White/Yellow Phosphorus as described above.

# 16. <u>Domestic Industry</u>

There are five companies in India who created capacity for production of Yellow Phosphorus namely UPL, Mumbai; PACT, Cochin, Excel Industries Limited, Mumbai, Star Chemicals Ltd., Mumbai; and SCIL, Mumbai The Application for imposition of safeguard duty has been filed by PACT and supported by UPL who have transferred their plant and capacity to SCIL. Excel and Star have opposed the petition and they are against the imposition of any safeguard duty on White/Yellow Phosphorus.

In the present case, during the period from 1994-95 to 1998-99, the production of the five companies who created capacity for production of Yellow Phosphorus was as under.

<u>Table 1</u> <u>Production of domestic industry (MT)</u>

Company	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	Total
UPL	2081	2973	1772	-	_	6826
SCIL	-	-	-	<u>-</u>	-	-
PACT	800	911	393	465	612	3181
Excel	1469	1800	1400	-	-	4669
Star	400	-	-	-	-	400
Total	4750	5684	3565	465	612	15076

Table 2 below gives the figures of production capacity of the five companies.

<u>Table 2</u>					
Production Capacities of domestic industry	(MT)				

Company	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
UPL	4500	5000	5000	5000	-
SCIL	-		-	-	5000
PACT	1000	1000	1000	1000	1000
Star	1800	1800	-	-	-
Excel	2500	2500	4000	4000	4000
Total	9800	10300	10000	10000	10000

It has been argued that SCIL have started producing Yellow Phosphorus only from 14.6.1999 and, have no past history of manufacturing Yellow Phosphorus. SCIL, therefore, have no *locus standi* in this matter. Similarly, the co-petitioner UPL by virtue of the fact that they have already discontinued with the production of Phosphorus in September, 1996, also have no *locus standi* in the matter. PACT also are alleged to hardly have any *locus standi* in the matter owing to their small production capacity

It is seen from Table-1 above that during 1994-99, the domestic industry produced a total of 15076 MT of Yellow Phosphorus. Out of 15076 MT, the Applicants (including UPL) accounted for 10007 MT and Star together with Excel accounted for the rest 5069 MT. During the last two years viz. 1997-98 and 1998-99, PACT alone produced 465 MT and 612 MT respectively of Yellow Phosphorus. The Applicants, thus, not only accounted for the entire production during 1997-99 but also accounted for the major proportion of the domestic production during the period 1994-99.

Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 defines 'domestic industry' to mean the producers –

- (a) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
- (b) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.

As discussed above, the Applicants not only produced the entire quantity of Yellow Phosphorus during 1997-99 but also accounted for the major proportion of the domestic production during the period 1994-99. The application is, therefore, considered to have been made by the domestic industry producing Yellow Phosphorus.

# 17. <u>Increased Imports:</u>

The White/Yellow Phosphorus is imported into India from Bulgaria, China, Chinese Taipei (Taiwan), Hong Kong, Germany, Japan, Korea DPR, the Netherlands, UK and USA.

⊀

Yellow Phosphorus attracted Customs duty of 50% ad-valorem in 1994-95 and 1995-96, which was reduced to 30% in 1996-97 and to 35% in 1997-98 and 1998-99. Currently, Yellow Phosphorus attracts Customs duty @ 35% + 10% ( of 35%).

The Applicants claimed imports of 5350 MT of Yellow Phosphorus in 1994-95, 7493 MT in 1995-96, 8829 MT in 1996-97, 12391 MT in 1997-98 and 16504 MT in 1998-99. While the import figures of Yellow Phosphorus for the period 1994-98 are supported by the DGCIS data, for the year 1998-99, DGCIS data is not yet available. The Applicants themselves, however, have disputed the import data provided by them in the application for the year 1998-99 and have stated that the information provided earlier by them was on the basis of estimated imports in the absence of factual information. They have now received import figures from the DGCIS for the year 1998-99 which is 12388 MT. They have, however, further stated that they have collected the data with regard to imports of Yellow Phosphorus from the information provided by various parties, on the basis of which the total imports made by various importers/users work out to 13380 MT.

The import data, however, was subjected to verification. Form the import details available with the importers subjected to verification, it has been revealed that these importers alone account for 14086.513 MT of Yellow Phosphorus in 1998-99. The total imports were, therefore, a minimum of 14086.513 MT. Taking this to be the imports in 1998-99 the domestic production and imports of Yellow Phosphorus during the period 1994-99 were as given in Table 3 below.

Table 3
Increased imports

Year	Domestic Production (MT)	Imports (MT)	Imports as % age of Domestic Production
1994-95	4750	5350	112.6
1995-96	5684	7493	131.8
1996-97	3565	8829	247.7
1997-98	465	12391	2264.7
1998-99	612	14086.5	2301.7

From the data tabulated above, it is observed that the imports which were 5350 MT in 1994-95 increased to 14086.5 MT in 1998-99 i.e. the imports increased to 263.3% of 1994-95 imports. The imports as compared to domestic production increased from 112.6% in 1994-95 to 2301.7% in 1998-99. The imports in comparitive term increased by 2189.1 percentage points or to more than 20 times in a span of five years.

It is, thus, evident that the imports have increased both in absolute terms as well as compared to domestic production.

#### 18. Serious Injury:

The domestic industry produced 4750 MT of Yellow Phosphorus in 1994-95, which increased to 5684 MT in 1995-96 but declined rapidly thereafter to 3565 MT in 1996-97, 465 MT in 1997-98 and to 612 MT in 1998-99. The first unit to stop producing Yellow Phosphorus was Star Chemicals who stopped production from 1995-96 onwards.

UPL and Excel Industries stopped production in 1996-97. Only PACT continued with its production in 1997-98 and 1998-99 but they produced only small quantities of 465 MT and 612 MT respectively during these years. The apparent domestic consumption (domestic sales including captive consumption + imports) during this period was 10656.48 MT in 1994-95, 12938.13 MT in 1995-96, 12671.799 MT in 1996-97, 12861.94 MT in 1997-98 and 14737.276 MT in 1998-99 (see Table 4 below).

<u>Table 4</u>
<b>Apparent Domestic Consumption</b>

Year	Sales including Captive	Imports (MT)	Apparent Domestic	
	Consumption (MT)		Consumption (MT)	
1994-95	5306.48	5350	10656.48	
1995-96 5445.13		7493	12938.13	
1996-97 3842.79		8829	12671.79	
1997-98 470.945		12391	12861.94	
1998-99 650.776		14086.5	14737.276	

The domestic producers thus, suffered a severe loss in production and capacity utilisation which declined from a high of 55.18% in 1995-96 to a low of 4.65% in 1997-98 and 6.12% in 1998-99. The market share of the domestic producers in the apparent consumption also declined from about 42% in 1995-96 to a mere 4.4% in 1998-99.

It has been argued that SCIL cannot claim to have suffered serious injury as they do not have any past history of production and UPL have no *locus standi* as they have shifted/transferred their plant to SCIL and have no production facility for Yellow Phosphorus now. It has also been argued that SCIL is a new unit and safeguard duty cannot be imposed for the protection of a new unit. These arguments, however, are untenable as for the purpose of imposition of safeguard duty, the serious injury caused to the 'domestic industry' as defined under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 i.e. domestic producers as a whole, or those who account for a major proportion of the domestic production is to be considered. It is irrelevant whether some of the domestic producers may have already existing plants or some of them may have set up new units.

Serious injury to the domestic industry producing White/Yellow Phosphorus is, therefore, evident.

#### 19. Cause of Injury

While the domestic industry has suffered serious injury and they have alleged the injury to have been caused by the cheaper imports, some others have argued that the injury to the domestic producers of Yellow Phosphorus has been caused due to increase in the cost of production of Yellow Phosphorus resulting from the increased cost of power. It has been argued that Yellow Phosphorus is a power intensive product and power constitutes about 50% of the cost of production of Yellow Phosphorus with other variable costs accounting for another 30-35%. The per unit cost of power in case of UPL has increased from \*\*\*(confidential) in 1994-95 to \*\*\*(confidential) in 1998-99 which has rendered the domestic production of Yellow Phosphorus unviable as about 14,000 kWh (or units) are required for the production of 1 MT of Yellow Phosphorus.

1

While this may be true that the domestic producers of Yellow Phosphorus have become uncompetitive on account of very high variable costs, mainly due to higher power costs, the fact remains that it is the cheaper imports which have taken away the market share of the domestic producers and forced them to shut down their production facilities.

During the period 1994-95, the imports into India increased from 5350 MT in 1994-95 to 14086.5 MT in 1998-99 at landed prices which on an average were much below the domestic prices as indicated in Table 5 below.

Year **Imports** Average Average Domestic Sales Average CIF price Landed (MT) (including Sale prices Rs./kg price Rs./kg captive Rs./kg consumption (MT) 1994-95 5350 36.68 55.02 5306.48 73.52 1995-96 45.35 7493 68.03 5445.13 76.45 1996-97 8829 56.74 73.76 3842.79 99.60 1997-98 12391 48.47 65.43 470.945 83.83 1998-99 14086.5 47.52 64.15 650.776 75.58

Table 5

The petitioners have provided the information regarding cost of production for UPL in the petition who were the major producers during the period 1994-97. It is observed therefrom that the cost of production of Yellow Phosphorus for UPL was much higher than their selling price and still higher than the landed price of the imported Yellow Phosphorus. The domestic producers were forced to reduce their selling price below the cost of production in the face of competition from cheaper imports.

It has been argued by some of the parties that imports of Yellow Phosphorus into India were necessitated to meet with the domestic requirements as the domestic producers of Yellow Phosphorus did not cater to the domestic demand, and produced Yellow Phosphorus mainly for their own captive requirements. In this regard, it is observed that during the period 1994-99, the total domestic production of Yellow Phosphorus was 15076 MT and the imports were 48150 MT. The apparent domestic consumption during this period was 10656 MTpa in 1994-95, which gradually increased to 14737.276 MTpa in 1998-99. Various parties have given different figures for the domestic demand of Yellow Phosphorus, varying between 13000 MTpa and 17000 MTpa. It is, however, observed that during 1995-96 to 1997-98, the apparent consumption of Yellow Phosphorus was of the order of 12800 MTpa. The imports during 1998-99, as verified were 14086.5 MT and domestic production in 1998-99 was 612 MT. The apparent consumption in 1998-99 of the order of 14737.276 MTpa is considered to be the reflective of the domestic demand during 1998-99.

Almost entirely the domestic demand was being met by the imports as the domestic producers except PACT stopped production of Yellow Phosphorus in 1996-97 PACT also produced only small quantities of 465 MT and 612 MT during 1997-98 and

1998-99 respectively. It is also observed that out of 10007 MT of Yellow Phosphorus produced by the Applicants during 1994-99, UPL accounted for 6826 MT out of which they consumed 6474 MT captively in the manufacture of Phosphorus derivatives and sold only 352 MT in the merchant market. A major portion of Yellow Phosphorus into India was imported by the domestic producers themselves, obviously for their captive requirements. Table 6 below gives the import figures of UPL/SCIL, Star and Excel.

<u>Table 6</u> <u>Imports by domestic producers (MT)</u>

		Imports by			
Year	Star	Excel	UPL/SCIL	Total of (2),(3) & (4)	Total imports
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1996-97	1510	2042	2918	6470	8829
1997-98	1566	3380	4260	9206	12391
1998-99	900	4939	4665	10504	14086.5

From the above, it is observed that while it is true that the domestic producers did not meet with the domestic requirement and the imports were necessitated to fill the supply-demand gap, it is also true that the cheaper imports caused the shut-down of most of the domestic production facilities.

The serious injury to the 'domestic industry' was, therefore, caused by the increased imports.

### 20. Adjustment Plan

The Applicants have stated that UPL/SCIL are making efforts to reduce the cost of production by resorting to use of captive power, optimising plant utilisation and increasing the capacity of the plant by 5000 MT by adding another furnace to achieve economies of scale. They expect to achieve substantial cost savings to the company through these efforts. The expansion of capacity from 5000 MT to 10000 MT will take about three years. From this expansion, they not only expect to achieve economies of scale but also improvement in consumption efficiencies for the raw materials (power, rock phosphate, coke) and distribution of fixed costs over larger volumes. Power being the major cost factor in the production of Yellow Phosphorus, SCIL expects to reduce the cost of generation of power by enhancing the load factor of Power Plant to optimal level. SCIL is also proposing to convert the Power Plant fuel from Liquid Naphtha to Natural Gas, which will augment the efficiency of the Power Plant and overall cost competitiveness for Yellow Phosphorus.

PACT is modifying their furnace at a cost of Rs. 80 lakh, which would increase the efficiency of the furnace both in terms of production as well as cost. This modification is expected to increase the plant capacity by about 30%. They have also entered into a preliminary agreement with the Kerala State Electricity Board (KSEB) to commission a 4 MW mini hydel power plant. They have submitted the Techno Economic Feasibility Report to the KSEB. The project when implemented will ensure relief not

4

only in terms of continuous power supply to the Yellow Phosphorus plant, but also availability of power at much cheaper rates.

In the context of re-adjustment by the petitioners, it is observed that SCIL were manufacturing caustic soda, which also is a power intensive product. They had set up a 50 MW power plant at an investment of Rs. 100 crores. SCIL expected that the surplus power from this captive power plant, after supplying to its own caustic soda plant could be wheeled to UPL for their Yellow Phosphorus production, thus making power at low cost available across the company. However, in view of constraints faced by them in transferring power from SCIL to UPL, UPL decided to transfer their Yellow Phosphorus plant to SCIL, thus making it possible to use the surplus power for the production of Yellow Phosphorus.

#### 21. Public Interest

The domestic producers of Yellow Phosphorus have suffered serious injury caused by the increased imports of Yellow Phosphorus. They are also making efforts to readjust. However, it needs to be examined whether or not imposition of safeguard duty on Yellow Phosphorus would be in the Public interest

In this regard, it is observed that the domestic demand of Yellow Phosphorus was about 14700 MTpa. The domestic producers had a total installed capacity of 9800 MTpa in 1994-95, which increased to 10300 Mtpa in 1995-96 but declined to 10000 MTpa thereafter. The production of the domestic producers registered a maximum of 5684 MT in 1995-96 and declined to 3565 MT in 1996-97, 465 MT in 1997-98 and to 612 MT in 1998-99. The domestic producers, therefore, did not cater to the domestic requirement of Yellow Phosphorus, which was almost entirely met by imports. The Applicants have submitted that they have 5000 MTpa capacity of Yellow Phosphorus, 1000 MT with PACT and 4000 MT with SCIL which was installed by transferring the UPL Yellow Phosphorus plant to SCIL. SCIL have further plans to increase this capacity by another 5000 MTpa in the next 3 years PACT have a capacity of 1000 MTpa installed with them which they plan to enhance to 1300 MT. The Applicants, thus plan to have a capacity of 11300 MTpa of Yellow Phosphorus in the next 3 years.

It is important to note here that against the demand of about 14700 Mtpa, the capacity available with the domestic industry to produce Yellow Phosphorus was only 5000 MTpa of the applicant companies as the other two companies namely Excel and Star have categorically denied any intention to recommence Yellow Phosphorus production. The Applicants have argued that Excel have not yet dismantled their plant and, therefore, if their capacity is not taken into account, their requirement of Yellow Phosphorus also should not be considered while determining the domestic demand.

This argument, however, is not tenable as all the domestic producers except PACT had stopped production of Yellow Phosphorus during the last two years i.e. 1997-98 and 1998-99. Excel have the right to decide whether they intend to re-commence the production or not. The capacity of Yellow Phosphorus installed by Excel in no way has had any effect on UPL/SCIL's production or had prejudiced their position in any other manner, specially as UPL/SCIL consumed their Yellow Phosphorus production almost entirely for captive requirements and hardly sold any material in the domestic market. In

\*

this context, it is also important to note that SCIL in the Prospectus issued for their Public issue in 1996 have specifically stated that they shall give preference to the requirements of UPL amongst all their buyers and as far as possible, make all reasonable efforts to meet the requirement of UPL first in case if they were unable to supply full quantities to all their buyers at any point of time. In the backdrop of these facts, and keeping in mind that SCIL are committed to first make available Yellow Phosphorus for the captive requirement of UPL, it is difficult to believe that the Applicants can meet with the domestic merchant requirements to any significant extent. Imposition of safeguard duty on imports of Yellow Phosphorus would thus severely affect the interests of the majority of the domestic consumers of Yellow Phosphorus who meet their requirements through imports.

It is important to note that UPL/SCIL are themselves producers of Phosphorus derivatives and they compete with other producers of Phosphorus derivatives. These producers of Phosphorus derivatives have been using imported Yellow Phosphorus. UPL/SCIL intend to produce Yellow Phosphorus for their captive requirements but their cost of production of Yellow Phosphorus is higher as compared to imported Yellow They, therefore, cannot compete with other producers of Phosphorus derivatives, if they use their own Yellow Phosphorus. Imposition of safeguard duty on Yellow Phosphorus will bring the landed price of imported Yellow Phosphorus at a level comparable to indigenous Yellow Phosphorus which will enable UPL/SCIL to compete in the domestic merchant market of Phosphorus derivatives. Thus, imposition Safeguard Duty is likely to benefit the Applicants alone as it will give them an advantage over other users/importers of Yellow Phosphorus who compete with the Applicants in the production of Phosphorus derivatives. The Applicants in this context have also argued that manufacture of pesticide intermediates have substantial margins and can absorb the increase in prices of Yellow Phosphorus as a result of imposition of safeguard duty. It is observed that this argument equally applies to the Applicants. Since the Applicants themselves produce Phosphorus derivatives like pesticide intermediates etc., they should also be availing of similar margins and should be able to absorb some increase in the cost of Yellow Phosphorus in case they decide to produce Yellow Phosphorus themselves and captively consume the same. If they wish others to bear the additional cost, they should themselves be prepared to do so, specially as admittedly they have some margins in the production of Phosphorus derivatives. Their demand for imposition of safeguard duty appears to have been made to ensure that others who manufacture Phosphorus derivatives do not have Yellow Phosphorus available to them at prices below which they transfer Yellow Phosphorus for their captive consumption i.e. below their cost of production.

In this context, it is also important to observe that UPL/SCIL have themselves stated that ".....we have imported Yellow Phosphorus for our export goods, it has helped us in maintaining our competitiveness and we could increase our exports at most competitive prices. Further, during the period of suspension, imports of Yellow Phosphorus for our captive consumption has fetched the company better profitability in the downstream items, which was not available in case the company as a whole is considered when we were consuming our own Yellow Phosphorus". It was, therefore, admittedly profitable for them to use imported Yellow Phosphorus. That being so, it is not understood as to why UPL/SCIL have requested for imposition of safeguard duty on imports of Yellow Phosphorus. UPL/SCIL, however, have explained that they have requested for imposition of safeguard duty to prevent the domestic industry from a

. 4

complete wipe out. According to them, the exporters have been waiting for such an opportunity as once the domestic industry is completely wiped out then they may charge whatever price they wish. According to them, the exporters did not increase the prices of Yellow Phosphorus as they knew that if they increased the prices, the domestic producers can re-commence production of Yellow Phosphorus.

In this context various arguments have been made by different parties. One of the arguments is to consider the benefit flowing from the decision to maintain the plant in running condition but without actually producing Yellow Phosphorus. According to the estimates of Excel, a Yellow Phosphorus plant of a capacity of 5000 MTpa would cost about Rs. 10 crores. The costs in the form of interest @ 15% per annum and depreciation @ 10% per annum would be about Rs. 2.5 crores and with other estimated cost of Rs. 50 lakh, the total cost of keeping the capacity idle would be in the range of Rs. 3 crores per annum. As against this, the saving resulting from the lower cost of imported Yellow Phosphorus @ Rs. 50 per kg (the amount of safeguard duty requested by the petitioners) for 5000 MT for use in the manufacture of Phosphorus derivatives will be Rs. 5000 X 50000 i.e. about Rs. 25 crores. It is, thus obvious that by spending a small portion of the saving so achieved, both the objectives could be met with.

It is also observed from the data furnished by UPL/SCIL that with all the proposed efforts to be made by them in reducing the cost of power and achieving higher production efficiencies, they may not be cost-competitive as compared to the imported Yellow Phosphorus, even after three years, the period for which imposition of safeguard duty has been requested. The major effort of UPL/SCIL is in improving the cost of power. They intend to reduce the cost of power in 3 years time from \*\*\* per unit to about \*\*\*(confidential) per unit. However, PACT who were getting power from the Kerala State Electricity Board at about Rs. 2.50 per unit which is much lower as compared to the cost of power to UPL/SCIL, are not able to produce Yellow Phosphorus at competitive prices. In fact due to higher cost of production they have stopped production of Yellow Phosphorus. It is, therefore, difficult to appreciate that even after three years indigenous Yellow Phosphorus can be made available to the domestic users/consumers at competitive prices.

An argument has been made that duty free imports of Yellow Phosphorus would not be affected by imposition of safeguard duty. In this regard, it is observed that duty free imports of Yellow Phosphorus fall in two categories. One those imported against Advance Licenses and meant for use in export production, and the other those imported under DEPB Scheme. So far as imports against Advance Licenses are concerned, it can be considered that imposition of safeguard duty may not have impact on such imports, as generally the Government has been exempting these imports from imposition of safeguard duty. DEPB imports are not at the same footing as DEEC imports. Under the DEPB Scheme the imports attract all duties but to the extent duty is debited through DEPB credit, the imports are not charged to duty. Imports under DEPB Scheme are, therefore, subject to payment of safeguard duty, if levied.

During 1998-99, as verified, 7143.028 MT of Yellow Phosphorus was imported under DEEC (Advance Licenses) and DEPB Schemes, out of which only 2245.926 MT was imported under DEEC Scheme. Excluding the DEEC imports from the total imports of 14086.5 MT will still leave a quantity of about 11841 MT, which if subjected to

imposition of safeguard duty @ Rs. 50 per kg as requested by the petitioners, would result in a burden of about Rs. 60 crores on the user industry.

Considering the facts that the domestic producers of Yellow Phosphorus produced only very small quantities in 1997-98 and 1998-99; the installed capacity of the Applicants is only 5000 MT which accounts for a small fraction of the domestic demand with maximum production ever achieved still less and most of which was used for captive consumption; UPL/SCIL compete with the users/importers of Yellow Phosphorus in producing Phosphorus derivatives admittedly with adequate margins; UPL/SCIL have themselves benefited from the use of imported Yellow Phosphorus; the cost of keeping the plant idle is only a fraction of the benefit likely to be achieved by use of imported material; and that even after making the adjustment UPL/SCIL may not be cost-competitive as compared to the imported Yellow Phosphorus, imposition of Safeguard Duty does not appear to be in public interest.

### 22. Conclusion and Recommendations

The domestic producers of White/Yellow Phosphorus have suffered serious injury caused by the increased imports of White/Yellow Phosphorus. It is, however, not in the public interest to impose Safeguard Duty on imports of White/Yellow Phosphorus. No recommendation to impose Safeguard Duty on White/Yellow Phosphorus imported into India is, therefore, made.

[No SG/INV/2/99]

R.K. GUPTA, Director General

\*\* ,